GOVERNMENT BILLS—*Contd.*

The National Commission for Minority Educational Institutions Bill, 2004

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): Sir, I beg to move:

> "That the Bill to constitute a National Commission for Minority Educational Institutions and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

SHRI P.G. NARAYANAN (Tamil Nadu): What is the reaction of the Government?

श्री सभापति: नहीं, इमीडिएट रिएक्शन नहीं दिया जा सकता।...*(Interruptions)* Don't expect immediate reaction from the Government. Wait for it. *(Interruptions)*

There is one amendment by Shrimati Sushma Swaraj for reference of the National Commission for Minority Educational Institutions Bill, 2004 to a Select Committee of the Rajya Sabha. She may move the amendment at this stage.

श्रीमती सुषमा स्वराज (उत्तरांचल): सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से इस बिल में यह संशोधन प्रस्तुत कर रही हूं—

> "That the Bill to constitute a National Commission for Minority Educational Institutions and to provide for matter connected therewith or incidental therewith, as passed by the Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of the following ten Members with instruction to report by the 1st day of the next Session of the Rajya Sabha,
>
> 1. Dr. Murli Manohar Joshi
>
> 2. Maulana Obaidullah Khan Azmi
>
> 3. Dr. P.C. Alexander
>
> 4. Smt. Chandra Kala Pandey

5. Shri Tarlochan Singh
6. Shri Sanjay Nirupam
7. Shri C. Ramachandraiah
8. Shri Tariq Anwar
9. Shri P.G. Narayanan, and
10. Shri Uday Pratap Singh."

सभापति जी, हमारे देश में कानून बनाने के जो तरीके संविधान में लिखे गए हैं, उनमें से एक तरीका अध्यादेशों के माध्यम से कानून बनाने का भी है और वह तरीका भी संविधान-सम्मत है। विभिन्न समयों पर विभिन्न सरकारों ने इस माध्यम का उपयोग करके कानून बनाए हैं, लेकिन जो संविधान अध्यादेश बनाने की इजाजत देता है, वह यह भी पाबंदी लगाता है सरकार पर, कि जब संसद सत्र में न हो...

[श्री उपसभापति पीठासीन हुए।]

उपसभापति जी, मैं अपनी बात को जारी रखते हुए कहना चाहती हूं कि जो संविधान यह इजाजत देता है कि अध्यादेश के जरिए कानून बन सके, वही संविधान यह पाबंदी भी लगाता है कि जब संसद सत्र में न हो और बहुत ज्यादा जरूरी हो, तब अध्यादेश का रास्ता अपनाया जाए, लेकिन इसको एक रूट का तरीका न बना दिया जाए। संसद सत्र में नहीं था, जिस समय यह अध्यादेश आया। लेकिन, ऐसी क्या आवश्यकता थी, क्या ऐसी जरूरत थी कि जो सही रास्ता है, जो रूटीन रास्ता है विधेयकों को लाने का, उसको छोड़ा गया? जब से हमारी स्टेंडिंग कमेटियां बन गई हैं, तब से यह रास्ता बना है कि बिल जिस समय संसद में प्रस्तुत किया जाता है, यदि वह राज्य सभा की कमेटी के नीचे आता है तो राज्य सभा के सभापति, और यदि वह लोक सभा की कमेटी के नीचे आता है तो लोक सभा के अध्यक्ष, उस बिल को संबंधित स्टेंडिंग कमेटी को, स्थाई समिति को भेज देते हैं और वहां उस बिल पर चर्चा होती है, जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर होती है। अगर कमेटी के सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या यह बिल किसी वर्ग-विशेष को प्रभावित करने वाला है तो उन वर्गों के लोगों को बुलाकर चर्चा होती है और बहुत विस्तृत चर्चा के बाद स्थाई समिति अपनी अनुशंसा, अपनी सिफारिश देती है। फिर उस सिफारिश के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टरी, प्रशासनिक मंत्रालय, संबंधित मिनिस्टरी अपना मत बनाती है, जिसके बाद उस बिल को कैबिनेट में ले जाते हैं और फिर वह बिल स्थाई समिति की अनुशंसा के साथ, संशोधित या गैर-संशोधित, संसद में आता है और उसके ऊपर सारे सदस्य चर्चा करने के बाद उसको पारित करते हैं।

उपसभापति जी, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि यह रूट क्यों नहीं अपनाया गया? इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजने में दिक्कत क्या थी? आप यह बिल प्रस्तुत कर देते, अगर बहुत जल्दी थी तो पिछली बार इसे प्रस्तुत कर देते और कह देते कि इस सत्र से पहले स्टैंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट जरूर दे दे। चूंकि आप आर्डिनेन्स रूट से आए, इसलिए आप यह तरीका लेकर बैठ गए कि आर्डिनेन्स से आए हुए बिल के लिए जरूरी नहीं है कि स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए। उसके बावजूद लोक सभा अध्यक्ष इसको भेज सकते थे, लेकिन वहां यह बिल स्टैंडिंग कमेटी को नहीं गया और इसलिए हमारे हाथ बंध गए हैं कि हम इसको स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भिजवा सकते क्योंकि यह भी नियमों में प्रावधान है कि जब एक सदन बिल को पारित कर दे तो वह स्टैंडिंग कमेटी को नहीं दिया जा सकता। क्योंकि उस सदन के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य इसके पक्ष में वोट कर चुके हैं, इसलिए मैं अब इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की सिफारिश नहीं कर सकती, लेकिन तब भी नियम को बनाने वालों ने यह प्रावधान किया कि अगर कोई बिल एक सदन से पारित हो जाए तो वह स्टैंडिंग कमेटी में तो नहीं जा सकता, मगर दूसरा सदन अपने यहां की सलेक्ट कमेटी में उसको भेज सकता है। इसीलिए, उपसभापति जी, मैं यह संशोधन लेकर आई हूं और इसमें मैंने जो 10 नाम दिए हैं, आपने देखे होंगे, वे 10 नाम सभी राजनीतिक दलों से लिए हुए हैं। नामों को लेते हुए मैंने यह ध्यान रखा कि माइनॉरिटीज़ के लोग लिए जाएं। मैंने उसमें 2 अल्पसंख्यक रखे हैं मुस्लिम समुदाय से मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी और श्री तारिक अनवर साहब, एक कांग्रेस से हैं, एक एन॰सी॰पी॰ से हैं। मैंने उसमें एक क्रिश्चियन धर्म से भी रखे हैं-डा॰ पी॰ सी॰ अलेक्जेन्डर। ...(व्यवधान)...

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (Kerala): Sir, what is this? *(Interruptions)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैंने उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के सिख समुदाय से भी रखे हैं- श्री तरलोचन सिंह और वे इस समय माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी हैं।...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. *(Interruptions)* Please sit down.

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभापति जी,...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. Let me hear one by one. *(Interruptions)* If all of you speak at once, how can I hear? *(Interruptions)* Please sit down. *(Interruptions)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभापति जी, मैंने यह बात कही थी ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. Let me listen. *(Interruptions)* I will give you time. *(Interruptions)* Please sit down. *(Interruptions)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभापति जी, मैंने अपनी बात कहते हुए यह बात कही थी ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: एक मिनट। What is your objection, Mr. Premachandran? *(Interruptions)*

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, my point is, she is referring to the persons who are proposed to be elected to the Select Committee; and the names are on the basis of religion. They are Members of Parliament. But according to this proposal...*(Interruptions)* That he belongs to the Muslim community...*(Interruptions)*

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: No, Sir, मुझे बोलने तो दीजिये। *(Interruptions)*

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Let me complete. My point is, what is the criteria? *(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are not allowing me to listen to Members. Let me listen. *(Interruptions)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, आप मुझे बोलने दें तो मैं अपनी बात पूरी करूं। ...**(व्यवधान)**...

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: What is the criteria for a Member getting elected to the Select Committee? Is it on the basis of religion? *(Interruptions)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभापति जी, जब बिल अल्पसंख्यक समुदाय के लिए लाया जा रहा है ...**(व्यवधान)**... उपसभापति जी ...**(व्यवधान)**...

SHRI SHAHID SIDDIQUI (Uttar Pradesh): We can't accept this, Sir. *(Interruptions)*

श्री संजय निरुपम (महाराष्ट्र): सर, इस कमीशन का चेयरमैन भी माइनॉरिटीज से, मैम्बर्स भी माइनॉरिटीज से। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Siddiqui, please sit down.

श्रीमती सुषमा स्वराज: अगर नहीं ऐक्सेप्ट, तो मेरा मोशन रिजेक्ट कर दीजिएगा। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is for me to regulate, you do not do it. *(Interruptions)*

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): This is a perfect example of pseudo-secularism. (*Interruptions)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभापति जी, अगर वे ऐक्सेप्ट नहीं करते तो ...(व्यवधान)...

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh) Sir, please allow me for a minute.... (*Interruptions)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, मेरी बात तो पूरी नहीं हुई।

श्री आनन्द शर्मा: अगर आप एक मिनट मुझे बोलने के लिए दें ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभापति जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई, बीच-बीच में बोले जा रहे हैं। when I am not yielding, how can you speak? (*Interruptions)*

श्री उपसभापति: आपको भी सुनूंगा।

श्री आनन्द शर्मा: ओ॰ के॰।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I can't direct the Member as to what she has to speak. But if there is anything unparliamentary in her saying, which is not according to the rules...(*Interruptions)* You will be given an opportunity. (*Interruptions)*

†**प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़** (जम्मू और कश्मीर): सर, आपने बात कह दी, हम भी कुछ कहें।

پروفیسر سیف الدین سوز : سر، آپ نے بات کہہ دی، ہم بھی کچھ کہیں۔

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How can I conduct the House if you go on interrupting? (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभापति जी, मेरे कुछ साथी कह रहे हैं कि हमें यह ऐक्सेप्टेबल नहीं है। मेरा मोशन जब वोट पर जाएगा तो वे इसे रिजेक्ट कर दें, लेकिन मुझे मेरी बात तो कहने दें। किस बात पर उन्हें एतराज है? उपसभापति जी, अगर माइनॉरिटी शब्द पर उन्हें एतराज़ है तो यह बिल ही माइनॉरिटीज़ के लिए है। ...(व्यवधान)... यह तो बिल ही माइनॉरिटीज के लिए है। ...(व्यवधान)...

श्री शाहिदी सिद्दिकी:*

---

†Transliteration of Urdu Script.
*Not recorded.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Shahid Siddiqui. please sit down. No, no...(*Interruptions*)...Nothing will go on record. Nothing will go on record. ...(*Interruptions*)... Mr. Shahid Siddiqui...(*Interruptions*)...No, no, this is not right. ...(*Interruptions*)...You know the rules. You cannot address the Member. Please address the Chair. If Members address like this, then how can I conduct the House? So, please address the Chair.

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभापति जी, मैंने तो नामों को लेते समय केवल यही ध्यान रखा है कि सब राजनैतिक दलों का प्रतिनिधित्व ज्यादा से ज्यादा आ जाए और यही ध्यान रख कर मैंने नाम लिए हैं। ...(**व्यवधान**)... मैं खत्म करने जा रही हूं। मैंने इसीलिए यह सोचा कि चूंकि अब यह बिल स्टेंडिग कमेटी को नहीं जा सकता तो कम से कम राज्य सभा की सलैक्ट कमेटी को जाए और सलैक्ट कमेटी बैठ कर इस बिल के तमाम प्रावधानों पर एक बार विस्तृत चर्चा कर लें। जिन वर्गों पर यह बिल प्रभावित होने वाला है, उन्हें भी इससे कुछ फायदा होगा, या नहीं होगा, उन्हें भी कुछ एतराज़ इस पर है या नहीं है, उसकी चर्चा करने का एक मंच सलैक्ट कमेटी उपस्थित कर सकती है, सलैक्ट कमेटी उनको मूव कर सकती है।

श्री उपसभापति: क्या आपने यहां से मोशन मूव किया है?

श्रीमती सुषमा स्वराज: इसलिए मेरा आपके माध्यम से, सदन से, निवेदन है कि यह बिल सलैक्ट कमेटी को जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we are taking up both the motions. We will give opportunity. Yes, Shri Saif-ud-din Soz.

श्रीमती सुषमा स्वराज: यह बिल राज्य सभा की सलैक्ट कमेटी को जाए और वहां पर इस पर चर्चा हो, तब यह बिल यहां पारित करने के लिए लाया जाए।

The questions were proposed

श्री उपसभापति: देखिए, मोशन मूव हुआ है, मिनिस्टर साहब ने मोशन मूव किया हैं। That motion is taken into consideration. Mrs. Sushma Swaraj has moved a motion. Now discussion will take place. One-by-one motion will be put to vote. That will be the procedure. Yes, Saif-ud-din Soz. ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय निरुपम: कौन से मोशन पर बोल रहे हैं आप? ...(**व्यवधान**)...

†**प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़:** भाई जान, आप बात तो सुनिए, मैं इतनी तमीज़ से बोल रहा हूं। आप बात तो सुनिए ...(**व्यवधान**)...

پروفیسر سیف الدین سوز : بھائی جان، آپ بات تو سنئے، میں اتنی تمیز سے بول رہا ہوں۔ آپ بات تو سنئے .....مداخلت.....

†Transliteration of Urdu Script.

श्री संजय निरुपम: तब मुझे भी अनुमति दी जानी चाहिए। We should also be allowed to speak on the motion moved by Mrs. Sushma Swaraj. ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप बैठ जाइए। बैठ जाइए आप। ...(**व्यवधान**)...

†**प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ :** इस मोशन पर बोल रहा हूं मैं, इसी मोशन पर। ...(**व्यवधान**)...

پروفیسر سیف الدین سوز : اس موشن پر بول رہا ہوں میں، اسی موشن پر .....مداخلت.....

श्री संजय निरुपम: जो मंत्री महोदय ने एप्रुव किया है उस मोशन पर आप बोल रहे हैं या जो सुषमा जी लेकर आई हैं आप उस मोशन पर बोल रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

†**प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़:** मैं दोनों मोशन पर बोल रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

پروفیسر سیف الدین سوز : میں دونوں موشن پر بول رہا ہوں .....مداخلت....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is the procedure. When the motion is moved ...(*Interruptions*)... Now, it will be taken up for discussion. you can give your name. Then you can speak. ...(**व्यवधान**)...

प्रो॰ रामबख्श सिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि जब आप खड़े हुए, तब भी यह माननीय सदस्य खड़े हुए थे, अब भी यह बैठे नहीं हैं।

श्री उपसभापति: आप बैठिए प्लीज़ यह सब पर लागू होगा, आप बैठ जाइए।...(**व्यवधान**)...

†**प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़:** जनाबे आला, मैं आपकी वसाकत से ...(**व्यवधान**)...

پروفیسر سیف الدین سوز : جناب عالی، میں آپ کی وساطت سے .....مداخلت.....

SHRI SANJAY NIRUPAM: Is he speaking on the Bill?...(*Interruptions*)...

†**प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़:** ये क्या करना चाहते हैं? ...(**व्यवधान**)... मैं आपकी वसाकत से अपनी बहन को ...(**व्यवधान**)...

پروفیسر سیف الدین سوز : یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ .....مداخلت.....میں آپ کی وساطت سے اپنی بہن کو .....مداخلت.....

SHRI SANJAY NIRUPAM: I want to know on which motion if Prof. Soz is speaking ? Is it on Sushmaji's motion?

†**प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़:** भई, यह सुषमा जी का मोशन था, that is the rule, that is the procedure.

پروفیسر سیف الدین سوز : بھئی، یہ سشما جی کا موشن تھا، ''دیٹ از دی رول، دیٹ از دی پروسیجر''۔

†Transliteration of Urdu Script.

श्री उपसभापतिः आप बैठिए, आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... संजय जी, आप कृपया बैठिए। ...(**व्यवधान**)..I want to explain. You see, both the motions are before the House. ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए।...(**व्यवधान**)... मैं जब खड़ा हुआ हूं तब आप मेहरबानी करके बैठ जाइए। Both the motions are under consideration. So you can speak on both motions. ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराजः उपसभापति जी, बिल पर डिबेट शुरु करिए, फिर दोनों मोशन पर लोग बोलेंगे। बाद में वोटिंग होगी। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः कृपया आप बैठिए।

†**प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़ः** सुषमा जी, मोहतरमा मैम्बर जो उस साइड में हैं, उन्होंने इसके विरोध में जो कुछ कहा है, उस पर मैं कुछ बोलना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)... सवाल यह है कि इनका मोशन आपके सामने है, हम तो केवल उसी पर राय दे रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

پروفیسر سیف الدین سوز: سشما جی، محترمہ ممبر جو اس سائڈ میں ہیں، انہوں نے اس کے وِرودھ میں جو کچھ کہا ہے، اس پر میں کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ مداخلت۔ سوال یہ ہے کہ ان کا موشن آپ کے سامنے ہے، ہم تو صرف اسی پر رائے دے رہے ہیں۔ .....مداخلت ....

डा॰ मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, अगर विधेयक पर चर्चा है तो पहले इस पर मंत्री महोदय को बोलना होगा।...(**व्यवधान**)...क्योंकि वे विधेयक के कंसिड्रेशन की बात कर रहे हैं, तो पहल उनको बोलना होगा।

श्री बलवंत उर्फ बाल आपटे (महाराष्ट्र): सर, मैं सुझाव देना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः अब सुझाव हो गया, अब मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं।

श्री बलवंत उर्फ बाल आपटेः सलेक्ट कमेटी वाला जो आपके सामने अमेंडमेंट है उस पर आप पहले विचार करें, If I am a supporter of the Motion, how can I speak on the Bill along with that? Therefore, first decide on sending the Bill to the Select Committee.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Minister's Motion has been taken up.

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, procedurally, this is not correct. This is not according to precedents, because we always dispose of amendments at the end.

---

†Transliteration of Urdu Script.

श्रीमती सुषमा स्वराज: नहीं, वह नहीं होगा। सर, मंत्री जी को कहिए।

SHRI ARJUN SINGH: Sir, the main objectives behind bringing this Bill, through the Ordinance route to which the hon. Member is taking objection, have been spelt out quite clearly in the Statement of Objects and Reasons attached to the Bill. It is evident as to why we have taken this route.

The question of minorities and their right to establish their institutions is enshrined in the Constitution itself. It is a fact that this right is a right which transcends all other rights that anybody may have in this regard. That is the meaning of the Fundamental Right. In the interim period, for many years, the minorities enjoyed this right and there are hardly any problems. If there was any problem, It was 'judicial problem.' If anybody wants to take any provisions to court, he is free to take the matter to courts. People have been taking issues to the courts and decisions of the Supreme Court, on many issues, are before us. What made for special consideration and, therefore, this route selected was this. A meeting, on 3rd July, 2004, where more than 300 representatives of all minorities in the country, cutting across every consideration, was held here. A two-day discussion took place as to what was weighing in the minds of the minorities regarding their right to establish institutions as enshrined under the Constitution. This was an effort to ascertain what they felt to be the inhibiting factor. The CMP of this Government took this matter on a very high priority. Therefore, this dialogue was very necessary. And the fact that dialogue was given importance can be considered by this fact along that the hon. Prime Minister himself initiated it on 3rd July. And, in this dialogue, all the fears, apprehensions and anxieties of the minorities were spelt out. The question arose as to what we should do to give quietus to these apprehensions and complaints, and restore to the minorities their rights, as enshrined in the Constitution. Many of these apprehensions were as to how the Government, as such, dealt with these problems. And, what came up in this dialogue brought out it very, very clearly that the gravest apprehension was there in the minds of the minorities that the Government that was there for the last 3-4 years tried to slight their rights and, in some cases, even trampled upon it. Two examples were given in this regard, about which I must inform the House. The first example was given with regard to the National Education Policy of 1986, which is at the moment the prevailing national policy. No different policy has been enunciated after that. This was enunciated in 1986 by the late Prime Minister, Shri Rajiv

Gandhi, who took into confidence the entire nation and Parliament before this policy was made effective. In that policy framework it was mentioned that it provided for the establishment of a Monitoring Committee for Minority Education. And, this Monitoring Committee was duly set up on 28th July, 1995 for a three-year term. This term ended in July, 1998. It is a very surprising feature—and in my view, even a shocking feature—that the previous Government which swore by the National Educaton Policy of 1986, time and again, the then hon. Minister of Human Resource Development used to mock at us, "I am following the policy of Rajiv Gandhi. Why are you criticising?" He used to mock at us in this very House, Sir. I want to tell him and this august House that this important feature of that policy of setting up a Monitoring Committee for Minority Education was given a goby by him and his Government when they failed to reconstitute this Committee when its term expired in 1998. This Committee, Sir, for the knowledge of hon. Members who might have not taken notice of it, was in fact reconstituted only on 7th August, this year, because this was very much a part of the National Education Policy. This was one apprehension, which every delegate to this dialogue voiced in a very firm and emphatic terms. Naturally, we had to take notice of it. The second was an example from your State, Sir, from Tamil Nadu. (*Interruptions)*

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: He is from Karnataka.

SHRI ARJUN SINGH: Believe me. He is from Tamil Nadu. (*Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; no. He is correct. (*Interruptions)*

SHRI ARUN SINGH: I am saying 'Tamil Nadu'. (*Interruptions*)

SHRI S.S. AHLUWALIA (Jharkhand): Sir, he said 'your State'. (*Interruptions*) The Chair does not belong to any State. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I belong to one State or the other. (*Interruptions*) There is nothing wrong in it. (*Interruptions*)

SHRI S.S. AHLUWALIA: The Chair belongs to the House. (*Interruptions*)

SHRI ARJUN SINGH: Sir, all these apprehensions went into the mind of the Government when it decided that it has to go through the Ordinance route and not though the regular route as is being suggested now.

The second example is this. Sir, the Karunya Institute of Tecnology and Science applied for a deemed university status on 17th March 2000, to the Ministry of HRD under section 3 of the UGC Act. For the information of

the House, I would like to read it out. It says, "The Central Government may, on the advice of the Commission, declare by notification in the Official Gazzette, that any institution for higher education, other than a University, shall be deemed to be a University for the purposes of this Act, and on such declaration being made, all the provisions of this Act shall apply to such institutions as if it were a University within the meaning of clause (f) of section 2." In other words. Sir, the only legal requirement for the Central Government to notify the Karuny Institute of Technology and Science as a deemed University was a positive recommendation from the UGC. This was the normal practice followed by the Government in all cases. The UGC, on its part, follows a prescribed procedure. I am taking the time of the House to make the House aware of what went into decision. The UGC, on its part, follows a prescribed procedure, including sending its own committee of experts to examine the Institute. In this case as well, Sir, the UGC sent its own Committee of experts, which included as many as five Vice Chancellors, including three Vice Chancellors of Technical Universities. The UGC recommended the case of Karunya Institute of Technology and Science for granting deemed University status after following all procedures on 24th April 2001 to the Ministry of HRD. Thus, under the UGC Act, nothing remains for the Government to do expect a simple notification, with the approval at the level of Minister of HRD. Now,strange things started happening, for reasons that are not recorded on the files, for reasons, which I don't know, and for reasons, Sir, what the then Secretary to the HRD Ministry told to me on face. When I asked him, "What are the reasons for all this?" He told me, Sir, I cannot tell you anything." Now, when the Ministry, its own apparatus, the person who is responsible for running it, the person who is the statutory secretary says, "I don't know", then what do we do? The file says, Sir, I am speaking of my own information. After the UGC had given this recommendation, which was the only valid thing required, the AICTE took the unusual stand that all the courses already approved by the AICTE itself—it had previously approved the subjects, which the Institute was teaching—further needed to be accredited by the National Accredition Board, and, therefore, the Ministry of HRD chose not to act on UGC's recommendation. This is a step totally uncalled for. I will say it is totally*. It was taken with prejudice. And you want to now give us the lecture. Sir, the UGC protested that under the UGC Act, the AICT stand was not penable. I did not protest, the UGC

*Not recorded.

protested it. Between April 2001 and 23rd June, 2004, till the present Government conferred the deemed university status to Karunya, no action was taken by the Minister of HRD. For three years, this was left almost as a forgotten case, dealing with minorities. One may well ask, was the Minister unaware of this? I would have preferred to say that, yes, he was unaware. I would have preferred to say. But the file speaks otherwise.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, it is one o'clock. I would like to take the sense of the House that should we continue with this and forgo the lunch hour.

1.00 P.M.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Let him finish his speech ...*(Interruptions)*...

SOME HON. MEMBERS: After the Minister's speech.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will tell you why because the hon. Prime Minister is going to reply at 4.30 p.m. Before that, we have to conclude the debate.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, we can forgo the lunch hour.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is the sence of the House? Should we forgo the lunch hour?

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Sir, we can forgo the lunch hour... *(Interruption)*...

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI GHULAM NABI AZAD): Sir, we can forgo the lunch hour...*(Interruptions)*...जिसको खाना होगा, लंच खा लेगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज: आपकी मरज़ी।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yesterday, we did it.

SHRI GHULAM NABI AZAD: We hae to complete everyday.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There will be no lunch break.

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया जब लंच forgo करते हैं, तो सारे लोग लंच खाने चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि सदन में इतना महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया था और सदन में कोई उपस्थित नहीं था। यह तीन घंटे की बहस है, लंच के बाद ले ली जाए। उसके बीच में प्रधान मंत्री जब आएंगे, तो वे अपना जवाब देकर चले जाएंगे, उसके बाद फिर इसको टेकअप कर लेंगे।

SHRI ARJUN SINGH: Sir, the file says two things. And I am refreshing the memory of the hon. Ex-Minister, Shri Joshi. I don't accuse him of a lapse of memory, but he does have a selective memory. The Institution felt that it was being targeted for no rhyme or reason. So, Sir, it went to the Madras High Court to challenge this. The Madras High Court heard their case and directed that the Government should give a recognition to this institute within a month. The file only says as to how to deal with that direction, they did not send, but the Secretary wrote in the margin, "there is no hurry about it." What kind of signal do these notes send out? I would not like to say anything on my own, this august House is competent enough to judge. The hon. Minister only wanted that a very, very senior person should take up this issue and appeal against it, obviously, to the Supreme Court. Sir, as I said, it is with no pelasure that I am reading this out, because, normally, what goes on between the covers of files should not be discussed publicly. It is bad administration. But we are left with no choice, when people who are entrusted with responsibility, people who are given the responsibility under the Constitution to deal fairly and equitably with all kinds of citizens, take this atitude in matters concerning minorities. Sir, it is not that the hon. Minister still did not know about it. Many senior Members of Parliament cutting across the political persuasions wrote to the hon. Minister reminding him that injstice is being done. Some of these names I would like to place before this House—Shri Vaik[illegible] May, 2000; Shri Denzil Atknson wrote on 23rd July, 1[illegible] November, 2002; Shri Master Mathan wrote in June 2[illegible] Sangma wrote in April, 2003.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Are we discussing this matter?...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापतिः एक्सप्लेन करने दो...(व्यवधान)

SHRI S.S. AHLUWALIA: Let the explanation come after the speech...*(Interruptions)*...

SHRI M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI (Kerala): He has the proof. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापतिः आप बैठिए। ...(व्यवधान)... अब तक तो आप चुप थे। ...(व्यवधान)...

SHRI ARJUN SINGH: They wanted to know...*(Interruptions)*... I am not voluntary ...*(Interruptions)*... The question came from them. Why? And who is going to answer it? ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Let the debate be over...*(Interruptions)*...

SHRI ARJUN SINGH: Let the debate be over! No...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Let the debate be over. You have full opportunity to speak or write...*(Interruptions)*...

SHRI ARJUN SINGH: What will be left the debate be over?...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: The question is very simple. Why is the Ordinance route.

SHRI ARJUN SINGH: Pardon.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Why is the Ordinance route?

SHRI ARJUN SINGH: This is what I am answering ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: It can go to the Committee. It can be discussed in the Committee. It can come as a simple Bill...*(Interruptions)*...

श्री सुरेश पचौरी (शिकायत कार्मिक लोक और पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्रालय में राज्यमंत्री): अहलुवालिया जी, हो सकता है कि सारी बातें सुनने के बाद आपकी समझ में आ जाए। ...(व्यवधान)... डिसकसन की आवश्यकता ही न पड़े। ...(व्यवधान)...

SHRI ARJUN SINGH: It is not a story. It is a spectacle...*(Interruptions)*... It is a spectacle of naked abuse of power against the minority ...*(Interruptions)*... It is nothing less than that, and so much so ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Let us discuss the serious debate on this ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can have your seat, Mr. Ahluwalia ...*(Interruptions)*... You can have your seat ...*(Interruptions)*... Please sit down ...*(Interruptions)*...

SHRI ARJUN SINGH: Don't try to shout me down...*(Interruptions)*...

SHRI YASHWANT SINHA (Jharkhand): But the hon. Minister, unfortunately, is being extremely provocative. He is being extremely provocative. This is not the way ...*(Interruptions)*... This is not the way ...*(Interruptions)*... He just picked up views ...*(Interruptions)*... One does not know which file he is refering to, and he is levelling one charge after another ....*(Interruptions)*... This is not the way...*(Interruptions)*... If this is the way he is behaving then, I am sorry ...*(Interruptions)*...

डा. मुरली मनोहर जोशी: उपसभापति जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय सदन को यह बताएंगे कि मेरे कार्यकाल में कितने मायनोर्टीज इंस्टीट्यूशन्स को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज का स्टेटस दिया गया? ...(व्यवधान)...I will produce the entire list before the House as to how many instiutions have been accorded the status of deemed universities during my time, and during the predecessor's time ...*(Interruptions)*... I have the whole list here. ...*(Interruptions)*... He is misleading the House ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am on my legs ...*(Interruptions)* Mr. Ahluwalia, please sit down...(Interruptions) I am on my legs. Please sit down. The Chair cannot say to the hon. Minister, when he is explaining, what he has to say, what he has not to say. It is his prerogative. At the sametime, you have got the right to reply when you get your chance. You have the right to demand whatever you are now demanding when your name will be called. There is precedence. There are rules. The Chair will not be able to direct a particular Member to speak in a particular way. So, it is their prerogative and their veiw point ...*(Interruptions)* Let us follow the rules. If you bring to my notice any rule, which is violated, then I will look into it and give my ruling ...(Interruptions)

SHRI YASWANT SINHA: Sir, I am talking about the rules.

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभापति जी, हम रूल्स की बात कर रहे हैं, मैंने अपना मोशन देते समय केवल एक प्रश्न किया था कि वाय ऑर्डिनेंस रूट, रुटीन में क्यों नहीं आया ...(व्यवधान)... वे उसका जवाब दे सकते हैं ...(व्यवधान)... उसका जवाब देते हुए ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: अगर आपने यह सवाल किया था के वाय ऑर्डिनेंस रूट, और उसका जवाब चाहते हैं, तो वे कैसा जवाब दे, यह मैं नहीं कह सकता लेकित वे दे रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: उसका जवाब देने में यह रिलेवेन्ट कहां से आ गया ...(व्यवधान)... एक ब्रीफ स्पीच होती और वह भी रूल के बारे में ...(व्यवधान)... introduction of Bill will be brief...(Interruptions)

SHRI YASHWANT SINHA: Is this a brief speech that he is making? He is going through the whole history how the Ministry had functioned and he is quoting selectively ...(Interruptions).. He has already taken forty minutes at the introduction stage ...(Interruptions)

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, जब उन्होंने कहा ...(व्यवधान)... एक मिनट ...(व्यवधान)... जब उन्होंने कहा ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: देखिए ...(व्यवधान)...Why are you coming out of your seat?...(Interruptions).. Please be in your seat.

श्रीमती सुषमा स्वराज: कितनी माइनोरिटी इंस्टीटयूशन्स को हमने डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया, यह नहीं बता रहे हैं ...(व्यवधान)... रूल्स को लेकर डिसकस कर रहे हैं ...(व्यवधान)...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Sir, my simple question is, and my simple request is that the hon. Minister may explain everything, but he has no right to mislead the House. He should place facts before the House if he is discussing ....*(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I agree.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: If he is trying to place one fact,then he must explain how many minority institutions were given the 'Deemed to be University' status in those five-and-a-half years. And, then, if he can prove that there was a case of ignoring the claims of the minorities, that will be justified. But, by citing only one case by ignoring more than two dozen cases, where the minorities' universities were also given 'Deemed to be University' status, why is he not giving full facts and the help that Ministry gave to the minority institutions? Why is he not coming with the full facts? What we did for the Jamia Humdard. He must be brief. A Minister is expected to place honest facts before the House...*(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: By this time, the hon. Minister would have completed the remarks ...*(Interruptions)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभापति जी, मार्जिन में क्या लिखा था ...(व्यवधान)... अगर वे एक जवाब दे रहे हैं, जवाब भी नहीं दे रहे हैं, एक बिल की कंसीडरेशन एण्ड पासिंग के लिए अपना एक ब्रीफ रिमार्क दे रहे हैं, जिसमें वे कह रहे हैं कि फाइल के मार्जिन में क्या लिखा था, वाइको ने क्या चिट्ठी लिखी, एलेक्जेंडर ने क्या चिट्ठी लिखी, अकिन्सन ने क्या चिट्ठी लिखी। आज तक जितने भी बिल इंट्रोडयूज हुए हैं या कंसीडरेशन एण्ड पासिंग के लिए रखे गए हैं, क्या किसी मंत्री ने इस तरह का जवाब देकर या रिमार्क देकर बिल रखा है? चेयर को बताना पड़ेगा ...(व्यवधान)... एक सवाल यह आया कि वाई ऑर्डिनेंस रूट ...(व्यवधान)... वाई ऑर्डिनेन्स रूट के जवाब में क्या फाइलें पढ़ी जाएंगी? फाइलों के मार्जिन में क्या लिखा है क्या यह बताया जाएगा? ...(व्यवधान)... क्या हम चुरहट की लॉट्री की फाइल मंगाएं? क्या हम यहां चुरहट डिसकस करें?...(व्यवधान)... मंगाइए चुरहट की फाइलें, अब वे यहां डिस्कस होंगी ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down...*(Interruptions)*... I am on my legs...*(Interruptions)*...

श्रीमती सुषमा स्वराज: हम चेयर से निवेदन करते हैं कि चुरहट लाटरी कांड की फाइलें मंगाइए, यहां चुरहट लाटरी कांड डिस्कस करिए। सदन का मजाक बना रखा है ...(व्यवधान)...

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, the Minister, as I said, has been irrresponsible...*(Interruptions)*...सदन में बात करने का एक तरीका होता है, ये इस तरह से बात करेंगे...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. I am on my legs.आप बैठिए प्लीज...(व्यवधान)...

SHRI YASHWANT SINHA: And, if he decides to ...*(Interruptions)*... the House, we will reply to him.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Yashwant Sinha, you are a senior Member of this House. Please sit down ...*(Interruptions)*...I am on my legs. Is it the...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, as per the Rules....*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I would like to bring to the notice of the hon. Members that as per the Rule, at the time of introduction, the Minister will make a brief statement, and, the Minister will have an opportunity to give detailed reply at that time. Now, I would request the...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, the whole speech should be expunged.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. There is no question of expunging. Where is the question of expunging.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, it is violation of the Rules...*(Interruptions)*...

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, you have just given the ruling...*(Interruptions)*... So, whatever he has said...(Interruptions)... This is clearly the violation of the Rules. All the details that...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. I have not given ...*(Interruptions)*...Please sit down. No, no...(*Interruptions*)... See, there is no ruling....*(Interruptions)*...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Sir, you are standing, and, whatever he is saying should not go on record ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seats...*(Interruptions)*... I am on my legs. .देखिए, जब भी मैं खड़ा होता हूं, आप भी खड़े हो जाते हो। प्लीज बैठिए ...(व्यवधान)...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD (Bihar): Sir, I have a point of Order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down ...(*Interruptions*)... He has a point of Order.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, I would like to draw your attention to Rules 121 and 122. Rule 121 says: "When a Bill originating in the House has been passed by the House, and is transmitted to the Council, the Bill shall, as soon as may be, be laid on the Table."

And, the Rule 22 says, "At any time after the Bill has been so laid on the Table, any Minister in the case of a Government Bill, or in any other case, any Member may give notice of his intention to move that the Bill be taken into consideration."

Then follows the motion for consideration, which you have already stated. The long speech which the hon. Minister is giving, is a highly provocative manner, is it permissible under the Rules? If that is not there, it should be completely expunged ...(*Interruptions*)... It should be expunged completely.

SHRI S.S. AHLUWALIA: The whole speech should be expunged. This is strictly the violation of the Rules ...(*Interruptions*)... The whole order is changed.

श्री उपसभापति: आप बैठिए, आप बैठिए ना ...(**व्यवधान**)...Do you want the Chair to rule, or, do you want to rule? ...(*Interruptions*)...

SHRI EKANTH K. THAKUR (Maharasthra): Sir, he has spoken. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have already said that the Minister has to make a brief statement. He is making ...(*Interruptions*)...

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, the Minister is also on his legs. He should sit down ...(*Interruptions*)...

श्री तारिक अनवर (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, सबको भूख लग गई है, इसलिए हल्ला कर रहे हैं और कुछ नहीं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, sit down. Now, that the Minister has given a brief statement. It is an indication and it is to be followed. But what the Minister has to say, how much he has to say to convince the House, he has the right to say whatever before the introduction ...(*Interruptions*)... No, before the introduction...

SHRI EKANATH K. THAKUR: But the Minister has no right to mislead the House...(*Interruptions*)...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, the long speech that the Minister is ...(*Interruptions*)...

श्री संजय निरुपम: लेकिन जो कहा, वह तो निकालना पड़ेगा, वह तो expunge करना उड़ेगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seats. Now, I will request the Minister...(*Interruptions*)... Let him conclude.

SHRI ARJUN SINGH: Sir, I am...(*Interruptions*)...

श्री दीपांकर मुखर्जी: बहुत हो गया तमाशा। Sir, it should not go on record. -ये सब कंपीटीशन हो रहा है, अंदर का।

श्री नारायण सिंह केसरी (मध्य प्रदेश): उपसभापति जी ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not allowed. -इस तरह चीखकर बोलना allowed नहीं है। प्लीज आप इस तरह से चेयर को address नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते।

SHRI ARJUN SINGH: Sir, I will follow the direction from the Chair in letter and spirit. But, the Chair will also consider the fact that an unusual steps has been taken . Normally, it is not done, 'normally'. I don't question the right of the hon. Member to move a Resolution.And, in that Resolution, the presumption has been raised-presumption, otherwise the Resolution was not necessary- that perhaps the ordinance route was not necessary and it has been taken and the direct question was asked "Why was it taken". Now, Sir, should I say that right has been taken away? Is the House not entitled to know why you have taken it, because this is not an issue on which, in a fit of absent-mindedness, I did it? The entire Government's prestige is involved in it. The Cabinet would have not approved my proposal for the ordinance route if there was no substance in it, no strenght in it. So much so, Sir, even ...*(Interruptions)*... फाइल एक ही है। अगर चेयर परमिट करें तो व फाइल ही मैं आपके सामने रख सकता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: ये मंत्री हैं ...(व्यवधान)...अपना अधिकार जानते हैं. ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बैठिए। ...(व्यवधान)...

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka): Sir, I have a point of order ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your point of order?

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, Clause II of rule 235 says, "Whilst the Council is sitting, a Member shall not interrupt any Member while speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly manner; shall not obstruct proceedings, hiss or interrupt and avoid making running commentaries". They including the former Minister are making a running commentary...*(Interruptions)*. After your ruling, there are still interruptions. ...*(Interruptions)*. So, Sir, let the hon. Minister continue his speech ...*(Interruptions)*.

SHRI BALAVANT *alias* BAL APTE: Sir, there is only one thing which I want to remind ....*(Interruptions)*.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Apteji, you are a senior Member. You know the rules...*(Interruptions)*.

SHRI BALAVANT *alias* BAL APTE: I am mentioning only one thing that we are discussing here a Bill, and the discussion is initiated by the Minister in respect of a Bill. We are not discussing a file where a right to reply will come. You have said, "You have a right to reply". Reply on what? On the Bill or on the file? Therefore, let that file be not a matter of discussion; let the bill be a matter of discussion.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Sir, the hon. Minister is ...*(Interruptions)*. He is advising ...*(Interruptions)*.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, you please take your seat ...*(Interruptions)*.

SHRI ARJUN SINGH: Sir, as I said, I will put an end to this ...*(Interruptions)* उपसभापति महोदय, तमिलनाडु के बीजेपी के एक नेता डा॰ तिरूवलनिथि ने भी इस संबंध में लिखा, कम-से-कम उनकी बात तो सुन लिए होते। ... (व्यवधान)

श्री एस. एस. अहलुवालिया: बिल पर बहस कीजिए .. बिल पर बहस कीजिए, बहुत सारी फाइलें देखनी पड़ेगी ... (व्यवधान)

SHRI ARJUN SINGH: Now, in this background, Sir, ...(*Interruptions*) अहलुवालिया जी, जरा सब्र से काम लीजिए। आप तो ... (व्यवधान)

श्री संजय निरुपम: इसलिए पूरा विषय सलेक्ट कमेटी के पास जाए ताकि हम सारी फाइल्स देख सकें। आप सारी फाइल्स अकेले क्यों पढ़ रहे हैं, हमें भी पढ़ने दीजिए, हमें भी जानने दीजिए।

श्री अर्जुन सिंह: माननीय उपसभापति महोदय, इस पृष्ठभूमि में तीन जुलाई का डायलॉग बहुत मटैरियल था। महोदय, जिन के लिए हमें कानून बनाना था, उन के रिप्रजेंटेटिव्स की ओर से ये सारे एप्रिहेंशंस रेज किए गए हैं। मैं क्या जानूं कि कहां क्या हुआ है? उन लोगों ने उदाहरण दिए, तब ये सब चीजें देखी गयीं। इसलिए उन का भी यह सुझाव था और हमारा भी यह निष्कर्ष था कि अगले एकैडेमिक सेशन में इस तरह की बातों की पुनरावृत्ति न हो ओर किसी को इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करने का मौका न हो, इसलिए इस एक्ट को ऑर्डिनेंस के रूप में लाया जाए ताकि नेक्स्ट एकैडेमिक ईयर में यह इफैक्टिव हो जाए। फिर इस तरह की चीजें जहां आएं, वे कमीशन के पास जाएं जिस का एक जूडिसियल चैयरमेन है, he will look into it, और अपनी राय देकर आगे की बात करे। इसलिए यह ऑर्डिनेंस के रूप में लाया गया और कैबिनेट ने इस ऑर्डिनेंस को अप्रूव किया, लोक सभा ने इसे अप्रूव किया। अब इसे यहां भी अप्रूव किया जाये, यह मेरी दरख्वास्त है।

श्री उपसभापति: श्री बलवंत उर्फ बाल आपटे।

श्री यशवन्त सिंहा: सर, लंच।

श्री उपसभापति: नहीं, वह फोरगो किया है।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सर, जब आप ने सदन से पूछा तो हम ने भी अपनी बात रखी।

श्री उपसभापति: आप ने कहा, वह हम मानते हैं, लेकिन ...(**व्यवधान**)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: There is a limit. ..*(Interruptions)*... Superman of this House or what..(interruptions).. वह बार-बार खड़े हो जाते हैं।

श्री उपसभापति: नहीं-नहीं, आप बैठिए, प्लीज।

श्री दीपांकर मुखर्जी: आप पहले उन्हें बिठाइए।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: खड़े होने की ताकत है, तभी तो खड़े होते हैं।

श्री दीपांकर मुखर्जी: सर, यह क्या है, यह सुबह से चल रहा है।...(**व्यवधान**)...ज्ञानी जी बोले जा रहे हैं, हाउस में सुबह से ज्ञान दिए जा रहे है। हाउस में इन पर कोई कंट्रोल नहीं है। हम सुबह से ज्ञानी जी का ज्ञान सुनते-सुनते थक गए हैं। ज्ञानी जी, सुबह से किसी भी विषय पर ज्ञान देते रहते हैं। ...(**व्यवधान**)... जब मर्जी आई, बोल दिए। सर, इन्हें बिठाइए।

श्री उपसभापति: आप बैठिए। He is going to make a speech. *(Interruptions)*... आप शुरू कीजिए।

श्री दीपांकर मुखर्जी: जब तक ये नहीं बैठेंगे, हम भी नहीं बैठेंगे।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: मत बैठो, हम खड़े हैं।

श्री उपसभापति: अब मैं खड़ा हूं, इसलिए आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... अहलुवालिया जी, प्लीज बैठ जाइए।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: नहीं सर, वह कहते हैं कि खड़ा हो जाता हूं...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Dipankar, whether he sits or not, but I am standing here ...*(Interruptions)*... you should sit down.

SHRI BALAVANT *alias* BAL APTE: Sir, it appears that both of them are hungry, Let us have a lunch. *(Interruptions)*

SHRI BALBIR K. PUNJ (Uttar Pradesh): He cannot be given monopoly rights for disrupting the House. *(Interruptions)*. He wants monopoly rights for disrupting the House.*(Interruptions)*

श्री उपसभापति: पुंज जी, आप बैठिए।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सर, यह आप कार्यवाही से निकलवा दीजिए। वह कह रहे हैं कि अहलुवालिया जी जब इच्छा होती है, खड़े हो जाते हैं। अरे भाई, खड़े होने के लिए भी इनर्जी चाहिए,

ताकत चाहिए। आप भी ले लो, खड़े हो जाओ। ...(व्यवधान)... खड़े होने के लिए कुछ चाहिए। ...(व्यवधान)...

SHRI BALAVANT *alias* BAL APTE: Sir, I believe both of them are hungry. *(Interruptions)*

†मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी (मध्य प्रदेश): ये कौनसी इनर्जी की बात कर रहे हैं?

†مولانا عبیداللہ خان اعظمی: یہ کون سی انرجی کی بات کر رہے ہیں؟

श्री उपसभापति: मौलाना जी, आप बैठिए। मौलाना जी, देखिए आप वक्त का लिहाज़ रखिए।

SHRI BALAVANT *alias* BAL APTE: Sir, my only conclusion is that both of them are hungry, can we have a lunch?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please.

SHRI BALAVANT *alias* BAL APTE: Sir, I seek to oppose this Bill because I find that it is cosmetic and hypocritic. Sir, I remember an old adage,

''शरदि न वर्षति गर्जति, वर्षति वर्षासु, निःस्वनो मेघः।
नीचो वदति न कुरुते, वदति न साधुः करोत्येव''।।

महोदय, जिन को कुछ नहीं करना है, वे बातें ज्यादा करते हैं और जिन को कुछ करना है, वे बातें कम करते हैं। इस बारे में दो उदाहरण आप के सामने रखना चाहता हूं। सर, एन.डी.ए. सरकार ने अपने कार्यकाल में मौलाना आजाद एजुकेशन फाउण्डेशन को जिन्दा करते हुए, 352 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन्स को 69 करोड़, 65 लाख 39 हजार की मदद दी। तीन हजार मदरसों को मॉडर्नाइजेशन के लिए मदद दी। सैंकड़ों छात्राओं और हजारों छात्रों को स्कॉलरशिप्स दी। उर्दू एकेडमी का बजट, जो इनके कार्यकाल में 84 लाख था, उसे 11 करोड़ किया, जिस पर डा॰ रफीक जकारिया ने डा॰ मुरली मनोहर जोशी को ओपेनली कम्प्लीमेंट किया। इसके बाद जाहिरात एन.डी.ए. ने नहीं की, क्योंकि ''वदति न साधुः करोत्येव'' ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: शाहिद सिद्दिकी साहब, प्लीज। आप का नाम है। जब आपका नाम आएगा तब बोलिएगा।

श्री बलवंत उर्फ बाल आपटे: सर, इनकी हिप्पोक्रेसी का दूसरा अभिलेख, इस पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स में है। 1977 में जब जनता पार्टी का शासन आया, तब कंस्टीट्यूशन 46th एमेंडमेंट बिल 1978 मूव किया गया, जिसमें आर्टिकल 338 सब्सीट्यूट करने की बात हुई। Article 338 provides for a Commissioner for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. By that amendment, it was proposed that there shall be a

†Transliteration of Urdu Script.

Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and it was also proposed that there shall be a Commission for the Minorities, to be known as the Minorities Commission.

Sir, it is a matter of record that the Scheduled Castes and Schedules Tribes Commission amendment was passed but the Minorities Commission amendment was not passed because of the Members of the other side. Therefore, this that they opposed a Minorities Commission getting a constitutional status, and now they are bringing forward this Bill, exposes their hypocrisy. क्योंकि उनको कुछ करना नहीं है। भाषण करना है। कुल मिलाकर इनका व्यवहार ऐसा है कि "शरदि न वर्षति गर्जति"। Sir, this Bill actually is not for minorities. It is for minority institutions, which, in the present circumstances of dearth of professional colleges and demand for seats, want to make money. Therefore, this Bill is to favour these institutions, which want to make money,

If I come to the legislation *per se*, I find firstly, it is unnecessary. We already have the National Commission for Minorities Act 1992. This Act makes provisions for the protection of the interest of minorities, minorities education, minorities welfare, and if at all, they wanted an authority to deal with even the affiliation of minority institutions, one simple amendment in that Act might have been necessary, might not have been necessary. But if you want to make a show that you are doing it for the minorities, you must bring a Bill with fanfare. That is what is required. Therefore, my first objection is that this is an unnecessary Bill. My second objection to this Bill is, it is patently *mala fide*, and the *mala fides* are writ large on the statement as to why an Ordinance was issued. The statement makes a mockery of the concept of Ordinance-making power under article 123 of the Constitution. It is a power which is termed as an emergency power, which is termed as a power to be exercised when the Parliament is not in Session, and there are circumstances, compelling reasons, which require to resort to this power. Now what is the urgency which is spelt out in the proclamation?

> "In view of the commitment of the Government in the National Common Minimum Programme,..."

--on the basis of which they came to power six months ago--

> "...the issue of setting up a National Commission for the minority educational institutions was a matter of utmost urgency."

No circumstances are referred to, not even mentioned! And this is done on 11th November,2004. Normally, the Parliament sits from the week commencing from 17th November or so. They did not have any Legislative Business; therefore, the Session was cut short to three weeks. If the Parliament were to sit on 17th November, what was the urgency to issue an Ordinance on 11th November? Therefore, my attack on this Bill is on the basis that it is a Bill *mala fide* not for the purposes for which it is sought to be enacted.

My more serious objection to this Bill is with reference to Article 30. The source of Minority Institutions' rights is Article 30. The way that Article has been used and interpreted by the courts, it has become a privilege to be a minority in this country because you are above law, because you are above regulation, and, therefore, if you are an institution, with the label 'minority' on it, you can do whatever you like, ...*(Interruptions)*...

†प्रो॰ सैफुद्दीन सोज: कोई भी एग्जाम्पल दे दीजिए।

†پروفیسر سیف الدین سوز : کوئی بھی ایگزامپل دیدیجئے۔

श्री उपसभापति: सोज साहब, आप इस पर बोलने वाले हैं, न? उस वक्त बोल लीजिएगा।

SHRI BALAVANT *alias* BAL APTE: Even the Ramakrishna Mission was tempted to claim the 'Minority' status because it found that it was a matter of privilege to be a minority, to be above law. But that is about Article 30, which is a larger issue. What I am pointing out is, the Statement of Objects & Reasons says that the Constitutional guarantees are there, but still justice is not being done. And then the Act goes on talking about the minority institutions by defining them in clause (g) of Section 2. The Supreme Court has consistently held that for an institution to be a minority institution, it has to be established and administered by a minority.

The definition contemplates only the establishement of the institution. The definition is silent about administration. what is mentioned is "established or maintained" "Establishing" or "maintaining" is one thing, and "administration" is totally a different thing. Administration part is missing from the definition. Therefore, the definition is vitiated with reference to Article 30.

†Transliteration of Urdu Script.

There is another definition, and that definition is of 'minority'. 'Minority' is something which, as the Act says, will be decided by the Central Government. How can the Central Government decide about what is stated expressly by and is interpreted, as such, by the Constitution and the Supreme Court. For an institution to be a minority institution, as I said, it is a matter of establishment and administration, and for a minority to be a minority in this country, one attribute is, minorities contemplated in this country are only two, religious and linguistic. The Supreme Court has held that this is not a matter of all-India conception, but since we have linguistic States, the reference to a minority or the concept of minority is referable to a State, not all-India. That is the majority view of the Eleven Judge Bench and that is binding on us, until we have a Constitutional amendment. That view says, "A reference to minority is necessarily with reference to a State. A community is a minority community within a State". Now, how can the Central Government decide that? If at all a Government has to decide, it will be the State Government which would decide. Therefore, the definition of minority is such that the Central Government would do what it wants without reference to article 30 of the Constitution and with a clear danger of this action being unconstitutional.

My next objection to this Bill is on a very small point and I will not elaborate on it. There is a sub-clause in clause 25 of this Bill. This clause is given the specious name of "power to remove difficulties". In other words, by this clause the Executive wants to take over the legislative power of the Parliament. This is notorious in Administrative Law. It is known as the Henry VIII clause and that is a clause by which the Executive wants to take the initiative from Parliament. This clause is introduced in this small Bill. What are the difficulties that you can't foresee? If such difficulties arise--fortunately, our Parliament meets very regularly—we can find solutions. It is not like the British Parliament in the days of Henry VIII. So, why is this Henry VIII clause which is draconian in nature? It really demonstrates the attitude of those in power.

Now, the aspect of minority institutions, in a wider context, has to be looked at from the point of the recent history of the field of education. There we find that, during the last 20 years, with the demand for professional colleges growing, with the State not in a position to have as many professional colleges as is necessary to meet the demands of students—it started with Karnataka and Maharashtra picked it up early, followed by Andhra Pradesh and Tamil Nadu--professional colleges became a business;

open up private unaided professional colleges, charge any fees you like, don't give any infrastructure, don't give any facilities and earn money. That has happened during the last 20 years. The matter went to the Supreme Court. At one stage, in 1993, the Supreme Court laid down some principle. Since the Government did not do anything, the Supreme Court, in the Unnikrishnan case, laid down that there would be free seats, there would be payment seats and there would be support to the poor by way of the rich paying half the fees of the poor. All that happened. The institutions went to the Supreme Court claiming that they are minority institutions and that they have a right to admit their own students on the basis of the decision of the Supreme Court in St. Stephens case. The Supreme Court tried to find a way out and also, in a way, kept ways out for the institutions, from time to time, providing for what are called the management seats through which money was earned.

Sir, in Mumbai, this concept of minority and majority has been given a perverse meaning when we find that Mumbai is the capital of Maharashtra. So, Marathi is supposed to be the language of the majority. In Mumbai, institutions run by Gujarati-speaking, Sindhi-speaking, Punjabi-speaking and South Indian languages-speaking people are working. They never bothered to claim this. Everybody was governed by the University Act, by the statutes under it, by the UGC and now by the IMC and the AICTE. Incidentally, I do not want to go into that discussion. The AICTE's approval is considered, by the Superme Court again, to be above the approval of the university or the UGC. Even if the university approves it, if the AICTE does not approve it, you cannot be a technical institute. Therefore, reference to the AICTE is now inevitable. That is what the Supreme Court has ruled.

SHRI ARJUN SINGH: I would like to point out one thing that each of these courses in this institution had been approved by the AICTE. That should not be forgotten.

SHRI BALAVANT *alias* BAL APTE: I am not on that. But whether a reference to the AICTE is necessary, undoubtedly it is. I am only on that. Since colleges earn money, we have nothing for the students. From St. Stephens, 50 per cent students will be of a particular community which as established the institution. In Andhra Pradesh, we had the spectacle of students getting converted so that they could get admission. This was brought to the notice of the High Court by the Andhra Pradesh Government that this has happened. They gave statistics. This is almost embracing

another religion so that your bigamy becomes legal. There are social ramifications also of this attitude by which colleges were run. In these circumstances, the Supreme Court in the case of T.M.A. Pai and then again in the case of Islamic Academy of Education brought out a formula. They said that there should be a quota for the minority students. It may not be 50 per cent; it may be less or it may be more. If the particular situation of the college is such that there are more minority students, then it need not be 50 per cent; it can be more also. But apart from that, the minority institutions would have their own admission procedures and the management will have certain remaining seats to fill in. * Sir, cases demonstrated in courts. ...*(Interruptions)*.

SHRI ANAND SHARMA: Will you yield for a minute?

SHRI BALAVANT *alias* BAL APTE: You will have your say when your turn comes.

SHRI ANAND SHARMA: When I am speaking, I normally yield. Even yesterday I yielded.

SHRI BALAVANT *alias* BAL APTE: I yielded to you the other day.

SHRI ANAND SHARMA: I will just take a minute. Sir, what is being referred to here are the Supreme Court rulings and that the Supreme court*. This should not go on record. I think it is a very serious matter. It is highly objectionable.

SHRI M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI: Sir, it is highly objectionable.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, he is casting aspersions on the highest court of the land. This forum is not meant for that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will examine the record.

SHRI BALAVANT *alias* BAL APTE: Sir, this is not an aspersion.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will examine the record.

SHRI BALAVANT *alias* BAL APTE: This is an interpretation to which I am entitled and I have said this before the courts. It is not that I am speaking here. I have told the court that this is what is happening.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM (Tamil Nadu): He cannot say it here.

*Expunged as ordered by the Chair.

SHRI BALAVANT *alias* BAL APTE: In such circumstances, whether the college is properly run with proper infrastructure, with necessary teachers, with necessary equipment, becomes necessary and there comes the role of both the university and the AICTE.

Now again under the orders of the Supreme Court—these days the administrations are run by the Supreme Court almost—every university now has a Master Plan. In that Master Plan, the student population is visualised and according to that the nature of colleges, the number of colleges, the areas where colleges are necessary is to be spelt out by the university. In that, colleges are permitted to grow or permitted to be affiliated. In such circumstances, the needs of the area are irrevocably connected with the establishment of a college. Now, if that is so, a university becomes a problem for an institution whose motive is not catering to education. Therefore, now, it is provided for a university of choice. Why? This country has so many universities. Universities function according to certain norms. Every university has its own standards. Mumbai University has its own standards. Pune University has its own standards. Aligarh University has its own standards. Every university has its own standards. And within that area, those standards prevail. Now, to say that I will stay in that area but I will have a university of my choice, is a perversion of your choice and it is not in the interest either of students or of education. And the list, in the Schedule, that is made for purposes of this choice is almost a case of *res ipsa loquit.* I will read only this much. "Colleges all over India seeking affiliation to a university of choice"; and what is the choice today given by this legislation? The University of Delhi is almost for an apology; the North-Eastern Hill University in Dibrugarh; Pondicherry University; Assam University, Nagaland University, Mizoram University. I will not say anything more on this.

Sir, therefore, this choice of university has nothing to do with the independence or the protection of minorities. You want to come out of rules; you want to come out of restrictions which are necessary for purposes of standards. So, go to a remote university. The remote university has no experience of such types of colleges and, therefore, it is very easy for you to convince them. This is not a matter of minority education at all. This is a matter of institutional vested interest. And I am, therefore, opposing it.

Sir, today, insofar as minority institutions and education in them are concerned, there are several unanswered questions which, in fact, it is necessary for the legislature to answer. And if the legislature does not

answer, the Supreme Court is there to legislate. While deciding the earlier cases which I mentioned, the Supreme Court has kept five questions unanswered which are really basic to matters of education. I would just point them out and I would urge that, in fact, if the Minister has some interest of education in his mind, let him legislate on this. The first question is: what is meant by religion? Article 30 talks about religious and linguistic minorities. But what is religion? Can a sect or a denomination claim the status of a religion for purposes of claiming minority status? The law is not very clear. Therefore, Supreme Court had referred this issue to a larger Bench. But they did not answer it. The other question is: What are the indices for treating an educational institution as a minority educational institution? Is it a minority educational institution because a person of minority established it? Or, is it a minority educational institution because it is administered by persons of minority? Question is raised; it is not answered. The third question is: where can a minority institution be operationally located? Can such an institution in one State admit students of their community from other States? This has happened. You establish a university in Andhra Pradesh, claiming to be a Tamil minority institution, and then admit students from Tamil Nadu. Can you do that? That is the question which is raised, and which continues to be unanswered. And who becomes a member of the management of the minority institution? Is it those only from one State or from all States? Is it possible for an institution to claim minority status in a State when, in fact, it is managed by persons belonging to other States where they are not in minority? The question is, whether such an institution is really a minority institution. Can a non-minority in one State, a linguistic non-minority in one State, claim minority status in another? Sir, there, while discussing or dealing with the question of minority education, it is necessary to answer these questions otherwise, the law as it stands will be taken disadvantage of by these institutions which even today they are doing.

Sir, there are certain wider implications which I want to point out to this august House, and those implications are, why is this protection to the minorities? Ultimately, if the society is to be a society as a whole, then this protection to the minorities which should lead to that integration of all the sections of the society and, then, sir, I have to point out two things. One is, the international document which talks about minority rights, particularly the last declaration, namely, the Declaration of the Rights of Persons belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic

2.00 p.m.

Minorities, 1992. Incidentally, Sir, our country does not have any national or ethnic minorities. We are one people, but we have religious and linguistic minorities. But, in a preamble to this Declaration, what the United Nations say is, "Emphasising that the constant promotion and realisation of the rights of persons belonging to national, ethnic, linguistic, religious minorities as an integral part of the development of society as a whole." So, protection of minorities is an integral part of the development of the society as a whole. If we continue to segregate everything, are we going to achieve that? That is one question on the basis of this.

Sir, we have two reports. One is by the Organisation for Economic Cooperation and Development, which was reported in September, 2001, where they suggest that education system should not just be fair to minorities. They should promote a spirit of equality and tolerance among ethnic and cultural groups. Then, there is a Report on minority rights in education in Estonia, Latvia, Romania and Macedonia. It is concluded that learning apart, अलग-अलग, does not encourage living together and that, there is a danger of a strictly mono-lingual, mono-religious, mono-cultural or even mono-racial approach leading to ghettoisation of minorities.

Sir, looking from the national perspective, I believe, while talking only about minority rights, we must consider that ultimately we don't want the minorities to be ghettoised, but it should be a matter of equality and tolerance among all the communities.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Apte, you have already taken 30 minutes of the allotted time to your party. There is one more speaker from your party.

SHRI BALAVANT *alias* BAL APTE: Lastly, there is one sad aspect to this. Why is this unnecessary legislation which really is mad, or, is there any method in this madness? Sir, I believe, when I look at the performance of this Government during the last six months, I would say this. You repealed the POTA; you gave prizes to Isharat Jehan, posthumously, who was a terrorist, died along with the terrorists; you offered five per cent reservation on communal basis to the Muslims; you glossed over the threat of Bangladeshi infiltration. There is a reply given by a Minister to a House of Parliament, which is sought to be negated by a statement outside Parliament. Sir, we have an NGO claiming to be an NGO which is, in fact,

not an NGO but a private limited company with allegations that it is funded from Saudi Arabia, and the president of that NGO sits on several prestigious committees of the HRD Ministry, and their slogan is accused must be punished. So, we want the law of this country to stand on its head when the law says that an accused is innocent until he is proved to be guilty in a competent court.

†**प्रो॰ सैफुद्दीन सोज:** एनजीओ बताइए न कौन है?

†پروفیسر سیف الدین سوز : این جی او بتایئے نا کون ہے ؟

SHRI BALAVANT *alias* BAL APTE: You want to say that an accused should be punished. I believe, there is a method in this madness. *(Interruptions)*

†**प्रो॰ सैफुद्दीन सोज:** एनजीओ का नाम बताना पड़ेगा।

†پروفیسر سیف الدین سوز : این جی او کا نام بتانا پڑے گا ۔

SHRI BALAVANT *alias* BAL APTE: I believe, there is a method in this madness and this kind of an approach will not integrate anybody, but will divide the country. This you are doing only for the purposes of gaining temporarily some votes because those votes are not going to last you for long. Thank you.

श्रीमती चन्द्रकला पांडे (पश्चिमी बंगाल): माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपकी और कांग्रेस पार्टी की आभारी हूं, जिन्होंने अपने समय से पहले मुझे समय दिया, क्योंकि मुझे आज किसी एक अत्यावश्यक मीटिंग में जाना था। मैं अपने पूर्ववर्ती वक्ता के लिए कहना चाहती हूं कि जो आज इतने बड़े खतरे की बात कर रहे हैं, जो अपने खतरे का रोना रो रहे हैं, वे दूसरों के लिए खतरा बोने में सबसे आगे थे और उनकी बात सुनते हुए मुझे बार-बार यही याद आ रहा है कि जो खुद कांच के घरों में बैठे हुए होते हैं, वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। महोदय, आज हम एक अत्यंत अहम विषय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग विधेयक, 2004 पर चर्चा कर रहे हैं जिसे माननीय मानव संसाधन मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी ने पेश किया है। मंत्री जी अभी किसी कारण से बाहर चले गए हैं, मैं आशा करती हूं कि नोट ले रहे होंगे। दो मंत्री यहां मौजूद हैं, वे नोट ले रहे होंगे। मैं आशा करती हूं कि मंत्री जी वापस आ जाएंगे।

†Transliteration of Urdu Script.

एक माननीय सदस्य: कौन से नोट ले रहे हैं?

श्री आनन्द शर्मा: ये जो बोल रही हैं, उसके नोट्स ले रहे हैं। दूसरा बंगारू जी के लिए छोड़ दिया था।

श्री सुरेश पचौरी: वह बंगारू जी पर छोड़ दिया है। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती चन्द्रकला पांडे: वे ले रहे हैं और उन्हें बता देंगे। आप लोग जब मंत्री थे, आपके मंत्री हमेशा रहते हों, ऐसा नहीं होता था। इसीलिए मैंने कहा कि जो आप करते हैं, वह दूसरों से आशा कीजिए..**(व्यवधान)**...अंग्रेजी नहीं जानते हैं क्या? क्या एक ही नोट जानते हैं? कई नोट्स होते हैं। ..**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य: नोट तो एक ही होता है।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे: मैं हिन्दी की बात नहीं कर रही हूं। अंग्रेजी नहीं जानते हैं क्या?...**(व्यवधान)**...असल में इनके साथ परेशानी यही है कि ये अपने मतलब का अर्थ निकालते हैं। जिस शब्द से जो अर्थ आपको निकालना होता है, आप निकाल लेते हैं। यहां नोट्स से नोट्स है या नोट, यह आप निकाल लीजिए। इस बिल के विवरणों और कारणों का उद्देश्य और कारणों का विवरण देते हुए मंत्री जी ने बताया है कि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के एक भाग में एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग स्थापित करने का उपबंध है, जो अल्पसंख्यक व्यावसायिक संस्थानों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से सीधे संबद्ध करने की व्यवस्था करेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षा से संबंधित शिक्षाविदों, विशिष्ट नागरिकों और समुदाय के नेताओं के साथ आयोजित अनेक बैठकों में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा लम्बे समय से की जा रही मांग पर भी विचार किया गया है, जैसा मंत्री जी ने उपबंध में लिखा है। अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों में से एक मुद्दा इस संबंध में उनको प्रदान की गयी सांवैधानिक गारंटियों के बावजूद उनकी स्वयं की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें चलाने में उनके द्वारा महसूस की गयी कठिनाई का था।

[उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) पीठासीन हुए।]

मुख्य समस्या उनकी पसंद के किसी विश्वविद्यालय के साथ सहबद्धता प्राप्त करने के विषय में थी। कुछ विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में राज्य विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय अधिकारिता और अल्पसंख्यक जनसंख्या केन्द्रित होने का दृढ़ता से यह अर्थ हुआ कि संस्थाएं अपनी पसंद के विश्वविद्यालयों से संबद्ध होने का अवसर प्राप्त नहीं कर सकती थीं। इस विषय में मैं यह कहना चाहूंगी कि यद्यपि हम अध्यादेश के समर्थक नहीं रहे हैं, संसद सत्र शुरू होने ही वाला था संभव था कि इंतजार कर लेते, लेकिन इस संबंध में बड़ी गंभीरता से जिस बात को मैं महसूस कर रही थी, मैं उसे आपके साथ बांटना चाहूंगी। गुजरात और देश के कुछ भागों में अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थाओं के साथ जो कुछ घटा, खास

करके affiliation प्राप्त करने के संबंध में उन्हें जो असुविधाएं हो रही थीं, उसी के कारण माननीय मंत्री जी को यह अध्यादेश लाना ज़रूरी लगा होगा। हम उस काले अध्याय को भूल नहीं सकते जो भारत के इतिहास में सदा बदनुमा दाग के रूप में याद किया जाएगा। जब सरकारी प्रचार माध्यम चीख-चीख कर " भारत उदय" का नारा लगा रहे थे, जिसमें हर चीज़ चमक रही थी और लोगों को जबरदस्ती खुशनुमा अहसास कराया जा रहा था, लेकिन हकीकत यह थी कि देश को मध्ययुगीन अंधेरे की ओर ले जाया जा रहा था और बर्बरता, नृशंसता तथा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार अपनी चरम सीमा पर थे। देश में यह माहौल था कि एक मरी हुई गाय की कीमत जीवित मनुष्यों से अधिक सिद्ध की जाती थी और उसे पीट-पीट कर मार डाला जाता था। विधर्मी, विजातीय साबित कर जलाकर खाक करने और खुले आम ethnic cleansing की साजिश में किसी प्रकार की कोई रोकटोक नहीं थी। अगर ये सारी स्थितियां देश में पैदा नहीं हुई होतीं तो शायद मंत्री जी को इस तरह ऑर्डिनेंस के रूप में यह विधेयक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं शायर मोहसिन जैदी को quote करना चाहूंगी जिन्होंने लिखा है-

"जुम्बिशे नोक-ए-कलम ही सही खंजर के खिलाफ
कोई मैदान में आए तो सितमगर के खिलाफ।"

जो माहौल था, उसमें यह ऑर्डिनेंस लाया गया और हम उस spirit की सराहना करते हैं, जिसे spirit को मद्देनजर रखकर यह विधेयक लाया गया हैं देश में जो माहौल था, हम इस तथ्य की किसी भी रूप में अनदेखी नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूंगी कि इस विधेयक से राज्यों में शिक्षा संस्थानों की जो स्वायत्तता है, उसको खतरा हो सकता है। जिन्हें अपने राज्यों में affiliation नहीं मिलेगा, वे केंद्र से उसे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। हमने मंत्री जी से इस संबंध में पहल की थी और माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन किया है, हमें पूरी उम्मीद है कि उससे विधेयक में जो छिद्र रह गए थे, उन पर कुछ न कुछ रोक लग जाएगी। किंतु मैं यह ज़रूर कहना चाहूंगी कि कुछ पर्याप्त नियमों और नियामकों की ज़रूरत हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जहां विविध प्रकार की minorities हैं, यह विधेयक उन सबके अधिकारों की रक्षा की कोशिश करे-चाहे religious minority हो, linguistic minority हो, ethnic minority हो-जब यह बिल पास हो जाएगा तो सभी समूहों के प्रतिनिधियों को लेकर और लंबी बातचीत की ज़रूरत होगी।

महोदय, मैं यह ज़रूर जानना चाहूंगी कि क्या सभी minority groups को इससे सुविधा और सहूलियत मिलेगी? विधेयक में minority institution की परिभाषा देते हुए एक जगह और कहा गया है, जिसे मैं quote करना चाहूंगी। परिभाषा इस प्रकार है-

"अल्पसंख्यक शैक्षणिक संख्या से भिन्न कोई महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है जो अल्पसंख्यकों में से किसी व्यक्ति या व्यक्ति-समूह द्वारा स्थापित या अनुरक्षित हो।"

जब ऐसा कहा जाता है तो लगता है कि परिभाषा का दुरुपयोग किया जा सकता है। यह प्रावधान रखा जाए कि इस परिभाषा का किसी भी प्रकार दुरुपयोग न हो। दसवीं पंचवर्षीय योजना से भी मैं उद्धत करना चाहूंगी जहां लिखा हुआ है–

"पिछड़े क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों को सहायता देकर और महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े और अल्पसंख्यक समूह जैसे सीमांतक समूहों के लिए पहुंच और समानताओं में बढ़ोतरी करके शहरी और सीमांतक समूहों के अंदर उच्च शिक्षाओं के अवसरों के वितरणों में व्याप्त असमानता को कम किया जाए।"

मैं सोचती हूं कि इस लक्ष्य को पूरा करने में यह विधेयक बहुत कारगर सिद्ध होगा। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को जोड़कर उन्हें अधिक आधुनिक बनाने की भी ज़रूरत होगी। इस विधेयक के पास होने पर विभिन्न राज्यों में मौजूद अल्पसंख्यक व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों को सीधे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से संबद्ध होने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके बाद इन संस्थाओं पर राज्य सरकारों और उनके विश्वविद्यालयों का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। इससे यह सोचा जा रहा है कि केन्द्रीय विश्व-विद्यालयों से संबद्ध हो जाने के बाद अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों को बेहतर संरक्षण मिल सकेगा और इससे उनके द्वारा ली जाने वाली परीक्षा प्रणालियों का और उनको मिलने वाली डिग्रियों का और महत्व बढ़ जाएगा। महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि अभी भी बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो बहुत ही उपेक्षित दशा में हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोले जाते हैं, उन्हें पर्याप्त धनराशि भी मिलती है, लेकिन उनके रख-रखाव और उनके कार्यक्रमों पर कोई निगरानी नहीं रखी जाती है। हम जिन संस्थाओं को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से जोड़ने का प्रावधान देने जा रहे हैं, उनके रख-रखाव की जिम्मेदारी भी सरकार को पूरी तरह संभालनी होगी। मैं, यहां पर यह भी बताना चाहूंगी कि संविधान के अनुच्छेद-30 में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, अपनी परम्परा और अपनी शिक्षा के इंतजाम करने का, जो दायित्व दिया गया है, उसकी हिफाजत और रखवाली के लिए अब तक कोई सुरक्षा कवच नहीं था। यह आयोग भी सुरक्षा कवच बन पाएगा या नहीं, यह संशय का विषय है। इस बिल के और दो-तीन पहलू हैं, जिन पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। इसके साथ ही मैं यह भी चाहूंगी कि सरकार इस ओर संजीदगी से सोचे। पहली बात तो यह है कि हमारे देश में मायानोरिटी संस्थान बहुत दिनों से चल रहे हैं। महोदय, मेरा अनुरोध है कि इन इंस्टिट्यूशन्स में व्यवसायकरण पीछे के दरवाजे से न हो, इस ओर भी सरकार को ध्यान देना होगा।...(समय की घंटी)... इसके कारण हमारी शिक्षण संस्थाओं में जो बहुत भयानक स्थिति पैदा होगी, उसे रोकने का प्रावधान भी रखना होगा। मैं सरकार से गुजारिश करूंगी क्योंकि हमारे देश में शिक्षा कन्करैन्ट

लिस्ट में है, इसलिए प्रादेशिक सरकारों को भी कंफिडेंस में लिया जाना चाहिए, सरकार के लिए यह देखना भी जरूरी है। तीसरी बात यह है कि इस बिल में 6 विश्वविद्यालयों के नाम लिए गए हैं, इन्हें भी बढ़ाने की जरूरत है। यदि बिना राज्य सरकारों की मदद के इंस्टिट्यूशन्स को अनाप-शनाप सुविधाएं दी जाएंगी तो कहीं, कोई न कोई असुविधा जरूर प्रकट होगी।

महोदय, आज हमने बहुत ही जरूरी मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। हमारे देश में आज मुक्त बाजार अर्थ-व्यवस्था चल रही है, जिसमें शिक्षा भी बाजार की वस्तु बन गई है। एक जनतांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार, हर मनुष्य का मूलभूत अधिकार है, इस अधिकार से हमारी राज्य व्यवस्था और सरकार, कोई इंकार न करे। ऐसे में आज यह जरूरी है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, जो निजी संस्थान हैं, जिनके मुनाफे की प्रवृति सुरसा के आकार की तरफ बढ़ती जा रही है, उन पर किसी न किसी तरह नियंत्रण रखा जाए। उनकी बेलगाम मुनाफे की नीति पर रोक लगाई जाए, जिसके चलते हजारों प्रतिभाएं, उच्च शिक्षा के प्रांगण में जाने से रुक रही हैं। मैं अपनी अंतिम बात आधे मिनट में कहना चाहूंगी। भारत में वर्तमान अर्थतंत्र, समाजतंत्र, राजतंत्र तथा उसकी क्षेत्रीय भिन्नताओं को देखकर, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के किसी सरल समीकरण की पहचान करना अत्यंत मुश्किल है। क्यूबा के सुप्रसिद्ध कवि होजमार्ते ने कहा था कि हमारे शिक्षा संस्थानों की चर्चा वास्तविक जीवन की कर्मशालाओं के तौर पर करनी चाहिए। हमारे स्कूल और खासकर विश्वविद्यालय तभी एतिहासिक बदलाव की प्रक्रिया का अंग बनेंगे जब समाज का हर तबका मूक दर्शक नहीं, बल्कि एक उर्जस्वित सहकर्मी और सहयोगी होने के संतोषपूर्ण अहसास के साथ राजनैतिक घटनाओं की गति से जुड़ सकेगा।

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Mr. Vice-Chairman, Sir, the National Commisson for Minorities Education Institution Bill, 2004 is a laudable measure. And, I stand to welcome it. It is after a long time that justice is being sought to be afforded to the minorities in India. I am happy that this Bill came after a long debate, especially in a convention where intellectuals drawn from the entire country, from every nook and corner of India assembled for a two-day convention in July, 2004. The hon. Minister, Shri Arjun Singh, sat throughout the discussions and heard every delegate, every intellectual, and every expert with rapt attention. I was amazed; I had not seen that kind of situation before. I have been in the Parliament of India, in both Houses, for a long time. I had never seen such a vigorous debate taking place on a Bill that had to later on come to Parliament of India. I am happy today and it is my privilege to congratulate the Government for its commitment to the Common Minimum Programme, where they had promised this measure. I am especially thanking the hon. Minister for his

keen interest and for piloting this important measure before the Rajya Sabha, this time. It is a historic measure. It will be remembered long in the annals of the history of constitutional procedures and in the history of justice system, particularly justice that was required to be afforded to the minorities of India. What makes it a great privilege for the hon. Minister for Human Resource Development is that it is after 56 years of Independence that this relief, this genuine relief has been afforded, to the minorities. Although there was a provision in the Constitution of India, yet no action had been taken up to this moment in practical terms. I quote this article. It would have remained only in the Statute Book without having the opportunity of implementation. I quote section 30 of the Constitution. "All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice." This measure remained on this 'social Bible'. Our Constitution has worked well. So many amendments, umpteen number of amendments have taken place. But this provision in the Constitution of India had never been implemented so far. This is a laudable step that the hon. Minister for Human Resource Development has taken. This reflects his commitment to implement the Common Minimum Programme. This is, therefore, his privilege that he has taken this historic step of historic importance and introduced this Bill, which I hope will be passed with a majority vote. There is full justification for this Bill. I hope minority institutions will, now, be able to seek genuine relief which had been unlawfully denied to them. I will not go into the issues that were raised by my colleague from the BJP here. I will also not go into what the hon. Minister had told this House earlier how it was unlawfully denied to the minorities, when it came to recognition of their institutions; when it came to affording them relief of affiliation of their institution in this country. And, a word of mouth was much more powerful than the written orders from the Ministry of Human Resource Development. Now, I will briefly come to this Bill itself. It is a very well drafted Bill. It is very comprehensive, but brief. I congratulate the hon. HRD Minister for this also because this has happended under his close direction and supervision. I did not move any amendments because I thought the hon. Minister could take notice of what I am saying. In clause 4(1) it has been said, "A person shall not be qualified for appointment as the Chairperson unless he". And clause 4(b) says, "has been a Judge of a High Court". I would say, why it should not include a retired judge of the Supreme Court also? If we restrict to retired judges of High Court, it would not be good.

The hon. Minister may consider it; whenever there is time, for the future. This Bill has laudable features in clauses 12(2) and 12(2)(d). Society will be grateful for them because...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Mr. Soz, there is a meeting of the Speaker and I have to go there. So, with the permision of the House, can I request Mr. Fali S. Nariman to take the Chair till I come back? Do I have the approval of the House?

SOME HON. MEMBERS: Yes.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI FALI S. NARIMAN) in the Chair]

SHRI SURESH PACHOURI: Sir, I have this opportunity of congratulating him on occupying this Chair.

PROF. SAIF-UD-DIN-SOZ: Congratulations, Mr. Vice-Chairman, Sir. It is a great privilege for me particularly. Sir, I was coming to two very important provisions of the Bill, which are very laudable. Clause 12(2) says: "The Commission shall, for the purposes of discharging its fucntions under this Act, have all the powers of a civil court trying a suit and in particular, in respect of the following matters, namely." The provisions have been listed there. Then the provision in 12(d) is also very laudable. It says, "subject to the provisions of sections 123 and 124 of the Indian Evidence Act, 1872, requisitioning any public record or document or copy of such record or document from any office; "These provisions will give teeth to this Commission, otherwise, there are so many commisions, which cannot operate properly. Under clause 13, I have a suggestion. It has been provided in the Bill, "The Chairperson shall exercise such financial and administrative powers as may be vested in him by the rules made under this section: Provided that the Chairperson shall have authority to delegate such of the financial and administrative powers as he may think fit to any Member or Secretary..." I would say, 'or Secretary", may be deleted because Secretary is a different category. Member is a different category. The Chairman has to delegate. He must delegate to other Members. There are two or three Members. Secretary is an official. Today we may find that it is possible for the Secretary to carry out the orders of the Commission, but there are difficulties. So, these are very important powers. This should be delegated to the Members and not the Secretaries. These are the brief points about the Bill.

There is one more thing which I want the hon. Minister to consider. It is about Annual Reports. There are so many institutions in this country. So many hon. Members have raised this question in both the Hosues that Annaul Reports do not come. They are not forwarded in time. So, I would suggest that for the year that Annual Report is getting prepared, it must come within three months of the next year. If it is provided in the Act, then the Annual Reports will come in time. I have myself seen that the Minority Commission Reports did not come for years and we had to raise voice in the House. Therefore, at some distant date, the hon. Minister may kindly go into these suggestions. These are the brief suggestions. It is a very good measure and the Bill has been very well drafted. So, Mr. Vice-Chairman, Sir, I saw how the hon. Minister was disrupted and it was a very painful situation in my heart and mind because the Opposition Party, particularly, the BJP has a different perception of governance. I would say, in due course of time, they will have to change that perception of governance. They will have to be a national political party of a nation state. And there are so many friends sitting on those Benches, I have great respect for Shri Jaswant Singh, who, at the moment, is not here. Ultimately, Mr. Chairperson, Sir, it is the question of perception of governance. Janab Arjun Singhji represented this perception of governance mention because he has a perception of this Government. As for BJP, its perception was explained by Jaswant Singhji to a friend of his and I quote very briefly. I quote, "I also found troblesome the way Islam fit into Jaswant's worldview-or, more to the point, the way it seemed to be inherently at odds with his concept of Hindu civilization. By implication, while Parsees, Christians, and others qualified as welcome additions to the Indian melting pot...(*Interruptions*) muslims did not."

श्री ख्दनारायण पणि (उड़ीसा): सर, इस विषय के साथ इसका क्या संबंध है ...(व्यवधान) सर, जिस विषय पर यह डिबेट हो रही है, उसके साथ इसका क्या कोई संबंध है? ...(व्यवधान)

THE VOICE-CHAIRMAN (SHRI FALI S. NARIMAN): Let him finish ...(*Interruptions*)... Let him finish ...(*Interruptions*)... We are aware ...(*Interruptions*)...

†प्रो॰ सैफुद्दीन सोज: उसी पर बोल रहा हूं। ...(व्यवधान)

پروفیسر سیف الدین سوز : اسی پر بول رہا ہوں۔

†Transliteration of Urdu Script.

श्री रूद्रनारायण पणि: अगर कुछ भी बोलना है, किसी भी समय बोलना है ...(व्यवधान) इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है ...(व्यवधान)

PORF. SAIF-UD-DIN SOZ: I have great respect for Jaswantji ...(*Interruptions*).

SHRI M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI: Sir, the Member has a right.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: I did not interrupt ...(*Interruptions*)...

श्री रूद्रनारायण पणि: मैं जो कहता हूं, आपके माध्यम से कहता हूं ...(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI FALI S. NARIMAN): Please listen to him.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: "For example, in his paean to Hinduism, Jaswant noted how this most polytheistic of the world's great religions included a dizzying array of female goddesses. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI FALI S. NARIMAN) Prof. Soz, may I just tell you one thing? This debate is on a particular Bill. Therefore, I would request you ...(*Interruptions*)...

PORF. SAIF-UD-DIN SOZ: I am telling you it is a perception of governance ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI FALI S. NARIMAN): Let us not have all these dissensions ...(*Interruptions*)...

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Just one line. ...(*Interruptions*)... I will skip ...(*Interruptions*)...

"What concerned me, in hearing it from Jaswant,

प्रो॰ रामबख्श सिंह वर्मा: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, ये माननीय जसवन्त सिंह जी का नाम ले रहे हैं, उनके बारे में कुछ कहने से पहले उन्हें नोटिस देना चाहिए।

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: It was what it implied about the BJP's ideology and, therefore, about the party's approach of governance." ...(*Interruptions*)...

श्री रूद्रनारायण पणि: ये माइनोरिटी को मेजोरिटी बनाने के लिए ...(व्यवधान)... सर, अगर यह रिकॉर्ड होगा तो हम भी बोलेंगे। ...(व्यवधान)...

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Mr. Vice-Chairman, Sir, if they take their seats, I will conclude within two minutes ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI FALI S. NARIMAN): We will ask the Chairman whether it is proper for a Member to be named ...(*Interruptions*)...

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: This was what Jaswant Singhji talked to Talbot. This is reported in the book ...(*Interruptions*)... not ...(*Interruptions*)... This is connnected with the BJP's ideology of governance... *(Interruptions)*... It is in Talbot's book at Page 134...*(Interruptions)*...

PROF. R.B.S. VERMA: Has he the authority to discuss... (*Interruptions*)... Please speak on the Bill. (*Interruptions*)...

†PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: They are not prepared to listen to the truth... (*Interruptions*)...

मैं गुरू नानक की याद दिला रहा हूं, आप तशरीफ रखिए... (व्यवधान)...

پروفیسر سیف الدین سوز : میں گرونانک کی یاد دلا رہا ہوں۔ آپ تشریف رکھیے.....مداخلت.....

PROF. R.B.S. VERMA: Please speak on the Bill.

श्री रूद्रनारायण पणि: अगर गुरू नानक पर बोल रहे हैं तो गुरू तेग बहादुर पर भी बोलिए। (व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI FALI S. NARIMAN): He is concluding in four minutes.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Sir, I have quoted from Talbot's book. The BJP must understand and appreciate that we are a pluralistic society and Prime Minister and other Ministers who went abroad recently came to know visibly that India is appreciated there for its commitment to democracy, for its commitment to secularism, for its commitment to pluralism and they should understand pluralism, as explained by Jawaharlal Nehru in his great phrase, "India's unity lies in its diversity." And they are not accepting it; so, I want to tell them, understand and appreciate what I have to say on behalf of Allamah Iqbal just one couplet because you go selectively to history... (*Interruptions*)... You don't take a comprehensive view on that.

---

†Transliteration of Urdu Script.

श्री रूद्रनारायण पणि: सर, क्या इन्हें इस बिल के विषय में हम को एकजुट करने का मौका मिल गया है? सर, यह घोर आपत्तिजनक है। (**व्यवधान**)... आप हमको क्या शिक्षा देंगे।...

†**प्रो॰ सैफुद्दीन सोज:** अफसोस की बात है आपको समझ नहीं आता। (**व्यवधान**)... आप थोड़ा सा गौर करो। ...(**व्यवधान**)... थोड़ा समझने की कोशिश करो।

پروفیسر سیف الدین سوز : افسوس کی بات ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا.....مداخلت..... آپ تھوڑا سا غور کرو.....مداخلت..... تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرو۔

Mr. Vice-Chairman what Alama Iqbal said is relevant today and it was relevant that day. ...(*Interruptions*)... I recommend them to understand and appreciate *Chisti* (*Interruptions*)...

SHRI RUDRA NARAYAN PANY: He is educating the BJP. ...(*Interruptions*)...

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज: इस में क्या खराबी है? Why are crying. ...(*Interruptions*)... I will concluding by saying his couplet. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI FALI S. NARIMAN): When your Members speak, you educate the other side. ...(*Interruptions*)... You educate the other side. ...(*Interruptions*)...

†PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: This verse promotes India's unity. ...(*Interruptions*)... अगर यह खराब है तो विद्ड्रा कर लूंगा। अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो विद्ड्रा कर लूंगा।

پروفیسر سیف الدین سوز : اگر یہ خراب ہے تو وڈڈرا کرلوں گا۔ اگر آپ کو پسند نہیں آئے گا تو وڈڈرا کرلونگا۔

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI FALI S. NARIMAN): You address the Chair. ...(*Interruptions*)...

SHRI RUDRA NARAYAN PANY: He is trying to educate us. ...(*Interruptions*)...

†PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: I wish you could understand this. ...(*Interruptions*)... मि॰ वाइस चेयरमैन सर, ये जो ख्वाजा मोहम्मद चिस्ती हैं और जिनकी

†Transliteration of Urdu Script.

दरगाह पर हिंदू, मुसलमान, सिख – सब लोग जाते हैं, सर, अल्लामा इकबाल ने कहा था, उन्होंने कंट्री को याद दिलाया था, 'चिस्ती ने जिस जमीं पर पैगामे हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में इबादत का गीत गाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है।' अब आपकी मुश्किल यह है कि आप इन चीजों को एप्रेसिएट नहीं करते।

پروفیسر سیف الدین سوز : مسٹر وائس چیئرمین سر، چشتی نے جس زمیں پر، سر یہ جو خواجہ محمد چشتی ہیں اور جن کی درگاہ پر ہندو مسلمان سکھ سب لوگ جاتے ہیں۔ سر، علامہ اقبال نے کہا تھا، انہوں نے کنٹری کو یاد دلایا تھا، ''چشتی نے جس زمیں پر پیغامِ حق سنایا، نانک نے جس چمن میں عبادت کا گیت گایا، میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے'' اب آپ کی مشکل یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپیریشی ایٹ نہیں کرتے۔

I stand for India's unity. ...(*Interruptions*)... I stand for India's unity. ...(*Interruptions*)... Many, many thanks.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI FALI S. NARIMAN): Dr. Malaisamy, you are next. Now, please listen to him at least. ...(*Interruptions*)...

Let him speak. ...(*Interruptions*)... Don't indulge in this cross talk, please. Let us have some order.

DR. K. MALAISAMY (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, there may not be much to dilate for me in as much as the earlier speakers have dealt with enough, and what all I wanted to say they have already said. However, I would like to touch upon some new areas that they have left out. Sir, for anything and everything to be undertaken. ...(*Interruptions*)... He should sit here. ...(*Interruptions*)...

प्रो॰ रामबक्ष सिंह वर्मा: सर, हाउस का कनवेंशन है कि स्पीकर स्पीच देने के बाद बैठकर सुनेंगे, मगर श्री सैफुद्दीन सोज अपनी स्पीच देने के बाद चले गए हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI FALI S. NARIMAN): There is no such rule. There is a convention, but there is no such rule. Please, let us not have this cross talk.

DR. K. MALAISAMY: Two essentials are required-one should have a vision for which there should be a mission. In other words, one should

have an objective and there should be a means to achieve this objective. As far as this Bill is concerned, from the action initiative, the Bill has come in shape and it will be enacted very soon from the action aspect of it, we welcome the Bill, in as much as it is the policy of the AIADMK to go all out of support the interests of the minorities and minority institutions, particularly our great leader, who is the Chief Minister as well as the General Secretary of the Party, is very keen in protecting and promoting the interests of the Minorities and their institution. Sir, under these circumstances, we are inclined to support the Bill. But, at the same time, we have got our own reservations on how it has been brought forward. I mean the backdrop or the background, with which the Bill has been brought, and the same has been rightly highlighted by the NDA allies. I was keenly listening to the Hon. Minister when he was giving introductory remarks about the Conference of the Minorities on 3rd July, in which the hon. Prime Minister and the hon. HRD Minister were the cynosures. Sir, he was telling that a consensus was arrived at in the Conference. What has emerged has been drawn, by way of the Bill, or, the Legislation. Sir, it cannot be correct at all because in the Conference, the Prime Minister was able to say about the Bill and the National Commission for the protection of the minority educational institutions. As such the spadework, or, the desk work could have already been over. Thus the fact that they had carved out certain ideas thereafter in the conference cannot be correct. Secondly in the Conference they had invited all the secular allies of UPA and asked them specifically to send their representatives even if the leaders could not come. But, it is on record, Sir, that only representatives from the CPM and the JMM parties were present. No other party's representative was present, particularly, the BSP and the Samajwadi Party, who were claimants of protecting the interests of minorities, had not been either called, or, even if called, were not present.

SHRI SHAHID SIDDIQUI: Samajwadi Party was not invited.

DR. K. MALAISAMY: What I am trying to highlight is that the secular recipe...

SHRI ARJUN SINGH: Sir, I am trying to clarify the misconception. Only the parties recognised by the Election Commission as national parties, were called, except the BJP.

DR. K. MALAISAMY: Sir, what I am trying to dwell upon is that the

action intiated is okay, but the objective behind this is something different and it has got a hidden agenda. As attributed by others, it is more political and time serving, particularly keeping U.P. in their mind. Sir, this is one aspect.

Now, coming to the Bill, according to me, it is not adequate. It is not comprehensive. It is proposed in haste, bypassing the norms of UGC, AICTE and MCA, etc. That is my first point. My second point is that they have prescribed the qualifications for the Chairman of the National Commission. They have said that one should have been a High Court Judge. Sir, I have got the greatest respect for judiciary in which you are also involved. But, I do not know the reason why in every Bill, in every enactment, they are so enamoured for High Court Judges and Supreme Court Judges. There are umpteen numbers of retired big wigs of statutory authorities and constitutional authorities and brilliant civil servants. But why they go for High Court Judges?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI FALI S. NARIMAN): Dr. Malaisamy, you have two minutes more. Try to finish in two minutes.

DR. K. MALAISAMY: I have no problem. Sir, as far as the qualification prescribed is concerned, my point is: why High Court judges alone, and, why not the Supreme Court judges.

Sir, therefore, the provision warrants an amendment to the effect that either it should be a High Court Judge, or, even a Supreme Court Judge, or, it can be worded 'not less than the rank of High Court Judge'. It should be better for them to prefer a High Court Judge, or, a Supreme Court Judge for which there should be a scope in the provision.

Sir, my second point is that the term of the Commission has been prescribed for five years. Sir, normally in a statute like this, it will be provided that one will hold office for a period of three years, or, five years but subject to a maximum age of either 60, 65 or 70 years. Here, you have not given any maximum upper age limit at all for the Chairman, or, the Members. If that is the case, can you appoint a person of 95, or, 95 years of age? Sir, it has been a practice, to fix maximum age limit. When one grows old and old he becomes physically and mentally sick.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI FALI S. NARIMAN): There is another point of view that they also become wiser sometimes.

DR. K. MALAISAMY: Wiser cases will be very few. Serenity will set in. So, why don't you prescribe the maximum age of 65 years, or, even 70 years? *(Time bell)*. Sir, I am concluding. I will take one minute more. Normally, you will be very considerate.

Sir, coming to the functions, according to me, they have limited the functions of the National Commission. There are umpteen number of interests, rights and duties of the minority institutions where as the Bill mainly speaks about the affiliation with scheduled universities for which the recommendation, or, the view of the National Commission is final, whereas all other minor functions are advisory.

So, according to me, tomorrow, umpteen number of areas will arise to the effect when this Act, or, the enactment is silent. In such a situation, what are you going to do? Are you going in for an amendment at that time, or, are you going to appoint a new Commission? In other words, you ought to have thought about it in a comprehensive way while framing the Bill.

Sir, finally, I would like to say about the composition of Chairman and two Members. I very much like that a person, a representative from the minority institutions that too a well-informed, a desirable, competent represenative of the minority institutions should find a place in the composition of the Commission. That is my point. At the end, I thank you for having given me the opportunity to speak on this matter.

†**श्री शाहिद सिद्दिकी:** वाइस चेयरमैन साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस बिल की हिमायत में, सपोर्ट में बोल रहा हूं और मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि यह जो बिल है, यह जो कमीशन है, यह जो माइनोरिटी के एजुकेशन का मामला है, यह माइनोरिटी का मामला नहीं है, यह इस देश का मामला है और यह मेजोरिटी का मामला है, क्योंकि अगर हम माइनोरिटी को, इन 15 प्रतिशत लोगों को पिछड़ा रखेंगे, इन्हें आगे आने नहीं देंगे, तो देश की एकता और देश की जो सेहतमंद ग्रोथ है, वह रुकती है। देश में अगर हमें आतंकवाद से लड़ना है, अगर देश में पिछड़ेपन से लड़ना है, अगर देश में बैकवर्डनेस से लड़ना है, अगर देश को इक्कीसवीं शताब्दी में लाना है, अगर देश को एक सुपर पावर बनाना है तो सारे देश के लोगों को आगे लाना होगा, वह चाहे माइनोरिटी के लोग हों या मेजोरिटी के हों।

उपसभाध्यक्ष जी, सुषमा जी की बात पर मुझे और कोई एतराज नहीं था, एक छोटा-सा इतना एतराज था कि आप इसको माइनोरिटी का सवाल मत बनाइए। यह मुसलमान और क्रिश्चियन का सवाल नहीं है, यह इस देश का सवाल है, भारत को आगे ले जाने का सवाल है और इसलिए मैं

†Transliteration of Urdu Script.

आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी, अर्जुन सिंह जी को मुबारकबाद देता हूं कि वह यह बिल लाए हैं। यह पहला कदम है, छोटा-सा कदम है कि माइनोरिटी की एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया गया है। मेरा मानना यह है कि हर मसले का इलाज, जो हमारा पिछड़ापन है या जो हमारे मसायल हैं या जो आप मदरसे को लेकर बात करते हैं या आप आबादी को लेकर बात करते हैं या आप बच्चों को लेकर बात करते हैं या औरतों के सवाल पर बात करते हैं इन सारे सवालों का जो हल है वह शिक्षा है। इसलिए हमें माइनोरिटी के लोगों को शिक्षा पूरी ताकत से ज्यादा से ज्यादा देनी होगी, उन्हें शिक्षा के मैदान में आगे लाना होगा। यह हिन्दुस्तान की जरूरत है, यह माइनोरिटी की जरूरत नहीं है। यह मैं कहना चाहता हूं। लेकिन मैं साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो बिल आया है, यह जल्दी में बनाया गया है। मैं इस बिल से बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं। सोज साहब ने बहुत तारीफ की, उन्होंने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, विद्वान आदमी हैं, लेकिन मैं चूंकि इसमें नया हूं, इसलिए मुझे इसमें बहुत सारी कमियां नजर आईं। सबसे बड़ी कमी यह नजर आई है कि जब हम माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि माइनॉरिटीज दो तरह की होती हैं - एक, जो शिक्षा के मैदान में आगे हैं, ऐडवांस हैं और दूसरी, जो शिक्षा के मैदान में पीछे हैं। आज जो मसला हमारे सामने है, वह उनका है जो शिक्षा के मैदान में पीछे हैं। जब हम बात कर रहे हैं हायर ऐजुकेशन के इंस्टिट्यूशंस की, तो मुझे कहने दीजिए कि जो मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं, उनका मसला हाई स्कूल की ऐजुकेशन है। आज भी अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया इस्लामिया में, डा॰ जाकिर हुसैन कॉलेज में मुसलमान 40 प्रतिशत भी नहीं हैं, क्योंकि वे हायर ऐजुकेशन में आ ही नहीं पा रहे हैं। वे लोअर ऐजुकेशन में रुक रहे हैं। उनका ड्रॉप-आउट रेट हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है। इसलिए उनका हाई स्कूल की शिक्षा चाहिए। आप गाड़ी को घोड़े के आगे बांध रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस कमीशन का जो गैमट है, उसको आप कम्प्रिहेंसिव कीजिए, इसमें आप, जो हाई स्कूल ऐजुकेशन है, प्राइमरी स्कूल ऐजुकेशन है, उसको भी इंक्लूड कीजिए और उनकी ऐफिलिएशन का जो सवाल है, उसको भी इसमें रिजाल्व कीजिए वरना यह गुनाहे बेलज्जत होगा। ये कहेंगे कि मुसलमानों का तुष्टीकरण हो गया, माइनॉरिटीज का तुष्टीकरण हो गया, लेकिन हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, हमें उससे फायदा नहीं होने वाला है। अगर फायदा पहुंचाना चाहते हैं इस देश के हित में, तो फिर नीचे की जो एजुकेशन है, उस पर आपको ध्यान देना होगा, वहां हमें बहुत सारी दिक्कतें है।

दूसरी बात है, सर ऐफिलिएशन की। अब ऐफिलिएशन युनिवर्सिटी से मिलेगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐफिलिएशन से पहले असल मसला एन॰ओ॰सी॰ लेने का होता है, इंस्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश करने का होता है, इंस्टिट्यूशन को बनाने का होता है और वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। आज शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि किस तरीके से माइनॉरिटीज के सवाल पर फाइलों में क्या होता है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे जिंदगी के हर कदम पर; बचपन से आज तक,

एक खामोश डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा है। दिल्ली युनिवर्सिटी से गोल्ड मैडलिस्ट होने के बावजूद मुझे नौकरी लेने के लिये डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा है। मेरे बच्चों को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है- खामोश हैं, साइलेंट, सिस्टमैटिक। इसलिए मुझे मालूम है कि जब हम हाई स्कूलों को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जब हम युनिवर्सिटीज को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हमें कदम-कदम पर कितनी दिक्कत होती है। ऐफिलिएशन का सवाल तो आखिर में आता है। आखिर में आपने हमारा मसला हल करने की बात की है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें जो दिक्कतें हैं, तो रास्ते की रुकावटें हैं, उनको दूर करने के लिए यह कमीशन क्या करेगा, किस तरीके से इसको तब्दील किया जा सकता है, इस पर अर्जुन सिंह जी को बात करनी चाहिए, इस पर सोचना चाहिए और इसके लिए अमेंडमेंट्स लानी चाहिए।

मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने इसकी रिकमेंडेशन्स के बारे में कहा है कि यह कमीशन सैंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिकमेंडेशन्स देगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि माइनॉरिटीज कमीशन के हमारे चेयरमैन साहब यहां बैठे हुए हैं, माइनॉरिटीज कमीशन बड़ी उम्मीदों से बनाया गया था, उसे बड़ी हैसियत दी गई थी, आज तक चाहे इनकी सरकार रही हो या उनकी सरकार रही हो, उसकी रिपोर्ट को पार्लियामेंट तक में पेश नहीं किया गया। क्यों? क्या उसमें कोई सच्चाई है, क्या उसमें कोई ऐसी कड़वी सच्चाई है, जिस से पार्लियामेंट को भी नहीं बताना चाहते? क्या हम इस देश को कांफिडेंस में नहीं लेना चाहते? हमने माइनॉरिटीज कमीशन बनाया क्यों था? हमने माइनॉरिटीज कमीशन इसलिए बनाया था कि वह इंक्वायरी करे, जहां डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसका पता करे और उसे इस हाऊस के सामने रखे, इस देश के सामने रखे, लेकिन हमने माइनॉरिटीज कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में रखा, उसे यहां कभी हम लाए नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसको यदि स्टैट्यूटरि पोजीशन नहीं देंगे तो इसकी रिकमेंडेशंस का भी वही हश्र होगा जो माइनॉरिटीज कमीशन की रिपोर्ट का आज तक होता आया है।

شری شاہد صدیقی (اتر پردیش): وائس چیئرمین صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ میں اس بل کی حمایت میں، سپورٹ میں بول رہا ہوں اور میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بل ہے، یہ جو کمیشن ہے، یہ جو مائنارٹی کے ایجوکیشن کا معاملہ ہے، یہ مائنارٹی کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس دیش کا معاملہ ہے اور یہ میجورٹی کا بھی معاملہ ہے۔ کیوں کہ اگر ہم مائنارٹی کو، ان ۱۵ فیصد لوگوں کو پچھڑا رکھیں گے، انہیں آگے آنے نہیں دیں گے، تو دیش کی ایکتا اور دیش کی جو صحت مند گروتھ ہے، وہ رکتی ہے۔ دیش میں اگر ہمیں آتنک واد سے لڑنا ہے، اگر دیش میں پچھڑے پن سے لڑنا ہے، اگر دیش میں بیک ورڈ سے لڑنا ہے، اگر دیش کو اکیسویں صدی میں لانا ہے، اگر دیش کو ایک سپر پاور بنانا ہے تو سارے دیش کے لوگوں کو آگے لانا ہوگا، وہ چاہے مائنارٹی کے لوگ ہو یا میجورٹی کے ہوں۔

†Transliteration of Urdu Script.

آپ سبھا اڈیکش جی، سشما جی کی بات پر مجھے اور کوئی اعتراض نہیں تھا، ایک چھوٹا سا اتنا اعتراض تھا کہ آپ اس کو مائنارٹی کا سوال مت بنایئے۔ یہ مسلمان اور کرسچن کا سوال نہیں ہے، یہ اس دیش کا سوال ہے، بھارت کو آگے لے جانے کا سوال ہے اور اس لئے میں آپ کے مادھیم سے مانئے منتری جی، ارجن سنگھ جی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ یہ بل لائے ہیں۔ یہ پہلا قدم ہے، چھوٹا سا قدم ہے کہ مائنارٹی کی ایجوکیشن کی طرف دھیان دیا گیا ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ہر مسئلے کا علاج، جو ہمارا پچھڑا پن ہے یا جو ہمارے مسائل ہیں یا جو آپ مدرسے کو لیکر بات کرتے ہیں یا آپ آبادی کو لیکر بات کرتے ہیں یا آپ بچوں کو لیکر بات کرتے ہیں یا عورتوں کے سوال پر بات کرتے ہیں، ان سارے سوالوں کا جو حل ہے وہ شکشا ہے۔ اس لئے ہمیں مائنارٹی کے لوگوں کو شکشا پوری طاقت سے زیادہ زیادہ دینی ہوگی، انہیں شکشا کے میدان میں آگے لانا ہوگا۔ یہ ہندوستان کی ضرورت ہے، یہ مائنارٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ لیکن میں ساتھ ہی یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بل آیا ہے، یہ جلدی میں بنایا گیا ہے۔ میں اس بل سے بہت زیادہ خوش نہیں ہوں۔ سوز صاحب نے بہت تعریف کی، انہوں نے بہت دھیان سے پڑھا ہوگا، وکیل آدمی ہیں، لیکن میں چونکہ اس میں نیا ہوں، اس لئے مجھے اس میں بہت ساری کمیاں نظر آئیں۔ سب سے بڑی کمی یہ نظر آئی ہے کہ جب ہم مائنارٹیز کی بات کر رہے ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مائنارٹیز دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک جو شکشا کے میدان میں آگے ہے، ایڈوانس ہے اور دوسری جو شکشا کے میدان میں پیچھے ہے۔ آج جو مسلمہ ہمارے سامنے ہے، وہ ان کا ہے جو شکشا کے میدان میں پیچھے ہیں۔ تو جب ہم بات کر رہے ہیں ہائر ایجوکیشن کے انسٹی ٹیوشنس کی، تو مجھے کہنے دیجئے کہ جو مسلم مائنارٹیز ہے، اس کا مسئلہ ہائی اسکول کی ایجوکیشن ہے۔ آج بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں، ڈاکٹر ذاکر حسین کالج میں مسلمان سٹوڈنٹس بہت نہیں ہیں کیونکہ وہ ہائر ایجوکیشن میں آ ہی نہیں پا رہے ہیں، وہ لوور ایجوکیشن میں رک رہے ہیں، ان کا ڈراپ آؤٹ ریٹ ہندوستان میں سب سے زیادہ ہے۔ اس لئے ان کو ہائی اسکول کی شکشا چاہئے۔ آپ گاڑی کو گھوڑے کے آگے باندھ رہے ہیں۔ اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کمیشن کا جو گیمٹ ہے، اس کو آپ کمپریہنسو کیجئے، اس میں آپ، جو ہائی اسکول ایجوکیشن ہے، پرائمری اسکول ایجوکیشن ہے، اس کو بھی انکلوڈ کیجئے اور انکی affiliation کا جو سوال ہے، اس کو بھی اس میں resolve کیجئے، ورنہ یہ گناہ بے لذت ہوگا۔ یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کا تشٹی کرن ہو گیا، مائنارٹی کا تشٹی کرن ہو گیا، لیکن ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔

اگر فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اس دیش کے حق میں، تو پھر نیچے کی جو ایجوکیشن ہے، اس پر آپ کو دھیان دینا ہوگا، وہاں ہمیں بہت ساری دقتیں ہیں۔

دوسری بات ہے سر، affiliation لی۔ اب affiliation یونیورسٹی سے ملے گا، بہت اچھی بات ہے، لیکن affiliation سے پہلے اصل مسئلہ این او سی لینے کا ہوتا ہے، انسٹی ٹیوشن کو اسٹیبلش کرنے کا ہوتا ہے، انسٹی ٹیوشن کو بنانے کا ہوتا ہے اور وہاں پر بہت زیادہ دقتیں ہیں۔ آج شکشا منتری جی نے بتایا کہ کس طریقے سے مائنارٹیز کے سوال پر فائلوں میں کیا ہوتا ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، لیکن مجھے زندگی کے ہر قدم پر، بچپن سے آج تک، ایک خاموش ڈسکریمینیشن کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دہلی یونیورسٹی سے گولڈ میڈلسٹ ہونے کے باوجود مجھے نوکری لینے کے لئے ڈسکریمینیشن کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میرے بچوں کو ڈسکریمینیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خاموش ہیں، سائلنٹ، سسٹمیٹک۔ اس لئے مجھے معلوم ہے کہ جب ہم ہائی اسکولوں کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم یونیورسٹیز کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قدم قدم پر کتنی دقتیں ہوتی ہیں۔ affiliation کا سوال ہے تو آخر میں آتا ہے۔ آخر میں آپ نے ہمارا مسئلہ حل کرنے کی بات کی ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لئے ہمیں جو دقتیں ہیں، جو راستے کی رکاوٹیں ہیں، ان کو دور کرنے کے لئے یہ کمیشن کیا کرے گا، کس طریقے سے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس پر ازجن سنگھ جی کو بات کرنی چاہیئے۔ اس پر سوچنا چاہئے اور اس کے لئے امینڈمینٹ لانی چاہئے۔

میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اس کی recommendations کے بارے میں کہا ہے کہ یہ کمیشن سینٹرل گورنمنٹ کو اپنی recommendations دیگا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مائنارٹیز کمیشن کے ہمارے چیئرمین صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مائنارٹیز کمیشن بڑی امیدوں سے بنایا گیا تھا، اسے بڑی حیثیت دی گئی تھی، آج تک چاہے انکی سرکار رہی ہو یا اُن کی سرکار رہی ہو، اس کی رپورٹ کو پارلیمنٹ تک میں پیش نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ کیا اس میں کوئی سچائی ہے، کیا اس میں کوئی ایسی کڑوی سچائی ہے، جسے یہ پارلیمنٹ کو بھی نہیں بتانا چاہتے؟ کیا ہم اس دیش کو confidence میں نہیں لینا چاہتے؟ ہم نے مائنارٹیز کمیشن بنایا کیوں تھا؟ ہم نے مائنارٹیز کمیشن اس لئے بنایا تھا کہ وہ انکوائری کرے، جہاں ڈسکریمینیشن ہو رہا ہے، اس کا پتہ کرے اور اسے اس ہاؤس کے سامنے رکھے، اس دیش کے سامنے رکھے، لیکن ہم نے مائنارٹیز کمیشن کی رپورٹ کو ٹھنڈے بستے میں رکھا، اسے یہاں کبھی ہم لائے نہیں۔ اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو اگر اسٹے ٹیوچری پوزیشن نہیں دیں گے تو اس کی recommendations کا بھی وہی حشر ہوگا جو مائنارٹیز کمیشن کی رپورٹ کا آج تک ہوتا آیا ہے۔

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI FALI S. NARIMAN) Mr. Siddiqui, you have got two minutes.

SHRI SHAHID SIDDIQUI: Sir, please let me continue, because I am talking on specific points.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI FALI S. NARIMAN): Right, right, please continue.

†श्री शाहिद सिद्दिकी: कमीशन के मैम्बर्स की तादाद इसमें सिर्फ 3 रखी गई है। मैं कहना चाहूंगा मंत्री जी से कि इसे आप कम से कम 7 रखिए और इसमें माइनॉरिटीज ऐजुकेशनल इंस्टिट्यूशन्स के कम से कम 3 नुमाइंदे होने चाहिए, जिनको मालूम हो कि ग्राउंड लेवल पर उनको क्या डिफिकल्टीज होती हैं इंस्टिट्यूशन्स को चलाने में और ऐफिलिएशन देने में। वे जितना दर्द को समझते है। जो जूता पहनता है, वहीं जानता है कि तकलीफ कहां होती है। इसलिए आप सात सदस्य कीजिए और माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के कम से कम तीन नुमाइंदे इसमें रखे जाएं, इसकी बहुत जरूरत है। मैं इसमें जाना नहीं चाहता, मंत्री जी ने भी कहा, और लोगों ने भी सवाल उठाया। जुलाई में एक कॉन्फरेंस बुलाई गई थी, उसमें समाजवादी पार्टी को बाहर रखा गया। भाजपा को भी बाहर रखा गया। उनके नुमाइंदे भी नहीं बुलाए गए।.....(व्यवधान) कोई बात नहीं, हमें भी नहीं बुलाया गया। ठीक है, आप एक साथ रखिए, लेकिन मुझे एक बात बताइए। मैं .....(व्यवधान)

شری شاہد صدیقی: کمیشن کے ممبرس کی تعداد اس میں صرف ۳ رکھی گئی ہے۔ میں کہنا چاہوں گا منتری جی سے کہ اسے آپ کم سے کم ۷ رکھئے اور اس میں مائنارٹی ایجوکیشن انسٹی ٹیوشنز کے کم سے کم ۳ نمائندے ہونے چاہئیں، جن کو معلوم ہو کہ گراؤنڈ لیول پر ان کو کیا difficulties ہوتی ہیں۔ انسٹی ٹیوشنز کو چلانے میں اور affiliation دینے میں۔ وہ جتنا درد کو سمجھتے ہیں۔ جو جوتا پہنتا ہے، وہیں جانتا ہے کہ تکلیف کہاں ہوتی ہے۔ اس لئے آپ سات سدسئے کیجئے اور مائنارٹی ایجوکیشن انسٹی ٹیوشن کے کم سے کم تین نمائندے اس میں رکھے جائیں، اس کی بہت ضرورت ہے۔ میں اس میں جانا نہیں چاہتا، منتری جی نے بھی کہا، اور لوگوں نے بھی سوال اٹھایا۔ جولائی میں ایک کانفرنس بلائی گئی تھی، اس میں سماج وادی پارٹی کو باہر رکھا گیا۔ بھاجپا کو بھی باہر رکھا گیا۔ ان کے نمائندے بھی نہیں بلائے گئے۔ ...مداخلت... کوئی بات نہیں، ہمیں بھی نہیں بلایا گیا۔ ٹھیک ہے، آپ ایک ساتھ رکھئے، لیکن مجھے ایک بات بتایئے۔ میں...مداخلت...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI FALI S. NARIMAN): Do not answer him you do not have to answer him.

†Transliteration of Urdu Script.

†**श्री शाहिद सिद्दिकी:** सर, मैं एक नोन एडीटर हूं और माइनॉरिटीज की एजुकेशन से जुड़ा रहा हूं। मेरा पूरा जीवन उनकी शिक्षा व सोशल डवैलपमैंट के लिए समर्पित रहा है। लेकिन मेरा नाम भी काटा गया, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी से था। इस तरह से यदि भेदभाव होगा,यदि इसी तरह का रवैया रहेगा, तब मैं इन लोगों से कहना चाहूंगा कि यदि ईमानदारी से आप काम करेंगे, तब उसका फायदा आपको ही मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। किन्तु यदि आप इस तरह से माइनॉरिटी के सवाल पर, एजुकेशन के सवाल पर, देश के सवाल पर, भेदभाव की राजनीति करेंगे, तब उससे लम्बे समय में आप कोई प्वांइट्स स्कोर पर लेंगे, बहुत खुश हो जाएंगे कि हमने आपको भाजपा के साथ जोड़ दिया, लेकिन उससे आपको फायदा होने वाला नहीं है। (व्यवधान) ये राजनैतिक बातें कहती हैं के आप डवैलपमैंट का कुछ काम नहीं कर सकते। आखिर में, मैं कहना चाहूंगा कि अल्टीमेटली माइनॉरिटीज हों, पिछड़े हों, कमजोर हों, अगर हमें उन सभी को आगे लाना है, उन्हें उनकी जगह दिलवानी है, तब सिर्फ कमीशन बनाने से और माइनॉरिटी की बात करने से यह नहीं होगा। हमें एफरमेटिव ऐक्शन की एक स्कीम बनानी होगी। राजनैतिक तौर पर हमें एफरमेटिव ऐक्शन की तरफ जाना होगा और जिस तरह से इंग्लैंड में रेशियल सोशल इक्वैलिटी कमीशन है, उस अन्दाज पर हमें काम करना होगा। जो इस तरह का कमीशन होता है जो एफरमेटिव ऐक्शन को लेकर चलता है, व यह देखता है कि किसी इलाके में अगर माइनॉरिटी 20 प्रतिशत है तो वहां पर स्कूलों में 20 प्रतिशत क्यों नहीं है? फैक्ट्रियों में 20 प्रतिशत क्यों नहीं है? अगर नहीं है, उसके कारणों को जानता है और कारण जान कर उसे दूर करने की कोशिश करता है। उन इन्स्टीट्यूशंस से, उन रोजगार देने वालों से, सवाल करता है कि तुम्हारे यहां माइनॉरिटीज का रिप्रैजेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है। इस प्रकार का रेशियल और सोशल इक्वैलिटी कमीशन अमरीका में है, इंग्लैंड में है, कनाडा में है और ऑस्ट्रेलिया में है। हिन्दुस्तान में भी इस तरह के कमीशन की जरूरत है क्योंकि जब तक माइनॉरिटी के लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, तब तक वे आगे नहीं आ पाएंगे। वे उच्च शिक्षा की ओर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि इस पूरे सदन को सोचना चाहिए कि माइनॉरिटी और मेजौरिटी के इस जाल से निकल कर हम इस कॉन्सेप्ट पर आएं के एफरमेटिव ऐक्शन हो। एफरमेटिव ऐक्शन कैसे हो, यह देखने की बात है क्योंकि एफरमेटिव एक्शन ही इस मुल्क के मसलों का इलाज है।...(व्यवधान) आप अच्छी बात की सपोर्ट नहीं करें, इस में आपकी परेशानी है। यदि आप सही बात का समर्थन नहीं करते हैं, आप सिर्फ राजनीति करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं की इसका नुकसान आपको ही होगा। हम राजनीति नहीं करते हैं। आपने हमें नहीं बुलाया फिर भी हम इस बिल का समर्थन करते हैं। हम इस बिल को सही नहीं मानते हैं फिर भी हम इस बिल का समर्थन करते हैं, क्योंकि हम राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। हम पॉजिटिव एफरमेटिव एक्शन में विश्वास करते हैं। धन्यवाद।

---

†Transliteration of Urdu Script.

श्री एस॰ एम॰ लालजन बाशा (आन्ध्र प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, अर्जुन सिंह जी माइनॉरिटीज के लिए जो बिल ले कर आए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं और उसके साथ ही साथ, मैं उनकी बहुत ही इज्जत करता हूं, क्योंकि 1991 में, जब मैं लोक सभा में था, तब वे एच.आर.डी मिनिस्टर थे। तब वे माइनॉरिटीज के बहुत करीब भी थे। लेकिन आज मुझे अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है, क्योंकि उच्च न्यायालय के इलैवन जजेज बैंच के द्वारा, माइनॉरिटीज की शिक्षा के बारे में इतना स्पष्ट डायरैक्शन सरकार को मिला है। उस उच्च न्यायालय के डायरैक्शन से भी, हिन्दुस्तान में माइनॉरिटीज के लिए क्या करना है, आजादी के 56 वर्ष पश्चात भी, आज कांग्रेस वालों ने आंख खोली है, फिर भी देर आयद, दुरुस्त आयद। आज श्री अर्जुन सिंह जी से मैं यही पूछना चाहता हूं के हिन्दुस्तान में आजादी के बाद तकरीबन 35 प्रतिशत मुसलमान स्नातक थे। 25 परसेंट गवर्नमेंट के जॉब्स में थे। उसके बाद आज जब हम लोग देखते हैं तो वन परसेंट भी मॉयनारिटी के ग्रेज्युएटस आज हिन्दुस्तान में नहीं हैं। आज एजुकेशन में ले लें और जॉब्स में देखेंगे तो वन परसेंट भी नहीं हैं। हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा हुकूमत कांग्रेस की रही है। कांग्रेस के रूल में हम लोग देख सकते हैं कि मॉयनारिटी को क्या मिला है और क्या नहीं मिला है। आंध्र प्रदेश एक एक्जैंपल है, 1995 में जब चन्द्रबाबू नायडु साहब चीफ मिनिस्टर बने, उससे पहले आंध्र प्रदेश में सिर्फ 29 इंजीनियरिंग कॉलेज थे जिसमें से सिर्फ दो इंजीनियरिंग कॉलेज मॉयनारिटी के लिए थे। उनके 9 साल के पूरे शासनकाल में 238 इंजीनियरिंग कॉलेजज में से 31 कॉलेज देने का काम हुआ। मैं ऐसा इसलिए बोलता हूं क्योंकि जिस रूलर की नीयत अच्छी रहती है तो उसकी सोच भी अच्छी रहती है। आप यहां बैठे हैं और रूल करते हैं। लेकिन तुम्हारी नीयत में आज भी शक है। आज मुसलमानों ने कांग्रेस को दोस्त समझा है। लेकिन जिनको दोस्त नहीं समझा उनके पीरियड मे एन॰डी॰ए॰ की हुकूमत में जितने कॉलेजज की परमिशन मिली है, वह हम लोग देखते हैं। आज यहां मुरली मनोहर जोशी जी बैठे हैं। मैं आज उनको बधाई देता हूं कि उनके पीरियड में कॉलेजिज के लिए माइनॉरिटी के लिए जो काम हुआ है वह हिन्दुस्तान में अन्य किसी हुकूमत में नहीं हुआ है। खुसुसन आंध प्रदेश में नहीं बल्कि कश्मीर में भी काम हुआ है, उस संबंध में वहां के चीफ मिनिस्टर साहब बोले हैं। जितना इनको पैसा दिया है, कभी हम लोगों को इतना पैसा नहीं मिला है, क्योंकि नीयत साफ है। आप कॉइन की एक साइड देख रहे हैं, दूसरी साइड नहीं देख रहे हैं। आज काइन के दो साइड में मुसलमानों को* आज तक हिन्दुस्तान में जो काम हुआ है, सर.....(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI FALI S. NARIMAN): That word will be expunged. Just one minute. Mr. Basha, there was a word which you uttered. You withdraw that word.

श्री एस॰ एम॰ लालजन बाशा: अच्छी बात है, सर। आज उसमें कुछ भी.....(व्यवधान)

SHRI SHAHID SIDDIQUI: Sir, that stands for wise people.

*Expunged as ordered by the chair..

3.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI FALI S. NARIMAN): That word is withdrawn.

श्री एस॰ एम॰ लालजन बाशा: जब से आजादी आई है हिन्दुस्तान में 226 मेडिकल कॉलेज हैं उनमें से सिर्फ 6 कॉलेज मुसलमानों के लिए है। तकरीबन 22 कॉलेज क्रिश्चियनों के लिए हैं, बाकी के सभी के लिए हैं। सर, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज इसी से मालूम हो रहा है, आंध्र में एक भी डेन्टल कॉलेज मुसलमानों के लिए नहीं है। आजादी के बाद आज जितना भी है, क्योंकि मैं .....(**व्यवधान**) नारायणसामी जी, यह सच्चाई है क्योंकि आपको कड़वा लगता है, क्योंकि आजादी के बाद 40 साल हुकूमत की है आपने। आपकी हुकूमत की वजह से आज मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं दिल से, पार्टी से हटकर, सब से अपील कर रहा हूं कि हिन्दुस्तान यदि तरक्की कर रहा है या करेगा तो मॉयनोरिटी को साथ लेकर और उनको तालीम देने का काम सब लोगों को करना है, क्योंकि आज बगैर तालीम के हिन्दुस्तान के फॉरेन रिजर्व जितने बढ़े हैं, जो आप बोल रहे हैं, वह गल्फ में जाकर हमारे मुसलमान भाई, जो पैसा भेज रहा है, आज उसी के कारण हैं।

[उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) पीठासीन हुए]

आप 25 साल के रिजर्व बैंक का खाता देखो, कितना पैसा है, जो गल्फ से आता है। इसलिए सर, यह चाहता हूं कि मॉयनोरिटी के एजुकेशन के लिए जितना काम चन्द्रबाबू नायडु साहब ने किया है और उससे पहले जब एन॰टी॰ रामाराव जी 1983 में हुकूमत में आए तो उस समय उन्हीं के शासन के दौरान मॉयनोरिटी फाइनेंस कारपोरेशन पहली दफे हिन्दुस्तान में हमारी स्टेट से शुरू हुआ था। एन॰टी॰ रामाराव की नियत और चन्द्रबाबू की वजह से आज आन्ध्र प्रदेश में कम्युनल राइट नहीं हुए हैं। जो-जो रूलर बैठता है, जो रूलर सही रूल करता है वह सब को लेकर चलता है। आज मैं फिर एक बार एन.डी.ए. की सरकार के दौरान हमारी यूनिवर्सिटीज के लिए जो काम हुआ है सर, ये लोग अभी इस बिल से उसकी बाउंड्री फिक्स करने वाले हैं। इस बिल से बाउंड्री फिक्स हो रही है। डा. मुरली मनोहर जोशी जी के समय में बाउंड्री खोल दी गई है। आप तालीम को फ्री करें। उन्होंने वीमैन्स के लिए आंध्र प्रदेश में इंजीनियरिंग कालेज देने का काम किया है। यह सच्चाई है। उनकी नीयत साफ है। लेकिन आज इनकी नीयत में खोट है। ये छह यूनिवर्सिटीज़ लेकर के आये हैं। सर, इन छह यूनिवर्सिटीज़ का काम क्या है? पूरे हिन्दुस्तान में ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): आपके बोलने का टाइम खत्म हो गया। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰एम॰ लालजन बाशा: सर, जब माइनारिटीज़ को एजुकेशन देना है, तो माइनारिटीज़ की एजुकेशन के लिए इतने रूल्स रखने की जरूरत नहीं है। सर, मैं मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता

हूं कि स्वीमिंग पूल में तैरने के लिए माइनारिटीज़ को खाली कालेज देने का काम किया है कि इसमें खाली तैरो। वह उसमें तैरेगा या डूबेगा, उनको तो मालूम नहीं है। इसमें परमिशन देने का काम यही है। मैं माननीय अर्जुन सिंह जी से पूछ रहा हूं कि आप इसके लिए कौन-सा फंड दे रहे हैं? आप इस बिल के पीछे माइनारिटीज़ की एजुकेशन को स्ट्रैंथन करने कि लिए कितना फंड दे रहे हैं? आपने खाली तैरने की परमिशन दे दी है। चंद दिन वह तैरेगा और उसके बाद वह कालेज सही नहीं चलेगा, वह फिर डूब जायेगा। माइनारिटीज़ के बच्चों को अच्छी तालीम मिलनी चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बतायें कि कितना फंड आप इसके लिए दे रहे हैं, आप कितना पैसा माइनारिटीज़ पर खर्च करने के लिए तैयार हैं? मैं इसके बारे में एक बात कह रहा हूं कि यहां हमारा सेंट्रल वक्फ काउन्सिल है। सेंट्रल वक्फ काउन्सिल को माइनारिटीज को एजुकेशन के लिए फंड दिया जाता है। गवर्नमेंट आफ इंडिया से 1972 में इसको ग्रांट मिलनी शुरू हुई थी। आज 32 साल हो गये, इन 32 सालों में, हिन्दुस्तान के पूरे मुसलमानों के लिए सेंट्रल वक्फ काउन्सिल को 30 करोड़ रुपया दिया गया है। यह सब* है। आज भी आपकी नीयत साफ़ है? ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): I don't think that this is a parliamentary word. ...(*Interruptions*)... Listen to me. ...(*Interruptions*)... Listen to me. Anything 'unparliamentary' will not go on record. The word* is not a parliamentary word. Please don't use that word.

श्री एस॰ एम॰ लालजन बाशा: सर, हमारे साथ जो हुआ है, वही हम कह रहे हैं। ...(व्यवधान)...

उससभाध्यक्ष (श्री संतोष बागडोदिया): *अनपार्लियामेंट्री वर्ड है। इसलिए यह रिकार्ड में नहीं जायेगा।

श्री एस॰ एम॰ लालजन बाशा: सर, नहीं, नहीं, * का मतलब है, जो* हुआ है। हम लोग जा* पाये हैं। ...(व्यवधान)...

उससभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): *सही नहीं है। आपने कहा कि *दिया है। ...(व्यवधान)... whatever he had said, I have said, "If it is 'unparliamentary', it will not go on record."

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सर, * अनपर्लियामेंट्री शब्द नहीं है। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): ठीक है, वह अनपर्लियामेंट्री वर्ड है, तो रिकार्ड में नहीं जायेगा। ...(व्यवधान)...

---

*Expunged as ordered by the chair..

श्री एस॰ एम॰ लालजन बाशा: सर, मदरसों के लिए...।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): अच्छा, आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है।. ..(व्यवधान)...

श्री एस॰ एम॰ लालजन बाशा: जब उनको तालीम नहीं मिली है, तब वे सब मदरसों की तरफ गये हैं। (.. समय की घंटी ..) मदरसों में बच्चे इसलिए गये हैं, क्योंकि उन्हें तालीम ही नहीं दी गई है। मैं डा॰ जोशी जी को मुबारकबाद देता हूं कि आज उन्होंने हमारी कम्युनिटी के लिए रास्ता खोला है। उन्हीं मदरसों में डा॰ मुरली मनोहन जोशी जी ने अच्छा माहौल बनाया है। उनमें माडर्नाइजेशन किया है..।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): Excuse me. एक मिनट। एक मिनट। आप सुनते ही नहीं हैं। ...(व्यवधान)... if you don't listen to me, nothing will go on record. ...(*Interruptions*)... Why don't you listen to me? ...(*Interruptions*)... Please bear with me. I want to clarify that* is an unparliamentary word. Anyway, you complete it now. This is the last sentence; you please complete it.

श्री एस॰ एम॰ लालजन बाशा: सर, दिल जला है, तो कुछ भी हम बोल सकते हैं। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन पर्लियामेंट में नहीं बोल सकते हैं। अगर बोलेंगे, तो रिकार्ड में नहीं जायेगा। ...(व्यवधान)...

श्री एस॰ एम॰ लालजन बाशा: सर, हम 56 साल से पिस रहे हैं, इसलिए आज हमें भड़ास तो निकालने दो। चाहे* से ही ये लोग हुकूमत में आये हैं। लेकिन ये ज्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं। हरेक आदमी को मालूम है कि कौन से पीरिएड में, किन्होंने कितना काम किया है। जो स्टेट चलाते हैं, वे मुसलमानों के दर्द को समझते हैं। (... समय की घंटी ...) लोगों को क्या दर्द है, ये उनके दर्द को नहीं समझते हैं। इनकी हुकूमत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): अच्छा, अब आप खत्म कीजिए।

श्री एस॰ एम॰ लालजन बाशा: सर, आज मुसलमानों के लिए ..(व्यवधान)... सर, हिन्दुस्तान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी माइनारिटीज़ के लिए ..(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): मौलाना ओबैदुल्लाह खान आजमी अब आप बोलिए। ...(व्यवधान)...

श्री एस॰ एम॰ लालजन बाशा: उनके प्रोग्रेस के लिए...

*Expunged as ordered by the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): No; you can't continue like this. You have taken double the time. ...(*Interruptions*)... This is not fair. Nothing will go on record.* अनपार्लियामेंट्री वर्ड है। ...(व्यवधान)...

श्री एस॰ एम॰ लालजन बाशा: **

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Now, nothing will go on record.

श्री एस॰ एम॰ लालजन बाशा: **

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Nothing will go on record if you insist on speaking like this.

श्री एस॰ एम॰ लालजन बाशा: **

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): I am telling you that you have taken double the time. Nothing will go on record.

श्री एस॰ एम॰ लालजन बाशा: **

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): No, please stop him. He must learn the manners. ...(*Interruptions*)...

श्री एस॰ एम॰ लालजन बाशा: **

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Nothing is going on recrod now. Mr. Azmi.

श्री एस॰ एम॰ लालजन बाशा: **

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Sir, he has concluded. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): It is my ruling. My ruling is final. I do not want him to continue.

श्री एस॰ एम॰ लालजन बाशा: **

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सर, एक अकलियत का मेम्बर बोल रहा है। आप उसको बोलने नहीं दे रहे हैं। ...(व्यवधान)... एक छोटी पार्टी का सदस्य है। माइनारिटी का मेम्बर है, उसको

---

*Expunged as ordered by the chair.
**Not recorded.

बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)... यह क्या है? आनन्द शर्मा जब बोले तो एक मिनट का तीन सौ सैकेंड होता है। एक अकलियत का मैंबर बोल रहा है तो उसे रोक दिया जाता है। ...(व्यवधान)...

श्री तारिक अनवर: क्या बताती है अकलियत की आवाज? ...(व्यवधान)...

श्री शहिद सिद्दिकी: अकलियत की आवाज़ दबा दी जाती है। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): मौलाना औबेदुल्लाह खान आज़मी।

†**मौलाना औबेदुल्लाह खान आज़मी:** मोहतरम वाइस चेयरमैन साहब, अकलियत की आवाज़ इंशा-अल्लाह कभी नहीं दबेगी, उसकी सीधी मिसाल यह है कि सुबह से लेकर शाम तक सबसे ज्यादा अकलियत के नुमाइंदे अहलुवालिया साहब इस हाउस में बोलते हैं। इसलिए अकलियत की आवाज़ नहीं दबने वाली है, बेफिक्र रहिए।

مولانا عبیداللہ خان اعظمی "مدھیہ پردیش": محترم وائس چیرمین صاحب، اقلیت کی آواز انشاء اللہ کبھی نہیں دبے گی، اس کی سیدھی مثال یہ ہے کہ صبح سے لیکر شام تک سب سے زیادہ اقلیت کے نمائندے اہلووالیہ صاحب اس ہاؤس میں بولتے ہیں۔ اس لئے اقلیت کی آواز کبھی نہیں دبنے والی ہے، بے فکر رہئے۔

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): अच्छा आप इधर कहिए।

†**मौलाना औबेदुल्लाह खान आज़मी:** सर, नैशनल कमीशन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीटयूशन बिल, 2004 इस वक्त अपर हाउस में ज़ेरे-बहस है। मैं वज़ीर-ए-तालीम, जनाब अर्जुन सिंह साहब को अपने दीगर साथियों की तरफ से यह मुबारक कदम उठाने पर मुबारकबाद दे रहा हूं इस बिल की सख्त जरूरत थी। यह बिल हिन्दुस्तान के पसामान्दा लोगों की तालीम के हुसूल के लिए रास्ता हमवार करेगा और असल मकसद की तरफ मुल्क की बहुत बड़ी अकसरियती आबादी को, जिसको इत्तेफाक से अकतलयती आबादी कहते-कहते लोग थकते नहीं हैं, ले जाएगा। तालीम के मैदान में किसी भी कम्युनिटी का पिछड़ना सिर्फ उसके पिछड़ने की अलामत नहीं होती है बल्कि वह जिस समाज में रहता है, जिस मुल्क में रहता है, जिस माहौल में रहता है और जिस आबो-हवा में रहता है, ये सारी की सारी चीज़ें उससे मुतासिर होती हैं किसी भी मुल्क की आवाम अगर पढ़ी-लिखी हे तो वह मुल्क तालीमी कदरों की बुनियाद पर पूरी दुनिया में अपना इज्जत भरा हुआ मकाम रखता है। किसी भी दरख्त की शाख अगर हरी-भरी है और उसी दरख्त की कोई शाख सूख रही हो तो माली, चमन का सरपरस्त इस बात की फिक्र में रहता है कि दरख्त की खूबसूरती को किसी ऐतबार

†Transliteration of Urdu Script.

से देखने के लिए बर्बाद न होने दिया जाए ओर लोग उस दरख्त की खूबसूरती को हर ऐतबार से हुस्न-ए-नज़र से देखें। हमारा हिन्दुस्तान एक चमन की हैसियत रखता है। जिस बात को हमारे बुजुर्गों ने कहा था, हमारे आज के समझदार लीडर कहते हैं, आने वाले दौर की पैदा होने वाली नस्लें कहती रहेंगीं हिन्दुस्तान मुख्तलिफ कल्चर का मुल्क है, मुख्तलिफ संस्कार का मुल्क है, मुख्तलिफ तहज़ीबों का मुल्क है, मुख्तलिफ आस्थाओं और अकीदों का मुल्क है, इस मुल्क की अनेकता में एकता का जो दर्शन दुनिया देखती है, इसका कोई जवाब दुनिया के किसी मुल्क को आज तक तारीखी ऐतबार से देने की हैसियत नहीं है। ''सारे जहां से अच्छा, हिन्दोसतां हमारा।'' जिसने भी कहा था और डा॰ इकबाल ने कहा था, बिल्कुल सच कहा था। उन्होंने सिर्फ शेर नहीं पढ़ा था, सिर्फ कविता नहीं कही थी बल्कि सारी दुनिया के धर्म-कर्म, जो सारी दुनिया के मुल्कों में नहीं पाए जाते, वे हिन्दोस्तां में पाए जाते हैं। सारी दुनिया की तहज़ीबें, जो किसी एक मुल्क में अमानत ओर धरोहर के तौर पर नहीं पायी जातीं, हिन्दुस्तान में वे पायी जाती हैं इसीलिए हिन्दुस्तान में रहने वाले हर तबके के समाज को हिन्दस्तान की नुमाइंदगी करने का पूरा-पूरा हक हासिल होना चाहिए और हमें खुशी है कि हमारे मुल्क के इंसाफ-परवर, कानूनी हुक्मरानों ने मुल्क का दस्तूर देते वक्त हिन्दुस्तान में यह क्लीयर कर दिया था कि इस देश में धर्म-कर्म की बुनियाद पर, ज़ात-बिरादरी की बुनियाद पर, पक्षपात करने के लिए किसी को मौका नहीं दिया जाएगा। जो भी हिन्दुस्तानी है, वह हिन्दुस्तान का बाइज्ज़त शहरी है। हिन्दुस्तान का दस्तूर उसे ज़िंदगी के हर मोड़ पर रहनुमाई का नूर देता है ओर हिन्दुस्तान का दस्तूर उसके हकूक-ए-इंसानी को किसी भी तरह नज़रअंदाज नहीं करता। सर, हमारे मुल्क के कानून-व-दस्तूर की जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी, मगर...

''बनती नहीं है सब्र को रुख़सत किए बगैर,
काम उनकी बेक़रार निगाहों से पड़ गया।''

एक बात ज़रूर कहनी पड़ेगी कि आज minorities के मसायल पर जो कुछ सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है, किसी तरह से उस तरफ के लोगों की तरफ से भी हिमायत आ रही है, कांग्रेस की जो लोग मुख़ालफ़त करते हैं, उनकी तरफ से भी हिमायत आ रही है, यू.पी.ए. में जो लोग हैं, इनकी तरफ से भी हिमायत आ रही है, लेकिन अगर इस मुल्क में minorities damaged हुई है, अगर minority के लोग तालीम में पिछड़े हैं, अगर minorities के लोग आर्थिक ऐतबार से मजरूह और ज़ख्मी हुए हैं, तो किसी एक पार्टी के ऊपर इस इलज़ाम को आईद करना तारीख़ की सच्चाइयों से निगाह चुराने के मुतरादिफ है। अगर इस मुल्क की minority वाक़ई आज़ादी-ए-हिंद के बाद अब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं पहुंची है, अगर तालीमी ऐतबार से यह ग़ारत हुई है, अगर मआशी ऐतबार से यह मजरूह और कमज़ोर हुई है तो इस मुल्क के मुख़ालिफ़ सूबों में और सेंटर में किसी न किसी ideology के मानने वालो की हुकूमतें रहीं हैं। किसी एक पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार करार देना, मैं समझता हूं कि तारीख़ की सच्चाइयों से भागना है। सारी की

सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं अगर वाक़ई इस देश के लोगों के हक सल्ब हुए हैं और यकीनन सल्ब हुए हैं, जिसमें minority बहुत पीछे रह गई है तो इसके लिए कोई एक पार्टी जिम्मेदार नहीं है। अपनी-अपनी तारीफों के पुल बांधने के बजाय अगर लोग अपने-अपने शासन और प्रशासन के दौर की उन खराबियों पर शर्मिन्दा हों, तो ज्यादा बेहतर होगा, जिसकी वजह से minority आज इतनी पीछे रह गई है। आज सभी लोगों के दिलो-दिमाग़ में सामूहिक तौर पर minorities के लिए हमदर्दी का, प्यार का, एक सागर उबला है। हम उस उबलते हुए सागर का स्वागत करते हुए यह कहना चाहेंगे कि इस चीज़ को सियासी तनाज़ुर में देखते हुए बाज़ीचा-ए-अतफाल न बनाया जाए, बल्कि निहायत ईमानदारी के साथ, जो बिल आया हे, इसके इंप्लिमेंटेशन की राहें हमवार की जाएं ओर कमीशन को जो अख्तियारात दिए गए हैं, मैं उसकी मुबारकबाद वज़ीर-ए-तालीम साहब को देना चाहूंगां मगर कमीशन के पास जो अख्तियारात नहीं हैं और न होने की शक्ल में यह तालीमी प्रोग्राम फिर नाक़िस का नाक़िस रह जाएगा, मेरी गुज़ारिश है कि उन अख्तियारात की तरफ भी निगाह-ए-तवज्जह फरमाएं कमीशन इतना पावरफुल होना चाहिए कि जो भी इंप्लिमेंटेशन के लिए उसकी ख्वाहिशात आपके सामने आएं, उन ख्वांहिशात को अमली जामा पहनाया जाए ताकि Minorities के लिए रोशन मुस्तकबिल की राहें इल्म के मैदान में हमवार हो सकें वरना इससे पहले भी दीगर कमीशन्स आए हैं। उस कमीशन्स के हाल भी देखे गए हैं। उनकी नाक़िस नहीं, बल्कि कामिल कोशिशों के बावजूद आज तक पार्लियामेंट के ज़रिए उन कमीशनों के ऊपर कोई कार्यवाही हुई होगी कुछ पर, मगर एजुकेशन के मामले में वे दिगर मामले में बहुत सारे कमीशन इससे पहले भी बने थे। Minorities के मआशी पोज़िशन पर भी बहुत कमीशन बने और उन कमीशन्स को भी उसी तरह आज तक गर्द चाट रही है।

[श्री उपसभापति पीठासीन हुए]

मेरी गुज़ारिश यह है कि मामला इतना साफ और शफ़ाफ होना चाहिए, जिस नीयत-व-अख़लास के साथ यह कमीशन आया है, मेरी गुज़ारिश है कि इस बिल को न सिर्फ पास किया जाए, बल्कि तालीमी ऐतबार से Minorities के लिए हर वह मुश्किल राह आसान की जाए जिसके ज़रिए ये लोग भी मुल्क की मुख्य धारा के साथ चल सकें। 1947 से जिन लोगों के चलने के जज्बात हैं, उनके जज्बात आज भी शर्मिन्दा-ए-ताबीर नहीं हो पाते। जबकि Minorities के अंदर यह सलाहियत मौजूद है, minorities के अंदर यह कुव्वत और ताक़त मौजूद है, अपने देश के साथ वफादारी का वह जज़्बा मौजूद है कि जितने परसेंट लोगों को Minorities के मैदाने-अमल में उतारा गया, उन्होंने बहुत अच्छे काम करके दिखलाएं हैं, चाहे वह डा. अब्दुल कलाम जैसी बड़ी शख्सियत हो, चाहे खेल के मैदान की शख्सियत हो, चाहे तालीम के मैदान की शख्सियत हो, कोई भी ऐसा मैदान नहीं है, जिस मैदान में minority के लोगों को अगर टेस्ट करने के लिए उतारा गया है, तो minority के लोगों ने मुल्क को शर्मिन्दा किया हो। मुल्क का सिर minority के लोगों ने मेजॉरिटी की ही तरह, मुल्क की

आज़ादी से पहले भी ऊंचा किया था, मुल्क की आज़ादी के बाद भी ऊंचा करने का जज़्बा रखते हैं। इसलिए मेरी गुज़ारिश है कि आप इस बिल को पास कीजिए और इसमें जो ख़ामियां हैं, उन ख़ामियों को खत्म करते हुए, मुस्तक़बिल की तरफ Minorities को एक अच्छी राह दीजिए, जिससे उनका हौसला बुलंद होगा, यकीनन मुल्क में एक अच्छा पैगाम जाएगा, अच्छा message जाएगा। इसको राजनीति से ऊपर उठकर इंप्लिमेंट किया जाए, बहुत-बहुत शुक्रिया।

مولانا عبیداللہ خان اعظمی: سر، نیشنل کمیشن مائنارٹی ایجوکیشنل بل 2004 اس وقت اَپر ہاؤس میں زیرِ بحث ہے۔ میں وزیرِ تعلیم، جناب ارجن سنگھ صاحب کو اپنے دیگر ساتھیوں کی طرح سے یہ مبارک قدم اٹھانے پر مبارکباد دے رہا ہوں۔ اس بل کی سخت ضرورت تھی۔ یہ بل ہندوستان کے پسماندہ لوگوں کی تعلیم کے حصول کے لئے راستہ ہموار کرے گا اور اصل مقصد کی طرف ملک کی بہت بڑی اکثریتی آبادی کو، جس کو اتفاق سے اقلیتی آبادی کہتے کہتے لوگ تھکتے نہیں ہیں، لے جائے گا۔ تعلیم کے میدان میں کسی بھی کمیونٹی کا پچھڑنا صرف اس کے پچھڑنے کی علامت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ جس سماج میں رہتا ہے، جس ملک میں رہتا ہے، جس ماحول میں رہتا ہے، اور جس آب و ہوا میں رہتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ کسی بھی ملک کی عوام اگر پڑھی لکھی ہے تو وہ ملک تعلیمی قدروں کی بنیاد پر پوری دنیا میں اپنا عزت بھرا ہوا مقام رکھتا ہے۔ کسی بھی درخت کی شاخ اگر ہری بھری ہے اور اس درخت کی کوئی شاخ سوکھ رہی ہے تو مالی چمن کا سرپرست اس بات کی فکر میں رہتا ہے کہ درخت کی خوبصورتی کو کسی اعتبار سے دیکھنے کے لئے برباد نہ ہونے دیا جائے اور لوگ اس درخت کی خوبصورتی کو ہر اعتبار سے حسنِ نظر سے دیکھیں۔ ہمارا ہندوستان ایک چمن کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس بات کو ہمارے بزرگوں نے کہا تھا، جس بات کو آج کے سمجھدار لیڈر کہتے ہیں، آنے والے دور کی پیدا ہونے والی نسلیں کہتی رہیں گی۔ ہندوستان مختلف کلچر کا ملک ہے، مختلف سنسکار کا ملک ہے، مختلف تہذیبوں کا ملک ہے، مختلف آستھاؤں اور عقیدوں کا ملک ہے۔ اس ملک کی انیکتا میں ایکتا کا جو درشن دنیا دیکھتی ہے، اس کا کوئی جواب دنیا کے کسی ملک کو آج تک تاریخی اعتبار سے دیکھنے کی حیثیت نہیں ہے۔ ''سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا''۔ جس نے بھی کہا تھا اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، بالکل سچ کہا تھا۔

†Transliteration of Urdu Script.

انہوں نے صرف شعر نہیں پڑھا تھا، صرف کویتا نہیں کہی تھی، بلکہ ساری دنیا کے دھرم کرم، جو ساری دنیا کے ملکوں میں نہیں پائے جاتے، وہ ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ ساری دنیا کی تہذیبیں، جو کسی ایک ملک میں امانت اور دھروہر کے روپ میں نہیں پائی جاتیں، ہندوستان میں وہ پائی جاتی ہیں۔ اسی لئے ہندوستان میں رہنے والے ہر طبقے کے سماج کو ہندوستان کی نمائندگی کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہونا چاہئے اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے ملک کے انصاف پرور، قانونی حکمرانوں نے ملک کا دستور دیتے وقت ہندوستان میں یہ کلیئر کر دیا تھا کہ اس دیش میں دھرم کرم کی بنیاد پر، ذات برادری کی بنیاد پر، پکشپات کرنے کے لئے کسی کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ جو بھی ہندوستانی ہے، وہ ہندوستان کا باعزت شہری ہے۔ ہندوستان کا دستور اسے زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کا نور دیتا ہے اور ہندوستان کا دستور اس کے حقوقِ انسانی کو کسی بھی طرح نظر انداز نہیں کرتا۔

سر، ہمارے ملک کے قانون و دستور کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہوگی، مگر ؎

بنتی نہیں ہے صبر کو رخصت کئے بغیر

کام ان کی بے قرار نگاہوں سے پڑ گیا

ایک بات ضرور کہنی پڑے گی کہ آج مائناریٹیز کے مسائل پر جو کچھ سوچا جا رہا ہے سمجھا جا رہا ہے، کسی نہ کسی طرح سے اُس طرف کے لوگوں کی طرف سے بھی حمایت آ رہی ہے، کانگریس کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، ان کی طرف سے بھی حمایت آ رہی ہے، یو پی اے میں جو لوگ ہیں، ان کی طرف سے بھی

حمایت آ رہی ہے، لیکن اگر اس ملک میں minority damage ہوئی ہے، اگر مائنارٹی کے لوگ تعلیم میں پچھڑے ہیں، اگر مائنارٹیز کے لوگ آرتھک اعتبار سے مجروح اور زخمی ہوئے ہیں، تو کسی ایک پارٹی کے اوپر اس الزام کو عائد کرنا تاریخ کی سچائیوں سے نگاہ چرانے کے مترادف ہے۔ اگر اس ملک کی مائنارٹی واقعی آزادی کے بعد اب تک اپنے لکشے کی پراپتی تک نہیں پہنچی ہے، اگر تعلیمی اعتبار سے یہ غارت ہوئی ہے، اگر معاشی اعتبار سے یہ مجروح اور کمزور ہوئی ہے تو اس ملک کے مختلف صوبوں میں اور سینٹر میں کسی نہ کسی آئیڈیالوجی کے ماننے والوں کی حکومتیں رہی ہیں۔ کسی ایک پارٹی کو اس کے لئے ذمہ دار قرار دینا، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کی سچائیوں سے بھاگنا ہے۔ ساری کی ساری پارٹیاں اگر واقعی اس دیش کے لوگوں کے حق صلب ہوئے ہیں اور یقیناً صلب ہوئے ہیں، جس میں مائنارٹی بہت پیچھے رہ گئی ہے تو اس کے لئے کوئی ایک پارٹی ذمہ دار نہیں ہے۔ اپنی اپنی تعریفوں کے پل باندھنے کے بجائے اگر لوگ اپنے اپنے شاسن اور پرشاسن کے دور کی ان خرابیوں پر شرمندہ ہوں، تو زیادہ بہتر ہوگا، جس کی وجہ سے مائنارٹی آج اتنی پیچھے رہ گئی ہے۔ آج بھی لوگوں کے دل و دماغ میں ساموہک طور پر مائنارٹیز کے لئے ہمدردی کا، پیار کا، ایک ساگر اُبلا ہے۔ ہم اس اُبلتے ہوئے ساگر کا سواگت کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیں گے کہ اس چیز کو سیاسی تناظر میں دیکھتے ہوئے بازیچہ اطفال نہ بنایا جائے، بلکہ نہایت ایمانداری کے ساتھ، جو بل آیا ہے، اس کے امپلی منٹیشن کی راہیں ہموار کی جائیں اور کمیشن کو جو اختیارات دئے گئے ہیں، میں اس کی مبارکباد وزیر تعلیم صاحب کو دینا چاہونگا۔ مگر کمیشن کے پاس جو اختیارات نہیں ہیں اور نہ ہونے کی شکل میں یہ تعلیمی پروگرام پھر ناقص کا ناقص رہ جائے گا۔ میری گذارش ہے کہ ان اختیارات کی طرف بھی نگاہِ توجہ فرمائیں کمیشن اتنا پاور فل ہونا چاہئے کہ جو بھی امپلی منٹیشن کے لئے اس کی خواہش آپ کے سامنے آئیں، ان خواہشات کو عملی جامہ پہنایا جائے تاکہ مائنارٹیز کے لئے روشن مستقبل کی راہیں علم کے میدان میں ہموار ہو سکیں ورنہ اس سے پہلے بھی دیگر کمیشنس آئے ہیں۔ ان کمیشنس کے حال بھی دیکھے گئے ہیں۔ ان کی ناقص نہیں بلکہ کامل کوششوں کے باوجود آج تک

پارلیمنٹ کے ذریعہ ان کمیشنوں کے اوپر کوئی کارروائی ہوئی ہوگی کچھ پر، مگر ایجوکیشن کے معاملہ میں و دیگر معاملے بہت سارے کمیشن اس سے پہلے بھی بنے تھے۔ مائنارٹیز کے معاشی پوزیشن پر بھی بہت کمیشن بنے اور ان

کمیشنس کو بھی اسی طرح آج تک گرد چاٹ رہی ہے۔

(شری اُپ سبھاپتی صدر نشیں ہوئے)

میری گزارش یہ ہے کہ بل صاف اور شفاف ہونا چاہئے، جس نیت و اخلاص کے ساتھ یہ کمیشن آیا ہے، میری گزارش ہے کہ اس بل کو نہ صرف پاس کیا جائے، بلکہ تعلیمی اعتبار سے مائنارٹیز کے لئے ہر وہ مشکل راہ آسان کی جائے جس کے ذریعہ یہ لوگ بھی ملک کی مکھیہ دھارا کے ساتھ چل سکیں۔ ۱۹۴۷ء سے جن لوگوں کے چلنے کے جذبے ہیں، ان کے جذبات آج بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو پاتے۔ مائنارٹیز کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، مائنارٹیز کے اندر یہ قوت اور طاقت موجود ہے، اپنے دیش کے ساتھ وفاداری کا وہ جذبہ موجود ہے کہ جتنے فیصد لوگوں کو مائنارٹیز کے میدان عمل میں اتارا گیا، انہوں نے بہت اچھے کام کر کے دکھائے ہیں چاہے وہ ڈاکٹر کلام جیسی بڑی شخصیت ہوں، چاہے کھیل کے میدان کی شخصیت ہوں، چاہے تعلیم کے میدان کی شخصیت ہوں، کوئی بھی ایسا میدان نہیں ہے جس میدان میں مائنارٹی کے لوگوں کو اگر ٹیسٹ کرنے کے لئے اتارا گیا ہے تو مائنارٹی کے لوگوں نے ملک کو شرمندہ کیا ہو۔ ملک کا سر مائنارٹی کے لوگوں نے میجورٹی کی ہی طرح ملک کی آزادی سے پہلے بھی اونچا کیا تھا، ملک کی آزادی کے بعد بھی اونچا کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اس لئے میری گزارش ہے کہ آپ اس بل کو پاس کیجئے اور اس میں جو خامیاں ہیں، ان خامیوں کو ختم کرتے ہوئے، مستقبل کی طرف مائنارٹیز کو ایک اچھی راہ دیجئے، جس سے ان کا حوصلہ بلند ہوگا۔ یقیناً ملک میں ایک اچھا پیغام جائے گا، اچھا میسج جائے گا۔ اس کو راجنیتی سے اوپر اٹھ کر امپلی منٹ کیا جائے، بہت بہت شکریہ۔

''ختم شد''

SHRI FALI S. NARIMAN (Nominated): Sir, I rise to say a few things about the Bill particularly since we have been enlightened by what the hon. Minister said in introducing it—that it was the result of a consensus at a meeting of educational institutions, and that there was such a demand.

My only reason for making submission here is not to enter into the politics of minorities, because there is a lot of politics about minorities today; I would rather eschew politics of minorities. I only wish to draw the attention of the hon. Minister to two or three facts of this Bill because it is good in conception, but I do not want it to be declared unconstitutional for any reason. And one of the reasons, which gives me some problem, is that Article 30 does not empower Governments to define who are minorities. The Article says, all minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions for their choice. Therefore, Sir, the first comment that I would make it that, when you define "minority" in clause (f) of the Definition Clause and say that for the purpose of this Act it means a community notified as such by the Central Government, you have no power to do that. This is a constitutional right of all minorities. Therefore, one should not get into the situation of a good legislation sometimes going awry because of some problems that have arisen. Therefore, either this should be deleted or it should be prescribed by rules that 'all minorities' is meant by the word 'minority' whoever they are, because otherwise there is going to be a lot of problems between minorities, between linguistic minorities and religious minorities as well. The Supreme Court has not yet decided, although there are two views, namely, that religious minorities are, perhaps, national minorities, whereas linguistic minorities are State-based minorities. Therefore, that must be born in mind when you frame rules; I think it all can be covered under the rules which are to be framed.

Secondly, Sir, in the definition of minority educational institution, the word *'or'* is mis-placed. It means a college or institution established *'or'* maintained. No. It must be established *'and'* maintained; not merely established. Therefore, I accept the word 'maintained', although the correct word is 'administered'. Article 30 says 'administered'. But, since you have put the word 'maintained', it is all right. But this is a very important deletion that you would have to make, namely, the word *'or'* is not to be there; that would mean even if you establish and do not maintain it or administer it, it would be

entitled. No, it cannot be entitled becuase this is not Article 30; the definition cannot, in any way, go contrary to Article 30 of the Constitution.

The other aspect of this, which I would like to bring to the notice of the hon. Minister, is this. I may be wrong; but I have read this Bill twice. Now, the word 'technical education' has been defined, but I do not find it anywhere else in the Bill, because it is defined "for the purposes of the Act." It says, "Unless the context requires in this Act, technical education has the meaning assigned to it", and I do not find that in any other clause of this Bill the word technical education is there. So, perhaps, on a subsequent occasion, this could be deleted, unless the Minister had some other clause which has been ommitted for some reason or the other.

The last thing that I would like to mention to the hon. Minsiter is that—Prof. Saif-ud-Din Soz, I think, mentioned it—when Section 4 says that you shall not be qualified unless you have been a judge of the High Court, it seems to exclude judges of the Supreme Court, which is probably not the intention. But that again should be made clear, otherwise they may take very high unction at being deprived of filling this place.

The last thing that I would say is this. and there, Shrimati Sushma Swarajji has much more experience as a parliamentarian than I have. She has asked for a Select Committee. The surest way of defeating a motion for appointment of a Select Committee is for the Mover to mention the names of the Members of that Committee, because the surest way then is that it is defeated. I know this because, Sir, whenever judges propose that matter should go to arbitration and they ask counsel for one party and we very foolishly mention names of certain arbitrators, very distinguished people, immediately the other side says, "No. We don't want them, only because you have mentioned the names". So, I would respectfully request that the methodology should be that the Select Committee be appointed by the Chairman in consultation with the leaders of all political parties. Then, it may be more acceptable to all the Members of the House. That is all.

SHRI M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI: Sir, at the very outset, I would like to mention here that this is a very important discussion on the National Commission for Minority Educational Institutions Bill, 2004. This is a very important national issue and, cutting-across political or ideological differences, it should be seen as a national issue. Sir, every country's welfare

is very much linked with the welfare of the minority community of that country. Even the United Nations Organisation in its resolutions has stated that every country has to do the maximum for the welfare and protection of the rights of the minority community of that country. This is my request to the hon. friends who are sitting on the other side of the House. The U.P.A. Government has taken the initiative within weeks of its coming to power to hold a Conference for the Welfare and Education of Minorities. That was mentioned by the hon. Minister on 3rd July. Sir, it is in the interest of the nation that all communities are brought within the fold of education. Sir, the largest minority community, i.e., the Muslim community forms 15 per.cent of the total population of the country. Sir, bringing them within the educational framework means to bring them in the national mainstream. Among all other backward communities, the Muslim community is the most backward. The statistics show that. It speaks only about their backwardness. It is just marginally ahead of the SCs and STs.

Sir, I cannot understand why my friends who are sitting on the other side of the House are opposing such a great national move. Is it in the interest of the nation? So, I request them to understand the real situation of the backwardness of the community. Whenever some truth is disclosed by the hon. Minister, there is no meaning in making a hue and cry about that. I would like to remind them this.

हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से
खुशबू आ नहीं सकती, काग़ज के फूलों से।

This was the hue and cry made during the speech of the hon. Home Minister. I would like to compliment the Government, the hon. Prime Minister and the hon. Minister for Human Resource Development, Shri Arjun Singhji for taking this historic initiative.

Sir, it is very essential that the minorities should get their due share in the total welfare and in the education budget of the country. It is the responsibility of the Government to enable the minorities to play a constructive and productive role in the development process. So, I hope that this legislation will be a great help in attaining this great height of our ideas.

Sir, my hon. friend who is sitting on the other side of the House while speaking on the Bill mentioned about the phenomenon of ghettoisatin. I am not entering into any controversy with him. But, everybody knows how

the term 'ghettoisation' was brought to our country. Certain boards were put in some cities of our country that rooms or flats will not be allotted to the persons belonging to the minority community. Everybody knows it. I am not entering into any controversy on this issue.

Sir, I have a few suggestions to the hon. Minister. One objection which was raised against this Bill was that it does not give any power to the State Governments. There was some difference of opinion whether some powers should be given to the State Governments. There is a suggestion that some power should be given to the State Governments. But, Sir, that suggestion is not in the interest of the Bill. Because if the State Governments are given such a power, there is a chance for some of the State Governments to misuse or abuse that power. So, I humbly request the hon. Minister that it should be as envisaged in the Bill, and the status *quo* should be maintained.

Sir, the Bill has a provision for affiliation to the Central Universities. I have a suggestion to the hon. Minister. It should not be restricted to the Central Universities alone. It must be applied to all universities in the country so that *(Interruptions)* No, no; as far as affiliation to the Central Universities is concerned, my request to the hon. Minister is to make it a universal one.

Sir, the time is very limited and I am not going to reply to the objections raised from the other side. The functions of the Commission should not be restricted, merely, to giving affiliation to certain institutions. Sir, my request to the hon. Minister is that it should cover all areas of education of minorities. For example, their due share in the Sarva Shiksha Abhiyan and the obstacles faced by them-the obstacles faced by the minority communities in getting reasonable presence in the secondary and higher education professional and technical education, aided by the Government; also, Sir, getting the legitimate share in educational Budget of both, Centre and States—are to be removed.

Sir, this kind of legislation needs a great moral courage, integrity, and a sense of justice. That is why we say that the UPA Government has taken a very great initiative. Sir, the Minister is here, the former Minister is also here; they all know that education of the minorities is in a pathetic condition. So, instead of making it a political issue, instead of making it

an emotional issue, please try to understand the real situation faced by the minority communities in the country.

Sir, relative deprivation in specific areas has become a very important feature of the backwardness in minorities—backwardness in absolute terms. For example, Muslims are ten percentage points behind in the national literacy average, according to the Radhakrishnan Report. The percentage of matriculates in the community is only five per cent. Sir, many reasons are there—poor ambience, lack of motivation, dropouts at the school-level, poverty, etc. Sir, graduates are a mere 2.3 per cent as against 8-13 per cent in other communities.

Sir, the position that is granted to Urdu is pathetic. It is the *lingua franca* of the country. The new Commission, I think, will definitely look into it There is a calculated neglect of Urdu language resulting in, again, educational backwardness and backwardness in literacy.

Sir, finally, I have to mention here, it is our well-thought view that this Bill will re-establish the Constitutional right of the minorities to establish and manage their own educational institutions. Once again, it is under question. There are so many pronouncements from many judicial centres against the Constitutional right of the minorities to establish their own educational institutions. So, Sir, this has nothing to do with politics, this is in the national interest that this Government has brought in this legislation, and it is to reaffirm the Constitutional rights to the minorities for their educational rights. For this, I once again congratulate the hon. Minister. Whatever may be the opposition, I have to compliment Shri Arjun Singh, for his integrity, for his sense of justice.

गर तुन्द व तेज़ हवा ज़माने की चिराग़
अपना जला रहा है।
एक मर्द दरवेश जिसको खुदा ने दिया है
अन्दाज़ खुसर्वाना।

Thank you.

SHRI JESUDASU SEELAM (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, I take this opportunity to thank you for giving me this opportunity. Sir, I rise to support the Bill. I want to thank, through you, the hon. Minister.

Sir, this Bill will remove certain constraints, certain prejudices, the

minority community members are facing while establishing and then maintaining the educational institutions. Sir, you are aware that education is the key to so many problems the minority is facing. It is the key to their economic development. It is the key to their social development also. Much more than that, Sir, in the country today, we have to take the psychological aspects of the minority communities into consideration. When I psychological aspirations, I mean the whole effort of the Government has been to create confidence among the minorities and to psychologically empower them to remove that psychological reductionism. I am referring specially to development for the last fifteen years. There has been some situation where there is mistrust, where there is some sort of an absence of the trust. So it is possible only by improving their economic standards, economic conditions for which we have to have basic education and as mentioned by hon. Members, technical education and the professional education, with quality education. These days, if you look at the percentage of minorities in the civil services and in the important posts of Government, Sir, the delivery mechanism is very important. Whatever we may talk is okay but whatever happens in the field, whatever happens in the districts, whatever happens in the rural areas, where most of the minority community members are deprived of their real share is important. So the key lies in the basic education. I appreciate some of the suggestions made by the hon. Members where we have to take care of the dropouts. We have to give them proper inputs. We have to run some extra classes. This will be possible not in the existing structure. It has to be done through this Commission because the Commission I suppose will have its own prejudices. So, while doing so, the Commission should also take care of specific needs of the community which are rural based. Many points have been raised and clarified on the issue relating to the Muslim community. Sir, I would like to point out to this august House that there has been a traditional practice in South India. The Christian minorities are the pioneers in running educational institutions. They are the one's who govern the entire South India for imparting quality education. All the leaders who shaped this country's future have been educated in minority institutions. Sir, now if you look at the status, the situation, the conditions of those minority institutions are very deplorable because they have been treated with prejudices. They have been deprived of their rights. Their Fundamental Rights have been violated from time to time. This Bill will help to remove those anomalies which have crept in because of our discriminatory attitude, because of our

indifferent attitude, to the problems of the minorities specially the educational requirements of the minorities. Sir, I would like to point out here that certain deficiencies have already been pointed out by the hon. Members. I stand to agree with the points made by some of our Members specially, enhancing the Schedule where the affiliation could be sought for and I would like to draw the kind attention of the hon. Shri Laljan Bashaji from Andhra Pradesh. He was speaking about the *Neeyat* of the previous Government. मैं उन्हें ध्यान दिलाना चाहता हूं, उनकी नीति क्या है, वह मैं देखना चाहता हूँ। उनसे गुजारिश करता हूँ...(**व्यवधान**)...नीति...नीति साफ नहीं है...(**व्यवधान**)...you are giving doles on one side and stabbing at the back.. You are creating terror among the minorities. Is it साफ नीयत है, साफ नीति है? You started doing this dualism. You started doing double talk. That is why I appeal to my friends that you realise the truth. That is why people have rejected you outright. I would like to invite the attention of the hon. Member...*(Interruptions)*...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, this is unnecessary provocation.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the Bill.

SHRI JESUDASU SEELAM: Let me point out that ...*(Interruptions)*...Sir, let me point out one thing. I would like to point out one thing in this connection...*(Interruptions)*...

श्री एस॰ एम॰ लालजन बाशा: सर, वह बिल पर बोलें।

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, I am not talking about individuals...*(Interruptions)*..

श्री एस॰ एम॰ लालजन बाशा: सर, वह हमारे भाई हैं, मायनोरिटी में आते हैं, मैं उन की बात का बुरा नहीं मानता क्योंकि उन्होंने आई॰ए॰एस॰ से रिजाइन किया और कांग्रेस पार्टी के टिकट से खड़े हो गए, लेकिन हार गए।..(**व्यवधान**)...

डा॰ अलादी पी॰ राजकुमार (आन्ध्र प्रदेश): सर, चन्द्रबाबू नायडू साहब ने मायनोरिटीज़ के लिए जितना किया, देश में कोई नहीं करेगा। यह मेरा चैलेंज है, नहीं तो मैं रिजाइन कर के जाऊंगा।

Our leader, Shri Chandrababu Naidu has done a lot for the minorities ...*(Interruptions)*... You have to learn a lot from him...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापतिः यह डिबेट आंध्र के बारे में नहीं है। आप बैठ जाइए। यह डिबेट आंध्र की नहीं है।..(व्यवधान)... बैठिए, प्लीज।

Mr. Seelam, please conclude...*(Interruptions)*...

मि॰ नारायणसामी, आप बैठिए। आप बैठिए।..(व्यवधान)...

डा॰ अलादी पी॰ राजकुमारः सर, हैदराबाद में कफर्यू रहता था, दंगा-फसाद चलते थे ...(व्यवधान)...

श्री एस॰एम॰ लालजन बाशाः सर, क्योंकि मेरा नाम लेकर बोला गया है और मैं ने अपनी स्पीच में भी कहा है कि तेलगु देशम...(व्यवधान)...

डा॰ अलादी पी॰ राजकुमारः सर, 9 साल में कहीं कोई दंगा-फसाद नहीं हुआ।

श्री उपसभापतिः अभी दंगा-फसाद पर डिस्कसन नहीं हो रहा है।

डा॰ अलादी पी॰ राजकुमारः सर, 9 साल में लॉ एंड ऑर्डर जबर्दस्त था। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः मि॰ सीलम, आप कनक्लूड करिए।

SHRI JESUDASU SEELAM: I am concluding, Sir...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Seelam, please conclude ...*(Interruptions)*...Please confine yourself to the Bill. हनुमंत राव जी, बैठिए। Nothing will go on record except Mr. Seelam's speech...*(Interruptions)*...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY:*

SHRI S.M. LALJAN BASHA:*

SHRI V. HANUMANTHA RAO (Andhra Pradesh):*

SHRI NANDI YELLAIAH (Andhra Pradesh): *

DR. ALLADI P. RAJKUMAR:*

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, I wold like to appeal to the hon. Members to see what will happen after five years...*(Interruptions)*... That is all...*(Interruptions)*...

Sir, secondly, I would like to draw the kind attention of this House to the genuine efforts made by the hon. Chief Minister of Andhra Pradesh,

*Not recorded.

Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy. The Government of Andhra Pradesh have taken sincere efforts, for the first time, in reserving 5 per cent of jobs in all institutions for the development of minorities...*(Interruptions)*... I do not want to argue with them on this issue...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Seelam, please conclude.

SHRI JESUDASU SEELAM: I was only referring to ...*(Interruptions)*... I don't want to make this House the A.P. Legislative Assembly ...*(Interruptions)*... I was only referring to peoples' response...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You please speak on the Bill.

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, I would like to conclude by saying that I support this Bill and request the hon. Minister to make an amendment to enhance the scope of the Schedule and also to take cognisance on some of the suggestions made by the hon. Members of this House on the definition.

Secondly, while dealing with the cases relating to minorities, a lot of suggestions were made by the Supreme Court. It has also given some guidelines. Those guidelines have to be incorporated. I am happy that a separate clause has been introduced to regulate grants to minority institutions.

With these few observations, I thank you very much again.

SHRI SHANKAR ROY CHOWDHURY (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, Sir, in this context, I would like to address a few queries to the hon. Minister in furtherance or in continuation of the point raised by my hon. friend, Shri Fali Nariman, as to why the definition of 'minorities' is restricted to religious minorities. If you truly mean this to be a National Commission for minorities' education, you should ensure that it covers not only religious minorities but also linguistic minorities in various parts of the country.

Sir, the Bill provided to us here does not contain the Statement of Objects and Reasons.

But I have got a copy of the Bill, as presented in the Lok Sabha, in which the Statement of Objects and Reasons is there. In the Statement of Objects and Reasons, it particularly and apparently refers to running of

technical colleges. Amongst the various issues raised by the representatives of the minority community was the difficulty faced by them in establishing and running their own educational institutions despite the constitutional guarantee accorded to them in this regard. But the main thrust of the Statement of Objects and Reasons, it seems, pertains to technical universities, technical colleges, technical institutions. And, as Mr. Nariman pointed out, though 'technical education' has been defined in the preliminary chapter of the Act, there is no reference to technical education inside the body of the Bill itself. Again, it has given a scheduled list of universities, in which certain universities occur. I would like to know the basis on which these selected universities have been included in the schedule and not others. It is again mentioned in the Statement of Objects and Reasons that the territorial jurisdiction of the State universities and the concentration of the minority population in some specific areas invariably meant that institutions could not avail the opportunity of affiliation with the universities of their choice. What are the problems of minority institutions located in South India face in affiliation with, let us say, Madras University or any other established university? Why should it be necessary for such an institution to seek affiliation with the Mizoram University? The hon. Minister may please clarify this.

Another aspect of even religious minorities is its applicability region-wise. For example, will an institution, being run in the State of Jammu & Kashmir by the Hindu *pandit* community, would qualify as a religious minority in that State? This point would have to be specified because if you go by the Statement of Objects and Reasons, and particularly where the Act says 'concentration of minority population in some specific areas', I think, it fits the other way round also. And, the Hindu community is not defined as minority. So, these things have to be catered to.

I would also like to say a few words about the *madarsa* system of education. and, my comments, if you like, are particularly addressed to my Muslim colleagues in the House because I do think this is a system which has got to be looked into great detail by all of us. And, the answer, if any, has to come from within the Muslim community. It cannot come from outside. Now, again, I am taking the example of the State of West Bengal. There are three types of *madarsa* in West Bengal —high *madarsas,* senior *madarsas* and *kharijee madarsas.* As far as the high *madarsas* are concerned, they are governed by the West Bengal *madarsa* education

Board. They are like any other educational examination, with the exception of one additional language of Arabic. There is no problem in it. I had myself studied in a minority institution. I had studied in a Christian institution. In that institution, I had learnt lessons from the Bible. It has done no harm to me. In addition to that, I have learnt so many other good things from many best teachers in the world, as far as I can understand. The senior *madarsa* system is also under the control of the Government, in which, perhaps, the general subjects are in lesser proportion. But that is the business of the system. They can adjust it because to my understanding and my feeling, the type of education and degrees given by senior *madarsa* system do not fit the students for employability in modern society. But that is my personal view. The Hig *madarasa* system is like any other system. These are small private or *kharijee madarasas*, which have to be looked into. Because the *Kharijee Madrasa* system, exclusively, teachers religious texts. What is more, I will use the word, 'dangerous' in today's environment. These religious texts are taught by people, who themselves, do not know these things very well. As a result, they interpret and project the text in such a manner which, perhaps, is not conducive to maintain the type of environment that we require in this country.

SHRI M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI: But, Sir, regarding Madrasas, this allegation is coming up again and again. Many times it has been clarified. ...(*Interruptions*)... Without going into the depths of the matter. ...(*Interruptions*)... It is very unfortunate. ...(*Interruptions*)... It is very unfortunate.

SHRI SHANKAR ROY CHOWDHURY: I will repeat what I have to say though I have the greatest regard for my friend also. It is not about the first two types of Madrasas, which are well-regulated, well-controlled, well-administered, and well-looked into. Their standard of education is of the type in any other school. Good, bad or indifferent is a different matter. It is not a question of what is being taught. It is the people who are teaching it, who do not really have any deep knowledge of ...(*Interruptions*)... They are not scholars. ...(*Interruptions*)... these are small ....(*Interruptions*) These are not really ...(*Interruptions*)... in a manner which they themselves do not understand, in a village. I have seen this. ...(*Interruptions*)... सर, वे लोग इसको ठीक तरीके से समझते नहीं हैं। वे समझते नहीं हैं। ...(व्यवधान)

SHRI M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI: Sir, this is controversial. ...(*Interruptions*)... This is something very objectionable. ...(*Interruptions*)....

श्री उपसभापति: आप बैठिए। देखिए, there is a severe constraint of time. ...(*Interruptions*).... Please conclude now. ...(*Interruptions*).... There is a severe constraint of time. ...(*Interrutpions*)....

†**श्री अबू आसिम आजमी:** सर, यह गलत बयान हुआ है। ...(**व्यवधान**)

شری ابوعاصم اعظمی : سر، یہ غلط بیان ہوا ہے ....مداخلت.....

श्री शंकर राय चौधरी: मैं दुबारा कहना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)

†**श्री अबू आसिम आजमी:** मदरसों से क्या तकलीफ है? मदरसे कोई गलत चीज तो सिखाते नहीं हैं। आप पूरे हिंदुस्तान में, मदरसे चेक करा लीजिए, इंटेलीजेन्स से चेक करा लीजिए। पूरे हिंदुस्तान में एक मदरसा ऐसा नहीं मिलेगा। ...(**व्यवधान**)

شری ابوعاصم اعظمی : مدرسوں سے کیا تکلیف ہے؟ مدرسے کوئی غلط چیز تو سکھاتے نہیں ہیں۔ آپ پورے ہندستان میں مدرسے چیک کرا لیجئے، انٹیلی جنس سے چیک کرا لیجئے۔ پورے ہندستان میں ایک مدرسہ ایسا نہیں ملے گا۔ ....مداخلت.....

श्री उपसभापति: आप बैठिए। चेयर की परमीशन लेकर बात करना ठीक रहेगा, नहीं तो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

SHRI M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI: Sir, I have a humble submission to make. ...(*Interruptions*)....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Samadani, you can raise your point later on when you are speaking. ...(*Interruptions*)....

श्री शंकर राय चौधरी: सर, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं और दुबारा कह रहा हूं, जैसे मदरसों में उनका स्टैंडर्ड क्या है, वहां क्या पढ़ाया जाता है, कौन पढ़ाता है, वह स्टेट गवर्नमेंट अच्छी तरह निगरानी रखती है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि जो यह दूसरे मदरसे हैं, खारिजी मदरसे, इन पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं ....(**व्यवधान**)..

श्री एम॰ पी॰ ए॰ समद समदानी: यह खारिजी मदरसा क्या है, यह कहां है? ..(**व्यवधान**)..

श्री शंकर राय चौधरी: हमारे यहां होता है, हमारी स्टेट में यह नाम है। ...(**व्यवधान**) खारिजी मदरसा, जो हम कह रहे हैं, यह है। ....(**व्यवधान**)

श्री उपसभापति: अब आप कनक्ल्यूड कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

†Transliteration of Urdu Script.

SHRI M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI: Sir, I have a humble submission to make. ...(*Interruptions*).... Sir, one minute. ...(*Interruptions*).... Sir, please ....(*Interruptions*)... Sir, during the regime of the last Government; during the NDA Government's time, some MPs gave a request to the Government to please identify those *Madrasas* where there dangerous, so-called dangerous things are being taught, and that all the MPs will be with the Government to flight those centres. But the reply was, "No such *Madrasa* was identified." Sir, this is only a propaganda. Sir. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please ...(*Interruptions*)...

श्री शंकर राय चौधरी: सर, मदरसों का स्तर ठीक हो, इस पर क्या आपत्ति है? ...(व्यवधान) **श्री उपसभापति:** प्लीज, आप बैठिए।

†**श्री अबू आसिम आजमी:** सर, एक सेकेण्ड, यह खारिजी से गलतफहमी पैदा हो रही है। खारिजी का मतलब विदेश। यह विदेशी मदरसा क्या है? What is this 'Videshi Madarsa'? ऐसा कोई मदरसा नहीं चलता है। अलफाज गलत है. इसलिए मैं बात कर रहा हूं।

†شری ابوعاصم اعظمی : سر ایک سیکنڈ، یہ خارجی سے غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے۔ خارجی کا مطلب ودیش۔ یہ ودیشی مدرسہ کیا ہے؟ ''واٹ از دِس ودیشی مدرسہ'' ایسا کوئی مدرسہ نہیں چلتا ہے۔ الفاظ غلط ہے، اس لئے میں بات کر رہا ہوں۔

श्री शंकर राय चौधरी: माननीय उपसभापति जी, मैं दुबारा बोल रहा हूं। जो लफ्ज़ मैं कह रहा हूं, वह हमारे राज्य में इस्तेमाल होता हैं। मैं पश्चिम बंगाल का उदाहरण दे कर ही कह रहा था। मुझे सिर्फ यही कहना है कि जो कम्युनिटी है उसके अपने इंस्टीट्यशंस या मदरसा बोर्ड हैं, उन पर भी निगरानी रखी जानी चाहिए, जिस प्रकार हमारे राज्य में है। वैसे, यह जो अभी बिल पास हो रहा है, इसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन इसमें जो बोला गया है, उसमें जो मुख्य कमियां आई हैं, It is not clear enough. There should be clarified. And, I support the Bill.

श्री सुरेश भारद्वाज (हिमाचल प्रदेश): उपसभापति जी, धन्यवाद। मैं अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक 2004, जिसे माननीय अर्जुन सिंह जी इस सदन में लाए हैं, उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।...(व्यवधान) माननीय उपसभापति जी, इसं विरोध करने के पीछे कुछ कारण हैं, क्योंकि न तो यह विधेयक देश के हित में है और न ही यह विधेयक अल्पसंख्यकों के हित में है। लगता है कि माननीय मंत्री जी केवल वोट बैंक की राजनीति करने के लिए और अल्पसंख्यकवाद की मनोवृत्ति से ग्रसित हो कर इस विधेयक को लाए हैं। माननीय मंत्री जी अपने उन महान नेताओं और पुरोधाओं, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान किया था, उन लोगों के विचारों को भी इस प्रकार की मनोवृत्ति के साथ

†Transliteration of Urdu Script.

लेकर चल रहे हैं। वे उन्हें भी भूल गए हैं? संविधान की धारा 29 एवं 30 में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के लिए सेफगार्ड की व्यवस्था की गई है। जब हिन्दुस्तान का विभाजन हुआ, उससे पूर्व ही संविधान सभा में इस पर चर्चा प्रारम्भ हो गई थी और उस चर्चा में उस समय के संविधान सभा के माननीय सदस्य थे श्री महावीर त्यागी जी। उन्होंने आर्टिकल 29 के विषय में क्या कहा था मैं पहले वह बताना चाहूंगा–"He had said that the Assembly should not commit itself to a particular policy towards the minorities without first knowing whether the country was to be partitioned, and, if so, what treatment would be meted out to minorities in Pakistan or any other part of the India which might organise themselves separately." यह श्री सुभाष कश्यप जी के प्लानिंग ऑफ कांस्टीट्यूशन से उद्धृत किया गया है। संविधान सभा की माइनॉरिटी से संबंधित एक सदस्या थीं, राजकुमारी अमृत कौर जी, उन्होंने इस विषय पर क्या कहा है–Raj Kumari Amrit Kaur had expressed her strong objection to grant of freedom to minorities to establish and administer educational institutions of their own and becoming eligible to State aid. She wanted deletion of such a provision and cautioned that it could perpetuate communal institutions in the country. इस विषय पर बहुत लम्बी चर्चा हुई और अंत में आर्टिकल 29 एवं 30 पर, संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डा॰ भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा, ठीक प्रकार से उस धारा का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद उसे संविधान में सम्मिलित किया गया।

माननीय सभापति जी, जब संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के विषय में विचार किया जा रहा था, उस समय एक सलाहकार समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष महापुरुष सरदार पटेल थे। उस समिति के सदस्यों में पंडित गोबिंद वल्लभ पंत, श्री गोपीनाथ बारदोलोई, श्री एस॰ पी॰ मुखर्जी जैसे महान स्वतंत्रता सैनानी जैसे सदस्य थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू भी उस समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित थे। उस समय उस विषय पर जो विचार हुआ, जैसाकि मैंने शुरू में कहा है कि यह अल्पसंख्यकों के विरोध में है, उनकी आज जो मनोवृत्ति वोट बैंक के कारण चल रही है, उसी मनोवृत्ति के कारण अल्पसंख्यकों को देश की मुख्य धारा में जोड़ने के स्थान पर वे उनको एक अलग पहचान देकर रखना चाहते हैं। यह केवल मात्र राजनीतिक कारणों से है। केवलमात्र राजनीतिक कारणों से, उस समय के जो हमारे पुरोधा थे, उन्होंने इससे उलटमात्र विचार किया था और जब संविधान सभा में इस समिति की रिपोर्ट रखी गई तो उस समय सरकार पटेल जी ने कहा था कि–

In the long run, it would be in the interest of all to forget that there is anything like a majority or a minority in this country. At that, in India there is only one community.

लेकिन आजादी के इतने सालों बाद, जिसमें अधिकांश समय आज के ही सरकार के जो नेता हैं, उन्होंने शासन व्यवस्था चलाई है और आज 57 वर्षों के बाद भी इस बिल को लाकर वे दुनियां को यह संदेश देने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने की सहमति नहीं दी जा रही है, उनकी एफिलिएशन किसी विश्व-विद्यालय से नहीं हो रही है। इस प्रकार के प्रोवीजन इस विधेयक में लाने के प्रयास किये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस बिल को लाने की आज आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इस प्रकार के प्रोविजन करने के लिए भारत में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का गठन हुआ है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का मेन्डेट इस विधेयक से अलग नहीं है। ...(समय की घंटी)... यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का मेन्डेट है–

The UGC has the unique distinction of being the only grant-giving agency in the country which has been vested with two responsibilities that of providing funds and that of coordination, determination and maintenance of students in institutions of higher education.

इस विधेयक को लाकर के इस यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के मेन्डेट को नेगेट किया जा रहा है। जो आज यहां पर विधेयक माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसकी धारा-13 में यह वर्णित है कि इस नेशनल आयोग को सरकार की ओर से ग्रांट दी जाएगी और वह इस प्रकार के कॉलेजेज़ को ग्रांट देंगे, जबकि पहले से संविधान में आर्टिकल-387 में भी वर्णित है, क्योंकि उस समय के जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने सोचा था कि जो इस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं, ये कुछ समय के लिए होंगी और उस में एंग्लो इंडियन के लिए ग्रांट देने का प्रोविजन किया गया था इंस्टीट्यूशन के लिए, लेकिन वह ग्रांट भी 10 वर्षों में समाप्त होनी थी। ...(समय की घंटी)...

श्री उपसभापति: प्लीज कांक्लूड।

श्री सुरेश भारद्वाज: बस, दो मिनट। हम बहुत कम बोलते हैं, सबसे पिछली बैंच में बैठते हैं, माननीय उपसभापति जी, इसीलिए थोड़ा समय और दे दीजिए।

श्री उपसभापति: समय का अभाव है, हम कुछ नहीं कर सकते।

श्री सुरेश भारद्वाज: इसलिए धारा-337 में जो एक व्यवस्था की गई थी, उसके भी विरोध में जो प्रावधान यहां पर किया गया है, इस नेशनल कमीशन के द्वारा, वह उसके भी खिलाफ जाता है। माननीय उपसभापति जी, हिन्दुस्तान 1947 से पूर्व किसी अल्पसंख्यकवाद की मनोवृत्ति से उपजे हुए द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत की मनोवृत्ति के कारण, आज तक भी उस विभिषिका में जी रहा है। आज भी हिन्दुस्तान इसी मॉयनिरिटिज्म और इसी मैजॉरिटिज्म के कारण वह दो राष्ट्रों में बंटा हुआ है। आज दोनों राष्ट्र अपने विकास के काम को छोड़ करके एक दूसरे से युद्ध करने के लिए बड़े-बड़े एम्युनिशन और फैक्ट्रीज और उसी प्रकार की न्यूक्लियर पॉवर बनती जा रही है। लेकिन आज भी

4.00 P M

57 वर्षों के बाद भी हम उसी मनोवृत्ति को देश में जिन्दा रखने का प्रयत्न करते हैं। मैं इस बिल का समर्थन कर सकता था, अगर माननीय मंत्री जी ने इस में प्रोविजन किया होता कि हिन्दुस्तान में जो यहां पर मुसलमान रहते हैं, जो यहां पर इसाई रहते हैं या जो अल्पसंख्यक रहते हैं, उनकी जो महिलाएं हैं, उनके लिए ठीक प्रकार से शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा। अगर यह इस प्रकार का प्रावधान किसी विधयेक में करते कि इन कम्युनिटीज से सम्बन्ध रखने वाले नौजवानों को हम आई॰टी॰आई॰ में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में इस प्रकार से व्यवस्था करेंगे ताकि इनको सही शिक्षा मिल सके और वे देश में डाक्टर बन सकें, देश में चिकित्सक बन सकें। यहां पर मदरसों की बात हुई, मदरसों से हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन केवलमात्र इनसे एक प्रकार की रिलिजियस एजुकेशन ही दी जाती है। उन मदरसों में पड़ने वाला व्यक्ति न डाक्टर बन सकता है, न चिकित्सक बन सकता है, न इंजीनियर बन सकता है, न वैज्ञानिक बन सकता है। इसलिए इसमें इस प्रकार का प्रावधान किया जाना चाहिये था, इस प्रकार की बात माननीय मंत्री जी करते, ताकि जिनके लिये यह विधेयक यहां पर आया है, उनको भी संदेश दे पाते कि हम आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। यह अल्पसंख्यकों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। इस कानून में एक और प्रोवीजन है।

श्री उपसभापति: आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री सुरेश भारद्वाज: एक चेयरमैन होगा माइनारिटीज़ से और दो मेम्बर्स होंगे। (समय की घंटी) जैसा कि मुझसे पूर्व यहां पर एक माननीय सदस्य ने कहा है.....।

श्री उपसभापति: आप कन्क्लूड कीजिये।

श्री सुरेश भारद्वाज: सर, मैं दो मिनट में कन्क्लूड कर रहा हूं।

श्री उपसभापति: नहीं, आप दो मिनट, दो मिनट कह रहे हैं।

श्री सुरेश भारद्वाज: सर, मैं एक मिनट में कन्क्लूड करं दूंगा। सर, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। जिस प्रकार से एक प्रोविजन किया गया है कि एक चेयरमैन और दो मेम्बर्स होंगे, जब आपने माइनारिटीज़ की छह कम्युनिटीज संविधान में एक्सेप्ट कर रखी हैं, तो मेरा एक निवेदन है कि माननीय मंत्री जी, उन सभी छह कम्युनिटीज़ के एक-एक मेम्बर की इसमें व्यवस्था करते। लेकिन माननीय मंत्री जी ने केवल एक कांसेंसस बना दी, इसके बारे में इन्होंने स्वयं कहा है कि हिन्दुस्तान की सभी पार्टीज बुलाई, बीजेपी को छोड़कर के और बीजेपी जो छह वर्षों तक यहां राज करती रही है, शासन व्यवस्था चलाती रही है, देश की एक सबसे बड़ी अपोजीशन पार्टी है। साथ ही साथ अल्पसंख्यकों के मसीहा मुलायम सिंह जी हैं, उनको भी इन्होंने उस मीटिंग में नहीं बुलाया। क्योंकि ये स्वयं अपनी पार्टी के अंदर ...(समय की घंटी)... देश में अल्पसंख्यकवाद के आधार पर नेतृत्व ग्रहण करना

चाहते हैं। ...(व्यवधान)... कृपया इनकी बात को ध्यान में रखते हुये, यह बिल लाया गया है, इसलिए माननीय उपसभापति महोदय, मैं इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Sanjay Raut. You have three minutes. There are six speakers and we have to conclude this debate 4.20 or 4.25 p.m. So, only three minutes for each speaker.

श्री संजय राजाराम राउत (महाराष्ट्र): सर, मैं आपका आभारी हूं। The National Commission for Minority Educational Institutions Bill, 2004 एक नया कानून बन रहा है। मैं इस बिल का समर्थन तो नहीं करूंगा लेकिन ऑनरेबल मैंबर श्री लालजन बाशा, श्री सिद्धिकी और माननीय सदस्य जनरल चौधरी ने जो बात कही है, वह समर्थनीय है। बहुत सी ऐसी बातें उन्होंने कही हैं जिनका विचार सब पार्टियों को, सरकार को करना चाहिए। इस बिल को जो हम समर्थन नहीं दे रहे हैं, उसके बहुत से कारण है लेकिन वक्त नहीं है। आपने कहा है कि वक्त नहीं है। ठीक है। माननीय सदस्य, श्री आपटे जी ने कहा था कि यह जो बिल है, इसमें माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन की चिंता नहीं है। This is the matter of institutions' vested interests. शिक्षा का बाज़ार हो गया है, उसका एक भाग है। सर, इस बाज़ार में माइनॉरिटी के नाम पर एक नयी दुकान खोल दी गयी है, ऐसा मैं मानता हूं। माननीय सोज साहब बैठे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया। मैं उसको प्रवचन नहीं कहूंगा। कानून के बड़े जानकार हैं, कानून की किताब लेकर बैठते हैं, अच्छी-अच्छी क्लॉज़िज देते हैं लेकिन क्या देश सचमुच आज कानून से चलता है? अगर देश कानून से चलता तो इस देश में कॉमन सिविल कोड आ जाता। कॉमन सिविल कोड आ जाता तो परिवार नियोजन की बात होती। परिवार नियोजन की बात होती तो जनसंख्या नियंत्रित होती। जनसंख्या नियंत्रित होती तो यह मैजोरिटी, माइनॉरिटी की बात नहीं आती और सबको अच्छी शिक्षा मिल जाती, सबको अच्छी तालीम मिल जाती लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आज भी शिक्षा के नाम पर, राजनीति के नाम पर धर्म की बात हो रही है,माइनॉरिटी की बात हो रही है। पचास साल पहले इस देश में जिस माइनॉरिटी की संख्या दो करोड़ थी, अब ऑफिशियली 15 करोड़ हो गयी है, अनऑफिशियली बीस करोड़ हो गयी है फिर भी हम माइनॉरिटीज़ हैं, ऐसा बोलते हैं। यह तो माइनॉरिटी की बात नहीं है। अगर जनसंख्या कम होती तो सबको शिक्षा मिल जाती, यह सब धर्म की बात है, यह नेशनल विचार है, राष्ट्रीय विचार है। सर, मेरा यह कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो माइनॉरिटी और मैजोरिटी शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हम राजनीति में पहले धर्म लाए हैं और धर्म ने इस देश की एकता और अखंडता को ठेस पहुंचाई है। उससे हम जो भुगत रहे हैं, हम सब उसके साक्षी हैं, विटनेस हैं। अब यह बात शिक्षा में आने लगी है, यह बहुत गलत है। सर, मेरा यह मानना हैं कि इस देश में कोई मायनोरिटी नहीं हैं, कोई मैजोरिटी नहीं है। सभी देश के नागरिक है। और सभी के लिए समान न्याय है, चाहे वे किसी भी धर्म के लोग हों। कानून का अधिकार और

शिक्षा का अधिकार सब के लिए समान होना चाहिए। धर्म के आधार पर किसी भी नीति को नहीं चलना चाहिए और शिक्षा तो कभी नहीं चलनी चाहिए। जब भी अल्पसंख्यकों की बात आती है तो उसका संबंध हमारे मुसलमान भाइयों से जोड़ा जाता है, यह गलत है। अगर इस देश में मायनोरिटी की बात कही जाती है तो ऐसे बहुत से धर्म हैं जिनकी जनसंख्या मुसलमानों से बहुत कम है, जैसे जैन धर्म है, पारसी है, क्रिश्चियन है, सिख है, लेकिन उनको कभी इन बातों की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए वे न तो धर्म के नाम पर जीना चाहते हैं और न कभी राजनीतिक सौदेबाजी करना चाहते हैं। वे अपनी आबादी नियंत्रित रखने पर विश्वास रखते हैं। अगर जनसंख्या कम होगी, घर में दो या तीन बच्चे होंगे तो परिवार सुखी रहेगा और अच्छी शिक्षा मिलेगी। वे इस देश के अच्छे नागरिक बनेंगे और उनका मान-सम्मान बढ़ेगा। मुझे लगता है कि यह जो धर्म के नाम पर एक दीवार खड़ी हो रही है, यह खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी। मायनोरिटी की बात, धर्म पर नहीं होती है, जैसे पहले रिलिजन पर होती है, बाद में लिंग्विस्टिक होती है। सोज साहब ने, एक बात कही थी, इस बिल में कहा है, This Bill extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir. मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जम्मू-कश्मीर इस देश में नहीं है? क्या वहां पर कोई मायनोरिटी नहीं है। जम्मू-कश्मीर में जो हिन्दू पंडित भाई हैं, वे मायनोरिटी में हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उनकी तो इस बिल में चर्चा नहीं है, कोई भी उनके ऊपर बात नहीं करना चाहते हैं। (समय की घंटी) ऐसा क्यों है? मैं माननीय मंत्री जी यह भी पूछना चाहूंगा कि जम्मू-कश्मीर में जो हमारे हिन्दू पंडित भाई हैं, वे भी देश के नागरिक हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? ठीक है, आपने राज्य को एक अलग स्टेटस दिया है, लेकिन फिर भी उनके लिए अलग से सोचना चाहिए। दूसरी बात लिंग्विस्टिक मायनोरिटी की है। मैं महाराष्ट्र से आया हूं इसलिए मैं वहां की भी थोड़ी बात जरूर करूंगा। सर, मुम्बई शहर शिक्षा का एक उच्च शहर माना जाता है। यह महाराष्ट्र की राजधानी है, लेकिन आज वहां मराठी भाषी अल्पसंख्यक बन गए हैं। वहां पर केवल 22 परसेंट ही मराठी भाषी रहते हैं। वहां पर भिन्न-भिन्न प्रांतों से, हर धर्म और हर जाति के लोग आते हैं और पूरे देश से आते हैं, हमें इसका कोई दुख नहीं है, ठीक है, वहां पर आएं। लेकिन मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि अगर यह सिलसिला इसी तरह कायम रहा तो क्या आप मुम्बई के मराठी भाषियों को भी मायनोरिटी एजुकेशनल इंस्टिट्यूट का दर्जा देंगे? क्योंकि आज मुम्बई में ऐसी बात हो रही है और वहां पर 125 कॉलेज हैं। ...(समय की घंटी)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

श्री संजय राजाराम राउत: जिनमें से 25 प्रतिशत कॉलेज ने जाति, धर्म के आधार पर मायनोरिटी एजुकेशनल इंस्टिट्यूट का दर्जा हासिल कर लिया है। उनमें से कुछ कॉलेज हमारे गुजराती भाइयों के हैं, कुछ सिन्धी भाइयों के हैं, कुछ दक्षिण भाइयों के हैं और कुछ मुसलमान भाइयों के हैं। उन कालेजों में जाति और धर्म के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। अगर इसी तरह

से होता रहा और जाति और धर्म के आधार पर शिक्षा का व्यापार चलता रहा तो वह शिक्षा नहीं रहेगी। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में दूसरी बात यह रखना चाहता हूं कि ये जो मायनोरिटी एजुकेशनल इंस्टिट्यूट हैं, उनमें नियमों का पालन नहीं होता है।

उपसभापति, जी, ऐसा नियम है.कि माइनोरिटी एजुकेशनल इंस्टिट्यूट (व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आपके तीन मिनट से पांच मिनट हो गए हैं।

श्री संजय राजाराम राउत: सर, अभी पांच मिनट नहीं हुए हैं, एक मिनट बाकी है।

श्री उपसभापति: यहां मेरे पास घड़ी है।

श्री संजय राजाराम राउत: मेरे सामने भी घड़ी है सर।

श्री उपसभापति: अच्छा खत्म कीजिए।

श्री संजय राजाराम राउत: "Minority Educational Institutes should be based on their religion, caste and culture. They should keep their religion, culture, language and values in the educational system. The Government has made it mandatory for these institutes, but this is not happening in various minority institutes. There must be compulsion of education in their own language."

लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि

"There is no reservation policy for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Government has no control on their accountability."

"And there is a rule for getting more than 50 per cent students of same religion in a minority institute. But this is also not implemented."

वहां पर दूसरे रिलीजन्स के स्टूडेन्ट्स को जो प्रवेश दिया जाता है, उसमें पैसे और डोनेशन का व्यापार होता है।

श्री उपसभापति: आप कन्क्लुड कीजिए।

श्री संजय राजाराम राउत: उपसभापति जी, सिर्फ रिलीजन्स और धर्म के आधार पर संस्था बनाने से इस देश में परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन तब आएगा जब उन्हें देश की मुख्य धारा में लाकर आप शुरू से अच्छी तालीम देंगे और यह चिंता सरकार की है, हम सबकी है। अगर जीवन के ऐसे मोड़ पर आप नौजवानों को खड़ा करते रहे और अगर आप उनके मन में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात जोड़ देते हैं तो मुझे लगता है कि यह अच्छी शिक्षा नहीं बन सकती, हम

अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बिल के बारे में एक बार फिर से सोचे। धन्यवाद।

श्री तारिक अनवर: उपसभापति जी, मैं नेशनल कमीशन फोर माइनोरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं इस बिल का समर्थन इसलिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूं, बल्कि एक सच्चा राष्ट्रवादी होने की हैसियत से मैं यह महसूस करता हूं कि यह बिल जो लाया गया है, यह समय के अनुकुल है और इसकी आवश्यकता थी। अभी हमारे मित्र संजय राउत जी ने कहा, अक्सर यह सुनने में आता है कि इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय को यह सलाह दी जाती हैं कि वह देश की मुख्यधारा में आए। यह देश की मुख्यधारा कहां बहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक देश की मुख्यधारा का मैं मतलब समझता हूं, वह यह है कि इस देश में रहने वाले जो तमाम लोग हैं, चाहे अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, सभी को बराबरी का अवसर मिले, सभी को आगे बढ़ने का मौका मिले, सभी को शिक्षा मिले और वे स्वयं को यह महसूस करें कि वे इस देश के अच्छे नागरिक हैं और इस देश में उनका भी एक हिस्सा है, उनकी भी एक जिम्मेदारी है, उनका भी एक दायित्व है। जिन लोगों ने हमारे संविधान की रचना की, वे इस बात को अच्छी तरह से समझते थे, वे दूरदर्शी लोग थे और इसलिए हमारे संविधान में इस बात का प्रावधान रखा गया कि जो अल्संख्यक समुदाय के लोग हैं, उनकी शिक्षा की, उनके संवैधानिक अधिकार की रक्षा हो सके। इसलिए आर्टिकल 30 के अंतर्गत, जो अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा का प्रावधान है, उस पर हमारे संविधान में पूरी तरह से जोर दिया है, उस पर रोशनी डाली है। हमारे संविधान की रचना करने वालों ने आरक्षण का प्रावधान रखा है। आखिर क्यों रखा है? यह इसलिए रखा है कि अगर किसी कारण से समाज का कोई वर्ग, पिछड़ा रह गया है, पिछड़ गया है, तो उसे देश की मुख्यधारा से जोड़ा जाए, उनके लिए विशेष प्रावधान किया जाए। इसीलिए हमारे संविधान बनाने वालों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए आरक्षण का प्रावधान रखा और हमारे समाज के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, उनको आरक्षण दिया गया, हर क्षेत्र में आरक्षण दिया गया।

श्री सभापति पीठासीन हुए

सभापति महोदय, अभी हमारे माननीय सांसद जनरल चौधरी साहब ने मदरसों के बारे में कुछ बातें उठाईं। अक्सर यह कहा जाता है कि मदरसों का modernisation होना चाहिए लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि लगातार यह असत्य propaganda हमेशा होता रहा कि मदरसों में जो पढ़ाई होती है, वहां fundamentalists पैदा होते हैं, वहां आतंकवादी पैदा होते है, मदरसे ISI के अड्डे बन चुके हैं। इस तरह की बातें लगातार कही गईं लेकिन जब इसकी जांच हुई तो यह स्पष्ट हो गया कि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है लेकिन आज भी यह बात अक्सर दोहराई जाती है। हम भी इस

पक्ष में हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को माडर्न शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन जब उनकों गांव के स्तर पर या जहां वे रहते हैं, यह शिक्षा प्राप्त नहीं होती है, उसका प्रावधान वहां नहीं होता है, तब वे मजबूरी की हालत में, मदरसों में अपने बच्चों को भेजते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं हमारे बच्चे अशिक्षित न रह जाएं। इसलिए जो भी तालीम वहां मिल सकती है, उसके लिए वे कोशिश करते हैं। अगर धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए वे अपने बच्चों को मदरसों में भेजते हैं। लगातार इस बात का प्रचार किया जाता है और इस बात को कहा गया कि मदरसों के अंदर जो पढ़ाई होती है, वह आतंकवादी बनाने की पढ़ाई होती है।

सभापति महोदय, हम अपने परिवार में भी देखते हैं कि जो बच्चा बीमार होता है, उसकी तरफ मां-बाप का ध्यान ज्यादा होता है। ठीक इसी तरह से जो देश के अल्पसंख्यक समुदाय हैं या दलित हैं या पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वे डरे हुए हैं, उनको समाज में उचित स्थान देने की आवश्यकता है और उनको उठाने के लिए सबसे जरूरी है कि उनको तालीम दी जाए, उनको शिक्षा दी जाए क्योंकि किसी भी समुदाय को या किसी भी व्यक्ति को यदि हम ऊपर उठाना चाहते हैं तो उसकी जो बुनियाद है, उसकी जो आत्मा है, वह शिक्षा में है। जब तक वह शिक्षित नहीं होगा, तब तक वह किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने में सफल नहीं हो सकता है।

सभापति महोदय, वहां पर वोट बैंक की बात भी कही गई। वोट बैंक का जहां तक सवाल है, जैसा कहा गया कि इस देश में 15 प्रतिशत या 16 प्रतिशत अल्पसंख्यक रहते हैं लेकिन कोई भी राजनीतिक दल, अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर अपना वोट बैंक नहीं बना सकता है। अगर वोट बैंक बनाना होगा, तो बहुमत का वोट बैंक बनाना होगा, क्योंकि जो हमारी 85 प्रतिशत आबादी है, उसकी बात कहकर हम वोट बैंक बना सकते हैं। लोकतंत्र में बहुमत ही निर्णय करता है, बहुमत ही निर्णायक होता है। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यकों को खुश करके किसी भी राजनीतिक दल का बहुमत में आना संभव नहीं है। इसलिए ऐसी बात कहकर अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति जो गलतफहमी पैदा की जाती है, उनके खिलाफ घृणा पैदा करने की कोशिश की जाती है, यह नहीं होनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं बहन सुषमा जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सेलेक्ट कमेटी की घोषणा की और उसमें हमारा नाम दिया, इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं। इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहना चाहूंगा कि यह जो बिल लाया गया है, इस पर काफी विचार-विमर्श हो चुका है। राजनीतिक दलों के अलावा शिक्षा जगत के जो eminent लोग हैं, जो

पढ़े-लिखे लोग हैं, शिक्षा जगत में जिनका एक मुकाम है, ऐसे लोगों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद हमारे मंत्री महोदय ने और हमारी UPA सरकार ने यह बिल यहां पेश किया है। इसलिए अब मैं नहीं समझता हूं कि अब वह समय रह गया है, क्योंकि लोक सभा से भी यह बिल पास हो चुका है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि अब इसे सेलेक्ट कमेटी को दिया जाए। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस बिल के बनने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर एक विश्वास पैदा होगा, हमारे देश के संविधान के प्रति भी और इस सरकार के प्रति भी, कि उनको देश की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार की ओर से प्रभावशाली ढंग से कदम उठाया गया है। धन्यवाद।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the National Commission for Minority Educational Institutions Bill, 2004. The conribution of minorities in India to the field of education has to be appreciated.

MR. CHAIRMAN: You have to conclude by 4.30 p.m.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, I will try. So, it is a social obligation on the part of the majority as well as all the people of this country to protect and safeguard the interests of the minorities in our country. I am also inclined to support this Bill because the spirit of this legislation is to protect the interests of minority educational institutions. But I have so many doubts in my mind. Therefore, I would like to seek some clarifications from the hon. Minister so far as this Bill is concerned. This legislation pertaining to the welfare and protection of the interests of minorities should be for the benefit and for the progress of that particular community. I would like to know whether this Ordinance or this legislation would serve the prupose. As far as minorities are concerned or the minority educational institutions are concerned, the main problem is not the problem of affiliation. Maybe, it is correct, affiliation is also a problem. So far as recognisation of courses is concerned—there are so many councils or boards like the All India Council of Technical Education, AICTE, Medical Council, Teachers Council, CBSE and so many educational boards and councils—the problem is, it is very difficult to get a course recognised in a particular council or a particular board and there is nothing about it in the

Bill. In the Bill, only the five Central Universities have been scheduled and any college of minority or any institution of minority can have affiliation to that particular University. That is the only thing which is enunciated in this Bill. This is why I am saying, if it is for the betterment of the minority community as a whole, whether it is linguistic or religious minority, this Bill will not serve the purpose. That is my humble submission.

I would like to know from the hon. Minister whether a serious thought was given to the Bill while drifting it. I think no serious thought was given to this Bill. They have not applied their mind properly while drafting this Bill. Sir, I am not supporting the manner in which this Bill was introduced. So far as the Ordinance is concerned—it may be part of the discussion which was held on 3rd July— if this House was to meet in December for the Winter Session, the necessity of constituting a National Commission for Minority Educational Institutions through an Ordinance can never be justified.

Now I come to clause 2 (f) of the Bill. I need not explain it because it has already been explained by Shri Fali S. Nariman. It is regarding definition of 'minority'. Even in the TMAPAI's case, eleven points were raised before the eleven-Judges Bench of the Supreme Court. One of the main issues was as to who is minority. Even the Supreme Court has not properly discussed and defined it. But in this Bill, we are giving a clear definition and clarification. Clause 2 (f) of this Bill says, "'minority' means a community notified as such by the Central Government." What is the criteria for notifying a particular community that this is minority community? The hon. Minister has to explain the criteria or the norms that are to be followed while considering a particular community as a minority community. I come to Clause 2(g); what is meant by a minority educational institution? Suppose an individual established and maintains a particular institution; he belongs to a minority community; it is a minority educational institution. The question is whether that institution is benefiting that particular community. I belong to a particular community and I am very rich; I have all the facilities and the infrastructure to start an educational institution. In such an institution, all the admissions may be going to people coming from elite

sections, after payment of capitation fee. So, such an institution will have nothing to do with minority education. No admission is given to minority communities. Hundred per cent admissions are given to those who pay capitation fee. The question is, whether according to this Bill that is a minority education institution. That institution will get benefits under this law. So, my submission is that the minorities should be protected; their rights should be protected; their education should be promoted; if they have to be promoted educationally, we should evolve a mechanism to see that that particular institution is benefiting the minority community in education. Otherwise, it will only help certain individuals who have influence in the society, or, in a particular community. That is my second submission.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I will make the rest of my speech after PM's statement.

MR. CHAIRMAN: No, no. You finish it.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Then, I will take two or three minutes more.

MR. CHAIRMAN: You can have the advantage of two more minutes.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Thank you, Sir. I come to Clause 4; the chairman and members of the Commission will be from the minority community. I accept it. But, here, as far as other national commissions are concerned, they are all recommendatory in nature. This Commission will have adjudicating powers which is given in Clause 12. If any dispute arises between a university and a particular educational institution, the decision of the Commission shall be final. That means it is an adjudicating authority to resolve the disputes. Therefore, the question arises whether it has secular credentials, whether it meets the requirements of the salient features of our Constitution, the secular features of our Constitution, the basic features of the Constitution. This may be looked into by the Government.

I come to clause 4(2). The qualification is that it should be a person of eminence, ability and integrity. Who will determine it, and how will it be determined? I come to Clause 10, on the role of the State Government, which has been amended by the Lok Sbaha. We have

strong reservations in respect of this because Education is in the Concurrent List and if Education is in the Concurrent List, and if a particular educational institution in the southern or northern part of the country has affiliation with a North-Eastern university, what is the role of the State? In my State, majority of the higher education institutions are run well by minorities, especially by the Christian community. The standards of institutions run by Muslims are also going up. They are also starting so many institutions. So, if all these institutions are being affiliated else where then the State has no role in the field of higher education. Also, a new amendment has been incorporated now. I welcome the amendment. But I would like to know this from the hon. Minister. If, as per Clause 10, sub-clause (2), when the State Government is being consulted, it says, "No. Affiliation shall not be given to that particular institution", what would be the position and what would be the role of the State Government? Also, there are private colleges or minority educational institutions which are being aided by the State Government. So, the State Government should have some say. Under the original Act, there was no say. We had proposed some amendments and those amendments have been carried out by the Government; I congratulate the Government for that. But the issue still remains that if a dispute arises between a State Government and the affiliating university, then, who will resolve that dispute. Does this Commission has the power? As per the present Act, and even in the amended Act, there is no such power for the resolution of the dispute between the two.

Sir, these are the clarifications that I seek from the hon. Minister. I would take this opportunity to say that we, the people of India, whether we are a majority or a minority, have this social obligation on our part to protect and preserve the interests of the minorities in this country. With these words, I conclude.

MR. CHAIRMAN: The debate will continue after the Prime Minister's Statement.